आज का विचार
अपनापन किसी वैद्य से कम नहीं होता है। हर तकलीफ में ताकत की दवा देता है।

दैनिक सिटी दर्पण
आईना सच का

5

सिटी दर्पण-राष्ट्रीय दैनिक हिंदी समाचार पत्र की अधिकारिक वेबसाइट पर जाने के लिए स्कैन करें।

पंचकूला । रविवार, 26 अप्रैल, 2026 | वर्ष 1, अंक 253, मूल्यः 3 रुपए, पृष्ठ 8 | RNI Regn No.: HRHIN/25/A2164 Established 2025 | www.citydarpan.com

कैंसर बचाव के लिए जन जागरूकता अभियान चलाएं: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन

एजेंसी (हि.स.)
जयपुर

उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि कैंसर से लड़ने और विजय प्राप्त करने के लिए मस्तिष्क से मजबूत रहना जरूरी है। उन्होंने कैंसर से बचाव के लिए विशेष रूप से युवाओं से नशीले पदार्थों और तंबाकू आदि से दूर रहने का आह्वान किया। उन्होंने कैंसर से बचाव के लिए व्यापक स्तर पर जन जागरूकता अभियान चलाए जाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कैंसर उपचार के अंतर्गत कीमोथेरेपी जैसी कठिन उपचार विधि के स्थान पर नवीनतम चिकित्सा अनुसंधानों में टैबलेट के जरिए उपचार की पहल उत्साहजनक है।

उपराष्ट्रपति शनिवार को महाराणा प्रताप ऑडिटोरियम में कैंसर सरवाइवर्स डे के अवसर पर कैंसर सोसाइटी द्वारा आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शुद्ध पानी की उपलब्धता सबके लिए आवश्यक है। प्रतिवर्ष कैंसर के रोगी बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत कैंसर के उपचार के तहत कैंसर रोगियों को प्रति वर्ष पांच लाख तक का निःशुल्क इलाज मिलता है। इसमें सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी जैसे प्रमुख कैंसर उपचार शामिल हैं। यह योजना देशभर के सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में ब्रेस्ट, फेफड़े और मुंह के कैंसर सहित अन्य प्रकारों के इलाज को कवर करती है। गरीब मरीजों के इलाज के लिए एकमुश्त 15 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाती है।

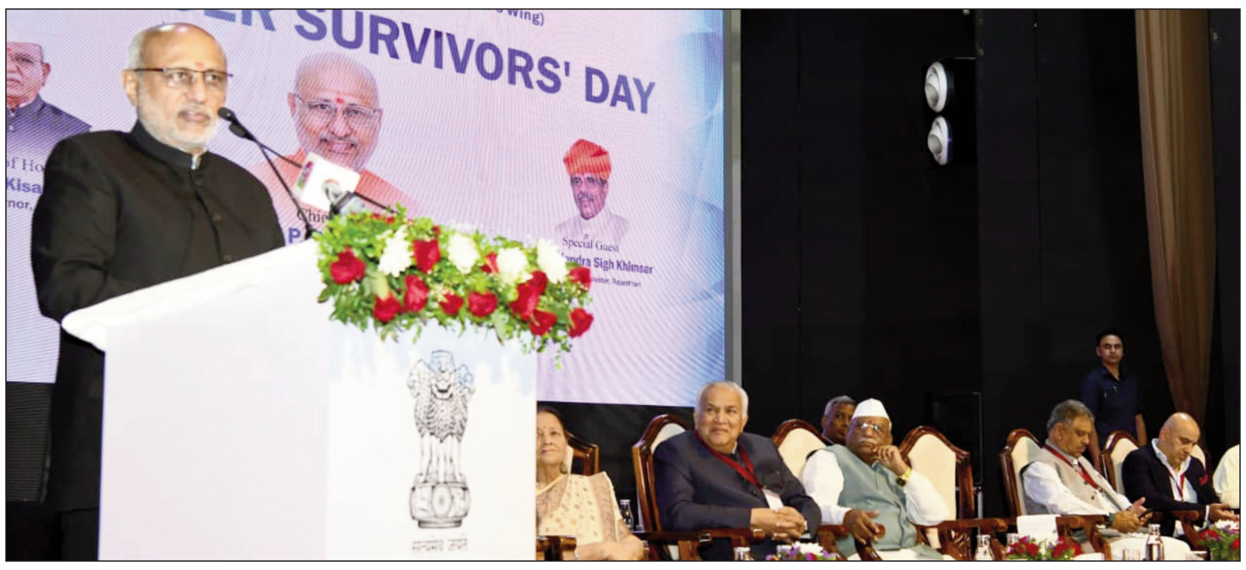

यह बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत भी ग्रामीण क्षेत्रों में 75 प्रतिशत राशि का व्यय कैंसर बचाव के लिए किया जा रहा है।

उपराष्ट्रपति ने कहा कि सर्वाइकल कैंसर इस समय देश में द्वितीय सबसे अधिक होने वाला कैंसर है। इसके बचाव के लिए वेक्सिनेशन के साथ उपचार के लिए कारगर प्रयासों की पहल केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा की गई है। राजस्थान कैंसर से लड़कर उससे मुक्त होने वालों में अग्रणी है। जो लोग कैंसर से लड़कर आज यहां उपस्थित हैं, वे प्रेरणा देने वाले हैं।

राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि जिस तरह से टीबी मुक्त अभियान चलाकर उससे मुक्ति के प्रभावी प्रयास हुए हैं, उसी तरह कैंसर मुक्त राजस्थान अभियान चलाकर प्रभावी प्रयास किए जाने की जरूरत है। बागड़े ने कहा कि तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट वालों को कैंसर अधिक होता है। इसलिए इनसे बचना चाहिए।

उन्होंने कहा कि प्राकृतिक वातावरण जीवन को ऊर्जा देता है। जल में घुलने वाले केमिकल, खेती में रसायनिक उर्वरकों के उत्पादों से कैंसर होता है। इसलिए आमजन को शुद्ध पानी, केमिकल मुक्त उत्पाद कैसे मिले, इस पर अधिकाधिक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने कहा कि कैंसर जागरूकता के लिए प्रभावी प्रयास जरूरी है। उन्होंने राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में विस्तार से अवगत कराया।

इससे पहले उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन, राज्यपाल बागडे तथा चिकित्सा मंत्री खींवसर ने कैंसर सर्वाइवर से संबंधित फिल्म का भी लोकार्पण किया। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद डॉ. राधामोहन अग्रवाल एवं अन्य गणमान्यजन उपस्थित रहे।

पूर्व जज बावड़ियों के समान, उनके ज्ञान और अनुभव का लें लाभ: सीजेआई सूर्यकांत

सीजेआई ने 'द बेंच बियोंड रिटायरमेंट' विषय पर आयोजित सम्मेलन को संबोधित किया

एजेंसी (हि.स.)
जयपुर

उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत ने कहा कि प्रदेश में बारिश के पानी को बावड़ी में सहेजा जाता है। हमारे पूर्व जज भी इन्हीं बावड़ियों के समान हैं, जिनसे हम परेशानी में मदद ले सकते हैं। ऐसे में इन्हें भी सहेजने की जरूरत है। ये लोग ही हमें उचित और अनुचित का फर्क बताएंगे।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत जयपुर में शनिवार को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 'द बेंच बियोंड रिटायरमेंट' विषय पर आयोजित सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी भी उपस्थित थीं।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि आज देश की जनता का न्यायपालिका पर गहरा विश्वास है। हमारे एक-एक शब्द को लोग पूजनीय मानते हैं। ऐसे में न्यायपालिका और उससे जुड़ी संस्थाओं को जागरूक होने की जरूरत है। हमारा दायित्व है कि हम लोगों का न्यायपालिका के प्रति विश्वास बनाए रखे। उन्होंने कहा कि हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि जज हमेशा जज रहता है। लोक अदालत जैसे माध्यमों से लाखों लोगों को न्याय मिलता है। उन्होंने कहा कि पूर्व जज आमजन को न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। वे स्कूल, कॉलेजों और ग्राम पंचायतों तक जाकर आमजन को न्यायिक प्रक्रिया और उनके अधिकारों के बारे में जागरूक कर सकते हैं। इस दौरान उन्होंने उच्च न्यायालय में यूनिफॉर्म रजिस्ट्रेशन नंबर सिस्टम का बटन दबाकर शुरूआत की।

सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि यह वह पीढ़ी है, जिसने देश में बड़े बदलाव देखे हैं। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका संविधान और कानून की रक्षक है। वह हर नागरिक को समान अधिकार देती है। जिस व्यक्ति को न्याय की जरूरत है, उसके लिए न्यायाधीश एक उम्मीद है। न्यायाधीश का एक बयान समाज के जीवन का आधार बनता है। आप समाज को जो दिशा देते हैं, उसकी समाज से मान्यता मिलती है।

मुख्यमंत्री ने पूर्व जजों को कहा कि वे रिटायर होने के बाद भी समाज को नई दिशा दे रहे हैं। नए न्यायाधीश आते हैं और पूर्व जजों से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि आमजन सीधे अदालत जाने से पहले लोक अदालत का दरवाजा जरूर खटखटाएं, इसमें बहुत काम होते हैं और लोगों को राहत मिलती है।

इस मौके पर उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसपी शर्मा ने कहा कि अदालतों में मुकदमों की भरमार होने से लोगों को न्याय मिलने में देरी हो रही है। डिजिटल इन्फास्ट्रक्चर बढ़ने से न्यायिक प्रक्रिया में तकनीक का उपयोग बढ़ा है। उन्होंने कहा कि एक जज की यात्रा रिटायर होने के बाद समाप्त नहीं होती है। पूर्व जज न्याय दिलाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं।

कॉन्फ्रेंस के बाद राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को दिए गए मल्टी यूटिलिटी वाहनों को उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश और मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये वाहन प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में जाकर लोगों को उनके अधिकारों और विधिक सेवा प्राधिकरण की योजनाओं के बारे में जागरूक करेंगे।

राजनीति के महत्वपूर्ण स्तंभ थे हेमवती नंदन बहुगुणा: योगी

एजेंसी (हि.स.)
लखनऊ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व मुख्यमंत्री स्व. हेमवती नंदन बहुगुणा की जयंती पर उन्हें नमन किया। शनिवार को योजना भवन स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बहुगुणा जी भारत की राजनीति के महत्वपूर्ण स्तंभ थे। उनका जन्म तत्कालीन उत्तर प्रदेश (वर्तमान उत्तराखंड) के पौढ़ी गढ़वाल जनपद में 25 अप्रैल 1919 को हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा गांव में अर्जित करने के उपरांत उच्च शिक्षा के लिए वह प्रयागराज आ गए थे। 1942 से 1946 तक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आह्वान पर भारत छोड़ो आंदोलन में बहुगुणा जी की सक्रिय सहभागिता रही, जिस कारण ब्रिटिश सरकार ने उन्हें जेल में भी डाला था। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि बहुगुणा ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रखर छात्रनेता के रूप में अपनी छाप छोड़ी। वह देश के स्वाधीनता आंदोलन में लगातार सक्रिय रहे। आजादी के बाद 1952 के पहले आम चुनाव में वह पहली बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य बने। उन्हें प्रदेश सरकार के मंत्री के रूप में भी कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ था। उत्तर प्रदेश में विभिन्न विभागों के मंत्री तथा मुख्यमंत्री के रूप में उनकी सेवाएं सराहनीय रहीं। योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर बहुगुणा का अपना दृष्टिकोण था। उसे आज भी प्रभावी रूप से धरातल पर उतरते हम सभी महसूस कर सकते हैं। बहुगुणा जी ने केंद्र सरकार में भी अनेक मंत्रालयों में सेवाएं दीं। लंबे राजनीतिक व सार्वजनिक जीवन में देश के प्रति उनकी सेवा उल्लेखनीय रही हैं, जो वर्तमान पीढ़ी के लिए प्रेरणा है।

कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, महापौर सुषमा खर्कवाल, विधायक नीरज बोरा, अमरेश कुमार, विधान परिषद सदस्य लालजी प्रसाद निर्मल, रामचंद्र प्रधान आदि मौजूद रहे।

गाजीपुर घटना में दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई और घटना की उच्चस्तरीय जांच हो : राहुल गांधी

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक महिला के साथ बलात्कार और हत्या मामले में राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने दोषी पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई, पीड़ित परिवार को सुरक्षा और घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग की।

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हाथरस, कठुआ, उन्नाव और अब गाजीपुर की घटनाओं को एक पैटर्न बताते हुए कहा कि हर बार पीड़िता दलित, पिछड़ी, आदिवासी या गरीब होती है और अपराधियों को संरक्षण मिलता है। उन्होंने मणिपुर की घटना का भी उल्लेख किया।

राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सत्ता हर बार चुप रहती है और जिनसे बोलने की उम्मीद होती है, वे मौन रहते हैं। जिस देश में माता-पिता को अपनी बेटी की एफआईआर लिखवाने के लिए भीख मांगनी पड़े, उस सरकार को सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है।

भगवंत मान ने राष्ट्रपति से मिलने के लिए मांगा समय पार्टी छोड़ने वाले सांसदों की वापसी पर करेंगे चर्चा

एजेंसी (हि.स.)
चंडीगढ़

पंजाब के सात में से छह राज्यसभा सदस्यों के आम आदमी पार्टी (आआपा) छोड़ने के बाद प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है। मुख्यमंत्री भगवंत मान जहां पार्टी छोड़ने वाले राज्यसभा सांसदों के विरूद्ध आक्रामक हो गए हैं वहीं इस पूरे मामले को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से मिलने का समय मांगा है।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चंडीगढ़ में शनिवार को बताया कि वह राष्ट्रपति से पार्टी छोड़ने वाले सांसदों के 'वापस बुलाने' के मुद्दे पर अपना पक्ष रखेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह राज्यसभा सभापति से मिलेंगे, जहां वे पार्टी छोड़ने वाले सांसदों की सदस्यता रद्द करने की मांग करेंगे।

संजय सिंह ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि मैं राज्यसभा के सभापति एवं उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को सभी प्रासंगिक नियमों का हवाला देते हुए पत्र दूंगा, जिसमें इन सातों राज्यसभा सांसदों की सदस्यता समाप्त करने की मांग की जाएगी।

वहीं, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोशल मीडिया एक्स पर पार्टी छोड़ने वाले सांसदों पर तंज कसा। मान ने लिखा कि अदरक, लहसुन, जीरा, मेथी पाउडर, लाल मिर्च, काली मिर्च और धनिया, ये सात चीजें मिलकर सब्जियां स्वादिष्ट बनाती हैं, लेकिन इनकी सब्जी नहीं बन सकती।

आम आदमी पार्टी छोड़ने के बाद राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने शुक्रवार को ही सांसद अशोक मित्तल और संदीप पाठक के साथ भाजपा ज्वाइन कर ली थी। राघव चड्ढा के मुताबिक हरभजन सिंह, विक्रमजीत सिंह साहनी, स्वाति मालीवाल, राजेंदर गुप्ता भी हमारे साथ हैं।

राजा नहीं, किसान का बेटा हूँ, खुद खेती की है: नायब सिंह सैनी

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पश्चिमी बंगाल में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में एक तरफा बीजेपी की सरकार बनेगी। प्रधानमंत्री ने गरीब व जनहितैषी योजनाओं को लागू किया है जिनका लाखों लोगों ने लाभ उठाया है और वे गरीबी रेखा से बाहर हुए हैं।

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी शनिवार को चण्डीगढ में आयोजित प्रेस वार्ता में पूछे गए एक सवाल का जवाब दे रहे थे। एक अन्य सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि वे प्रदेश के राजा नहीं बल्कि एक किसान के बेटे हैं और उन्होंने स्वयं खेती की है। इसलिए किसानों की समस्याओं से भलीभांति परिचित है। उन्होंने कहा कि वे किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए सदैव तत्परता से लगातार कार्य कर रहे हैं। कांग्रेसी नेताओं द्वारा मंडियों के लगातार दौरों के संबंध में पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष ऐसा वातावरण खड़ा करने में लगा है जैसे उनके समय में किसान बहुत खुश थे। वो केवल झूठ की दुकान खोलकर आमजन को गुमराह करने में लगे हैं, लेकिन जनता इन्हें अच्छे से समझती है। कांग्रेसी चुनाव के समय पोर्टल बंद करने की बात करते थे लेकिन जनता ने इन्हीं का पोर्टल बंद कर दिया है। वर्ष 2014 से लगातार डबल इंजन की सरकार विकास कार्यों को तेजी से कर रही है।

एक अन्य प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब में आप पार्टी ने मतदाताओं को बड़े-बड़े वायदे और सब्जबाग दिखाए थे। इनमें किसानों का कर्जा माफ करना, युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाना, पंजाब को नशे से मुक्त करना, महिलाओं को लाभ देने जैसे वायदे शामिल हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब में नशा बढ़ गया है और युवा नशे की गिरफ्त में हैं। उन्होंने कहा कि चुटकलों से जनता का पेट नहीं भरता, इसके लिए जनकल्याण के कार्य करने पड़ते हैं। हरियाणा में किसानों, महिलाओं, युवाओं के लिए अनेक योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। पंजाब में भाजपा की सरकार बनते ही हरियाणा में लागू सभी योजनाएं एवं व्यवस्थाएं हुबहू लागू की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में आयुष्मान चिरायु योजना के तहत अब तक 27 लाख से ज्यादा परिवारों ने ईलाज करवाकर स्वास्थ्य लाभ उठाया है। पंजाब में आप सरकार ने मोहल्ला क्लीनिक बनाए थे, वे अब हल्ला क्लीनिक बन गए हैं। पंजाब की जनता अब इनसे अपना पिण्ड छुड़वाना चाहती है। एक अन्य जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में डी ग्रुप के 18 हजार युवाओं के पदोन्नति के मामले को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसके लिए एक दिन का विधानसभा का सत्र बुलाया गया है। विपक्ष ने देश की आधी आबादी को धोखा दिया है। लोग इसकी निंदा कर रहे हैं। एक अन्य प्रश्न पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में लॉ एण्ड ऑर्डर की स्थिति की सख्ती से मोनिटरिंग की जा रही है। यदि कोई ड्रग व नशा बेचते पाया जाता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है।

नीति आयोग के नवनियुक्त उपाध्यक्ष अशोक लाहिड़ी ने प्रधानमंत्री से की मुलाकात

नई दिल्ली। नीति आयोग के नवनियुक्त उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से शिष्टाचार मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर लाहिड़ी से मुलाकात की तस्वीर साझा कर बधाई देते हुए कहा कि अर्थशास्त्र और सार्वजनिक नीति में उनका व्यापक अनुभव भारत के सुधारों की दिशा और विकसित भारत के लक्ष्य को मजबूत करेगा। उन्होंने विश्वास जताया कि लाहिड़ी के प्रयास देश में नीति-निर्माण को और अधिक गतिशील बनाएंगे। सरकारी अधिसूचना के अनुसार वरिष्ठ अर्थशास्त्री लाहिड़ी को शुक्रवार को नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसके साथ ही आयोग की नई पूर्णकालिक टीम की भी घोषणा की गई है। नई टीम में राजीव गौबा, प्रो. केवी राजू, प्रो. गोबर्धन दास, प्रो. अभय करंदीकर और डॉ. एम. श्रीनिवास को पूर्णकालिक सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री ने सभी नवनियुक्त सदस्यों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नीति आयोग भारत की नीति-निर्माण संरचना का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन चुका है, जो सहकारी संघवाद, सुधारों और ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभा रहा है। इस बीच प्रो. गोबर्धन दास ने सोशल मीडिया पर अपनी नियुक्ति पर आभार व्यक्त करते हुए इसे अपने जीवन का महत्वपूर्ण क्षण बताया। उन्होंने कहा कि एक साधारण किसान परिवार से आने के बावजूद उन्हें देश की सेवा का अवसर मिला है, जो उनके लिए गर्व की बात है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी उनकी पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए उनके योगदान की सराहना की और कहा कि पब्लिक हेल्थ, विज्ञान और नवाचार के क्षेत्र में उनका कार्य देश के लिए प्रेरणादायक है।

पानी की दक्षता और सुशासन की ओर राष्ट्रीय बदलाव का आह्वान : अनुराग सिंह ठाकुर

एजेंसी (हि.स.)
हमीरपुर

सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली में आयोजित चौथे विकासशील अर्थव्यवस्था सम्मेलन में मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित करते हुए जल प्रबंधन, दक्षता और सुशासन की दिशा में राष्ट्रीय स्तर पर ठोस बदलाव की आवश्यकता पर जोर दिया। यह सम्मेलन शुक्रवार को एरोसिटी स्थित पुलमैन होटल में केपीटी पाइप्स और अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हीटिंग, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया, जिसका विषय पानीः जीवन का अमृत झ ऊर्जा, संसाधन और प्रौद्योगिकी था।

अपने संबोधन की शुरूआत में अनुराग सिंह ठाकुर ने इतिहास और वर्तमान भारत के बीच समानता स्थापित करते हुए कहा कि कोई भी सभ्यता जल के कुप्रबंधन के कारण लंबे समय तक टिक नहीं सकी। सिंधु घाटी, मेसोपोटामिया और रोमन साम्राज्य जैसे उदाहरणों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि जल केवल एक सरकारी विषय नहीं, बल्कि सभ्यतागत और अस्तित्व से जुड़ा मुद्दा है।

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा जल सुरक्षा के लिए अपनाए गए चार प्रमुख स्तंभों का उल्लेख किया। जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल योजना की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि वर्ष 2019 में जहां केवल 17 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों तक पाइप जल पहुंचता था, वहीं आज 15 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल से जल उपलब्ध कराया जा चुका है और 15 राज्यों ने शत-प्रतिशत कवरेज हासिल कर लिया है। इसे उन्होंने जनस्वास्थ्य के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक पहल बताते हुए कहा कि इससे करोड़ों महिलाओं को पानी लाने के लिए लंबी दूरी तय करने से मुक्ति मिली है।

अनुराग सिंह ठाकुर ने पारंपरिक सोच को चुनौती देते हुए कहा कि केवल जल संरक्षण पर्याप्त नहीं है, बल्कि अब जल दक्षता को भी अपनाना जरूरी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि संरक्षण का अर्थ पानी कम उपयोग करना है, जबकि दक्षता का अर्थ है पानी का समझदारी से उपयोग करना। उन्होंने पहले से शुद्ध किए गए नगर निगम के पानी पर रिवर्स ऑस्मोसिस प्रणाली के अनावश्यक उपयोग को जल की बबार्दी का उदाहरण बताते हुए कहा कि इस प्रक्रिया में 40 से 60 प्रतिशत पानी व्यर्थ चला जाता है, जिसे बदलना आवश्यक है। उद्योग जगत और संबंधित संस्थानों के सदस्यों से आह्वान करते हुए उन्होंने चार महत्वपूर्ण उपाय सुझाए। इसमें हर भवन में जल मीटरिंग और उप-मीटरिंग को अनिवार्य बनाना, जल दक्ष ताप, वेंटिलेशन और वातानुकूलन तथा प्लंबिंग प्रणाली अपनाना, वर्षा जल संचयन और ग्रे वाटर पुनर्चक्रण को बढ़ावा देना तथा जल जागरूकता के लिए प्रशिक्षण और मानक विकसित करना शामिल है।

उन्होंने कहा कि बूंद-बूंद से घड़ा भरता है और हर जल संरक्षण का प्रयास भारत के भविष्य को सुरक्षित बनाने में योगदान देगा। उन्होंने जोर दिया कि आज लिए गए निर्णय आने वाले 50 वर्षों के जल प्रबंधन की दिशा तय करेंगे।

युवाओं के हाथों में है मादक पदार्थों के खतरे को समाप्त करने की कुंजी : मनोज सिन्हा

जम्मू। जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा शनिवार को 'नशा मुक्त अभियान' के तहत 100 दिवसीय गहन अभियान के हिस्से के रूप में सांबा जिला मुख्यालय पहुंचे। उन्होंने कहा कि युवाओं के हाथों में ही मादक पदार्थों के खतरे को समाप्त करने की कुंजी है। सांबा में भारी जनसभा हुई जहां समाज के सभी वर्गों के लोग नशामुक्त अभियान का समर्थन करने के लिए एकजुट हुए और समाज से नशे की बुराई को खत्म करने का संकल्प लिया। उपराज्यपाल ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने दोहराया कि यह 100 दिवसीय आंदोलन आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगा और इस बात का प्रमाण होगा कि जब लोग एकजुट होते हैं तो वे इतिहास बदल सकते हैं। गत 11 अप्रैल को उपराज्यपाल ने नशा विरोधी अभियान की शुरूआत के उपलक्ष्य में जम्मू के मध्य में स्थित एमए स्टेडियम से परेड ग्राउंड तक पदयात्रा का नेतृत्व किया। पिछले पखवाड़े में उन्होंने अभियान के तहत विभिन्न जिलों में रैलियों का नेतृत्व किया। उपराज्यपाल ने युवाओं को बताया कि इस गंभीर समस्या का समाधान उनके हाथों में है।

राष्ट्रपति के दौरे को लेकर शिमला में पुलिस अलर्ट, सुरक्षा के सख्त निर्देश

एजेंसी (हि.स.)
शिमला

शिमला में राष्ट्रपति के प्रस्तावित दौरे को देखते हुए हिमाचल प्रदेश पुलिस ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में शिमला में तैनात किए जाने वाले पुलिस बल के लिए शनिवार को एक विशेष बैठक आयोजित की गई। इसमें पुलिस अधीक्षक शिमला और उप महानिरीक्षक दक्षिणी परिक्षेत्र ने संयुक्त रूप से अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति का यह दौरा 27 अप्रैल से 2 मई तक रहेगा और इस दौरान वह शिमला के पास मशोबरा स्थित राष्ट्रपति निवास में ठहरेंगी। ऐसे में पूरे कार्यक्रम को सुरक्षित और सुचारू रूप से संपन्न कराना पुलिस की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी। अधिकारियों ने कहा कि यह दौरा पुलिस के लिए अपनी कार्यकुशलता और अनुशासन दिखाने का भी एक अहम मौका है।

बैठक में सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने कर्तव्यों को पूरी सतर्कता और जिम्मेदारी के साथ निभाने के निर्देश दिए गए। अलग-अलग इकाइयों के बीच बेहतर तालमेल और लगातार संपर्क बनाए रखने पर जोर दिया गया, ताकि किसी भी स्थिति में तुरंत और सही प्रतिक्रिया दी जा सके। साथ ही यह भी कहा गया कि ड्यूटी के दौरान किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सुरक्षा से जुड़े सभी प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना होगा।

पुलिस अधिकारियों ने आम लोगों और बाहर से आने वाले मेहमानों के साथ विनम्र और सहयोगपूर्ण व्यवहार बनाए रखने की भी हिदायत दी, ताकि पुलिस की सकारात्मक छवि सामने आए। उप महानिरीक्षक ने कहा कि इस उच्च स्तर के दौरे के दौरान हिमाचल प्रदेश पुलिस का काम पूरे देश की नजर में रहेगा, इसलिए हर अधिकारी को आगे बढ़कर जिम्मेदारी निभानी होगी।

पुलिस अधीक्षक शिमला ने सभी कर्मचारियों को अपने-अपने काम की पूरी तैयारी पहले से करने और हर स्थिति के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए, ताकि किसी भी आकस्मिक परिस्थिति का प्रभावी ढंग से सामना किया जा सके। पुलिस विभाग ने कहा है कि वह राष्ट्रपति के दौरे को पूरी तरह सुरक्षित, व्यवस्थित और सफल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और इस मौके को अपनी पेशेवर क्षमता दिखाने के अवसर के रूप में देख रहा है।

ठियोग के देहना में किसानों को संतुलित उर्वरक उपयोग पर किया जागरूक

एजेंसी (हि.स.)
शिमला

ठियोग उपमंडल के देहा में किसानों के बीच संतुलित उर्वरक उपयोग को लेकर शनिवार को एक जागरूकता अभियान आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान (आईसीएआर) के तत्वावधान में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान (सीपीआरआई) शिमला के वैज्ञानिकों की टीम द्वारा आयोजित किया गया। अभियान का उद्देश्य किसानों को वैज्ञानिक तरीके से पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में जानकारी देना और मिट्टी की उर्वरता के साथ-साथ फसल उत्पादकता बढ़ाना था।

कार्यक्रम के दौरान वैज्ञानिकों की टीम ने किसानों के साथ सीधा संवाद किया और उनकी खेती से जुड़ी समस्याओं को समझते हुए व्यावहारिक सुझाव दिए। ग्राम पंचायत की प्रधान कंचन स्नैक ने टीम का स्वागत किया और इस तरह के प्रयासों को किसानों के लिए उपयोगी बताया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय किसान और ग्रामीण मौजूद रहे।

सीपीआरआई के निदेशक डॉ. ब्रजेश सिंह ने कहा कि संतुलित उर्वरक उपयोग खेती के लिए बेहद जरूरी है। उन्होंने किसानों को मिट्टी परीक्षण कराने, पोषक तत्वों के सही अनुपात बनाए रखने और रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक इस्तेमाल से बचने की सलाह दी। उनका कहना था कि सही जानकारी के अभाव में किसान अक्सर जरूरत से ज्यादा उर्वरक इस्तेमाल कर लेते हैं, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता प्रभावित होती है।

प्रधान वैज्ञानिक डॉ. अनिल कुमार चौधरी ने रासायनिक, जैविक और जैव उर्वरकों के प्रकारों और उनके उपयोग के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने किसानों को कम्पोस्ट, वर्मी कम्पोस्ट और जैव उर्वरकों को अपनाने के लिए प्रेरित किया, ताकि मिट्टी का स्वास्थ्य बेहतर हो सके और उत्पादन भी बढ़े।

सिरमौर में गर्मी के बीच आग से निपटने की तैयारी, 53 जल टैंकर चिन्हित

एजेंसी (हि.स.)
नाहन

सिरमौर जिले में बढ़ती गर्मी के साथ आग लगने की घटनाओं की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। गर्म मौसम की दस्तक के साथ ही वनों और ग्रामीण इलाकों में आग लगने के मामले बढ़ने की संभावना रहती है, ऐसे में आपात स्थिति में पानी की कमी एक बड़ी चुनौती बन जाती है।

इसी समस्या से निपटने के लिए जल शक्ति विभाग सिरमौर ने जिले में 53 जल भंडारण टैंकों को चिन्हित किया है, जिनका उपयोग आग लगने की स्थिति में अग्निशमन विभाग कर सकेगा। इन टैंकों का उद्देश्य खास तौर पर उन क्षेत्रों में पानी उपलब्ध कराना है, जहां तुरंत जल आपूर्ति करना मुश्किल होता है।

अधीक्षण अभियंता राजीव महाजन ने बताया कि गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा कि जिले के सभी खंडों में संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर इन टैंकों का इस्तेमाल तुरंत किया जा सके। इसके साथ ही इन टैंकों की सूची उपायुक्त सिरमौर और होम गार्ड्स को भी भेज दी गई है, ताकि समन्वय बनाकर समय पर कार्रवाई की जा सके।

पिछले साल भी जिले में आग लगने के कई मामले सामने आए थे और इस साल भी ऐसी घटनाएं शुरू हो चुकी हैं। ऐसे में विभाग की यह पहल आग से होने वाले नुकसान को कम करने में मददगार साबित हो सकती है।

संक्षिप्त-समाचार

पुलिस ने लौटाया नकदी-गहनों से भरा महिला का खोया पर्स

शिमला। शिमला के संजौली क्षेत्र में एक महिला का खोया हुआ पर्स पुलिस ने नकदी और कीमती आभूषणों सहित सुरक्षित बरामद कर लिया है। पुलिस थाना संजौली की टीम ने यह कार्रवाई त्वरित ढंग से करते हुए पर्स को उसकी असली मालकिन को लौटा दिया। जानकारी के अनुसार अनीता दरेवला का पर्स कहीं गुम हो गया था। इसमें नकदी के साथ-साथ कीमती गहने भी रखे हुए थे। पर्स खोने की सूचना मिलते ही पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और तुरंत आसपास के इलाके में तलाश शुरू कर दी। पुलिस टीम ने इलाके में जांच-पड़ताल करते हुए हर संभावित जगह पर खोजबीन की। लगातार प्रयास और सूझबूझ के चलते पुलिस को सफलता मिली और पर्स को ढूंढ निकाला गया। जांच के बाद यह भी सुनिश्चित किया गया कि पर्स में रखी नकदी और आभूषण पूरी तरह सुरक्षित हैं। इसके बाद सभी औपचारिकताएं पूरी कर पर्स को महिला को वापस सौंप दिया गया। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में पुलिस के प्रति भरोसा और मजबूत हुआ है। लोगों का कहना है कि पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई से सुरक्षा की भावना को बढ़ावा मिला है।

हिमाचल में सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को ग्रेच्युटी-लीव इनकैशमेंट का बकाया जारी करने के आदेश

शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को राहत देते हुए उनकी ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट के शेष 30 प्रतिशत बकाया के भुगतान के आदेश जारी कर दिए हैं। यह फैसला मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू के निर्देशों के बाद लिया गया है। एक सरकारी प्रवक्ता के मुताबिक यह आदेश उन कर्मचारियों पर लागू होगा जो 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए हैं या सेवा के दौरान जिनका निधन हो गया था। सरकार ने साफ किया है कि संबंधित पेंशन वितरक प्राधिकरणों को निर्देश दिए गए हैं कि यह भुगतान जल्द से जल्द किया जाए, ताकि इन कर्मचारियों या उनके परिवारों को लंबित राशि पूरी तरह मिल सके। प्रवक्ता ने यह भी बताया कि राज्य सरकार पहले ही इस अवधि के कर्मचारियों को अंतरिम राहत के तहत पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी किस्त का भुगतान कर चुकी है। इसके अलावा मूल पेंशन और पारिवारिक पेंशन पर महंगाई भत्ते की 12 किस्तें भी दी जा चुकी हैं। इन किस्तों को पेंशन या पारिवारिक पेंशन के बकाया के साथ समायोजित किया जा सकता है। सरकार का कहना है कि नए आदेश के बाद यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट से जुड़ी कोई भी बकाया राशि बाकी न रहे और सभी भुगतान पूरी तरह निपटा दिए जाएं।

चौपाल में 130 ग्राम चरस के साथ एक काबू

शिमला। शिमला जिले के चौपाल क्षेत्र में पुलिस ने एक व्यक्ति को 130 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई शनिवार को उस समय की गई जब पुलिस की टीम इलाके में गश्त पर थी। पुलिस के अनुसार गश्त के दौरान टीम को एक विश्वसनीय स्रोत से सूचना मिली कि एक व्यक्ति क्यारी नाला की ओर मादक पदार्थ बेचने के उद्देश्य से आ रहा है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और क्यारी नाला के पास सरायन की ओर से आ रहे संदिग्ध व्यक्ति को रोक लिया। आरोपी की पहचान चौपाल के शीलन गांव निवासी संत राम के रूप में हुई है। पुलिस द्वारा तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 130 ग्राम चरस बरामद हुई। इसके बाद उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में पुलिस थाना चौपाल में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20, 61 और 85 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि आरोपी को अदालत में पेश किया जाएगा और मामले की आगे की जांच जारी है।

शिमला से लापता दो बच्चे अमृतसर में सुरक्षित मिले

शिमला। राजधानी के न्यू शिमला क्षेत्र से लापता हुए दो नाबालिग बच्चों को पुलिस ने सुरक्षित बरामद कर लिया है। दोनों बच्चों की उम्र 12 और 17 वर्ष है। इस मामले में पुलिस थाना न्यू शिमला में 10 अप्रैल को गुमशुदगी की शिकायत मिलने के बाद मामला दर्ज किया गया था। पुलिस के अनुसार बच्चों के लापता होने की सूचना मिलते ही मामले को गंभीरता से लिया गया और उनकी तलाश के लिए लगातार प्रयास शुरू किए गए। पुलिस टीम ने सुनियोजित तरीके से जांच की और विभिन्न जगहों पर जानकारी जुटाई। जांच के दौरान मिले अहम सुरागों के आधार पर टीम पंजाब के अमृतसर पहुंची। वहां स्वर्ण मंदिर क्षेत्र में दोनों बच्चों को ढूंढ निकाला गया। पुलिस ने बताया कि पूछताछ के दौरान बच्चों ने बताया कि वे घर से घूमने के इरादे से निकले थे। पुलिस ने आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद दोनों बच्चों को उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। पुलिस का कहना है कि समय रहते कार्रवाई करने से बच्चों को सुरक्षित वापस लाने में सफलता मिली।

घाटी के विभिन्न हिस्सों से 10 तस्कर गिरफ्तार, प्रतिबंधित पदार्थ बरामद

एजेंसी (हि.स.)
श्रीनगर

100 दिवसीय नशा मुक्त जम्मू-कश्मीर अभियान के तहत चल रहे व्यापक नशा-विरोधी अभियान को जारी रखते हुए पुलिस ने घाटी के विभिन्न हिस्सों से 10 नशीले पदार्थों के तस्करों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से प्रतिबंधित पदार्थ बरामद किए हैं। अनंतनाग में उतरासू पुलिस स्टेशन की एक पुलिस टीम ने तंजमुल्ला चटरगुल चौराहे पर नाका चेकिंग के दौरान पंचलथान चटरगुल निवासी मोहम्मद यूसुफ हाजम जो मोहम्मद हाजम का पुत्र है, को गिरफ्तार किया। मोहम्मद हाजम एक नियमित नशीले पदार्थों का तस्कर है। उसके पास से 1.600 किलोग्राम चरस पाउडर जैसा पदार्थ बरामद किया गया। इसी बीच जीबीएस पुलिस चौकी की एक पुलिस टीम ने बन मोहल्ला आंचीदोरा निवासी आकाश अहमद डार जो अब राशिद डार का पुत्र है को गिरफ्तार किया। तलाशी लेने पर कपड़े में लिपटा हुआ 26 ग्राम चरस जैसा पदार्थ बरामद हुआ। इसके अलावा पंजमुल्ला में नियमित नाका चेकिंग के दौरान ऐशमुकाम पुलिस स्टेशन ने हलवानी गनीगुंड निवासी मोहम्मद यूसुफ शाह के पुत्र शब्बीर अहमद शाह को 78 ग्राम चरस पाउडर और 9 ग्राम चरस के टुकड़ों के साथ गिरफ्तार किया। साथ ही, हलमुल्ला में नाका चेकिंग के दौरान संगम पुलिस चौकी की एक पुलिस टीम ने अवंतीपोरा से आ रही एक ऑटो (जेके13के-1926) को रोका। नैना बटापोरा निवासी अली मोहम्मद ट्राम्बू के पुत्र बशीर अहमद ट्राम्बू को 4.130 किलोग्राम चरस पाउडर और 56 ग्राम वजन की 4 चरस की डंडियों के साथ गिरफ्तार किया गया। इसी तरह सोपोर में चिंकीपोरा पब्लिक पार्क के पास गश्त के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति को रोका गया और गिरफ्तार किया गया। तलाशी लेने पर मनोरोगी पदार्थ (स्पास्मोप्रॉक्सीवॉन कैप्सूल) बरामद किया गया और उचित प्रक्रिया के तहत जब्त कर लिया गया। आरोपित की पहचान जुबैर अहमद मल्ला पुत्र अली मोहम्मद मल्ला निवासी महाराजपोरा सी सोपोर के रूप में हुई है। इसके अलावा, शिव क्रॉसिंग पर नाका चेकिंग के दौरान बोमाई पुलिस स्टेशन की टीम ने शौकत अहमद शाह पुत्र रियाज अहमद शाह निवासी दुरू सोपोर के पास से चरस जैसा नशीला पदार्थ बरामद किया। बारामूला में पुलिस ने नवान मोडे क्रेरी में नाका चेकिंग के दौरान एक नशीले पदार्थ तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान फैजान मोहिउद्दीन वानी पुत्र गुलाम मोहिउद्दीन वानी निवासी पेठगाम वागूरा के रूप में हुई है। तलाशी के दौरान उसके पास से मनोरोगी पदार्थ की गोलियां बरामद हुईं। बरामद प्रतिबंधित सामग्री में क्लोनाजेपम (2 स्ट्रिप्स), जोलपिडेम टार्ट्रेट (1 स्ट्रिप), एमनुराइट-पी (1 स्ट्रिप), डी वेनिज 100 (1 स्ट्रिप), वेंटैब एक्सएल 150 (1 स्ट्रिप), टैपेंटाडोल एचसीएल (3 स्ट्रिप्स) शामिल हैं, कुल मिलाकर 87 गोलियां। प्रतिबंधित सामग्री के परिवहन में इस्तेमाल की गई वाहन (सिएरा) जिसका पंजीकरण नंबर जेके05क्यू-1100 है को भी जब्त कर लिया गया है। अवंतीपोरा पुलिस स्टेशन खेव के एसएचओ इंस्पेक्टर नईम राशिद के नेतृत्व में सीर कॉलोनी खेव रोड पर नाका चेकिंग के दौरान शरशल्ली निवासी मुश्ताक अहमद भट के पुत्र रजी मुश्ताक को गिरफ्तार किया गया। तलाशी के दौरान उसके पास से 1.82 ग्राम हेरोइन जैसा पदार्थ बरामद हुआ। पुलवामा में राजपोरा रोड पर ईदगाह क्रॉसिंग पर नाका चेकिंग के दौरान पुलिस दल ने पंजीकरण संख्या जेके13ए-9406 वाली मोटरसाइकिल पर सवार दो व्यक्तियों को रोका। तलाशी के दौरान उनके पास से लगभग 369.5 ग्राम चरस पाउडर और 7 ग्राम चरस बरामद हुई।

पांवटा साहिब में 11.16 ग्राम चिट्टा सहित युवक गिरफ्तार

एजेंसी (हि.स.)
नाहन

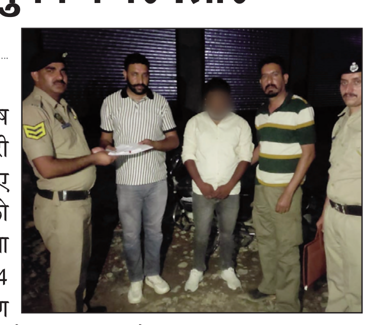

जिला सिरमौर की विशेष अन्वेषण इकाई टीम ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पांवटा साहिब क्षेत्र में एक युवक को चिट्टा/स्मैक सहित गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार 24 अप्रैल 2 की शाम विशेष अन्वेषण इकाई टीम गश्त के दौरान रैनबैक्सी चौक, पांवटा साहिब के पास मौजूद थी और मादक पदार्थों से संबंधित गुप्त सूचनाएं एकत्र कर रही थी। इसी दौरान टीम को गुप्त सूचना मिली कि मुर्तजा उर्फ फरमान, पुत्र मुख्तार, निवासी सहारनपुर (उत्तर प्रदेश), लंबे समय से पांवटा और आसपास के क्षेत्रों में चिट्टा/स्मैक की तस्करी कर रहा है।

सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए टीम ने आरोपी को विद्या पीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, केदारपुर के पीछे एक निमार्णाधीन मकान के पास खेत में दबोच लिया। तलाशी के दौरान आरोपी के पास मौजूद हेलमेट के अंदर छुपाकर रखी गई 11.16 ग्राम चिट्टा/स्मैक बरामद की गई।

इस संबंध में पुलिस थाना पांवटा साहिब में ठऊ&ढर एक्ट की धारा 21, 25 और 61-1985 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और अदालत से पुलिस रिमांड प्राप्त करने की प्रक्रिया जारी है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी यह नशीला पदार्थ कहां से लाया था और इसे किन लोगों तक पहुंचाने की योजना बना रहा था, ताकि पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ किया जा सके।

सावधानी लोगों को दोपहर के समय धूप में निकलने से बचने, पर्याप्त पानी पीने और सावधानी बरतने की सलाह

हिमाचल में दो दिन हीट वेव का अलर्ट, 28 से 30 अप्रैल तक बारिश-आंधी से मिलेगी राहत

एजेंसी (हि.स.)
शिमला

हिमाचल प्रदेश में गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है और हालात ऐसे हो गए हैं कि पहाड़ों में भी लोगों को तपिश का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के कई इलाकों में तापमान सामान्य से काफी अधिक दर्ज किया गया। ऊना सबसे गर्म स्थान रहा, जहां अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया। इसके अलावा भुंतर, सुंदरनगर और धर्मशाला जैसे शहरों में भी अधिकतम तापमान 33 से 36 डिग्री के बीच रहा, जो सामान्य से काफी ज्यादा है। मौसम विभाग ने साफ किया है कि आज 25 अप्रैल और कल 26 अप्रैल को गर्मी और अधिक तीखी रहने के आसार हैं, जिसके चलते दो दिनों के लिए हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। गर्मी के इस बढ़ते असर का अंदाजा न्यूनतम तापमान से भी लगाया जा सकता है, जो लगातार बढ़ रहा है। कुकुमसेरी में सबसे कम न्यूनतम तापमान 6.1 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि इसके बाद ताबो में 8.4 डिग्री, कल्पा में 9.4 डिग्री, सराहन में 11.4 डिग्री, मनाली में 13.3 डिग्री, सेओबाग में 13.5 डिग्री और भरमौर में 14 डिग्री तापमान दर्ज हुआ। इसके अलावा भुंतर में 15 डिग्री, सोलन में 16.5 डिग्री, सुंदरनगर में 17.6 डिग्री, ऊना और धर्मशाला में 18.2 डिग्री, मंडी में 18.3 डिग्री, नाहन में 18.8 डिग्री, शिमला और पालमपुर में 19 डिग्री, कांगड़ा में 20.3 डिग्री, बिलासपुर में 20.5 डिग्री, जुब्बड़हट्टी में 21 डिग्री, देहरा गोपीपुर में 22 डिग्री और पांवटा साहिब में 25 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। शिमला और मनाली जैसे हिल स्टेशनों में भी रातें सामान्य से करीब 6 डिग्री ज्यादा गर्म रिकॉर्ड की गई हैं, जिससे लोगों को राहत नहीं मिल पा रही। मौसम विभाग के पूवार्नुमान के अनुसार 25 अप्रैल को कुछ स्थानों पर हल्की गतिविधि हो सकती है, लेकिन 26 अप्रैल को पूरे प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। 27 अप्रैल को फिर से कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। हालांकि, 28, 29 और 30 अप्रैल को मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। इन तीन दिनों में कई जगहों पर बारिश, आंधी और बिजली गिरने की आशंका है। साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। विभाग ने इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से अप्रैल के आखिरी दिनों में मौसम बदलेगा और इससे तापमान में गिरावट आएगी। बारिश और आंधी के चलते लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। फिलहाल, आज और कल के लिए जारी हीट वेव अलर्ट के बीच लोगों को दोपहर के समय धूप में निकलने से बचने, पर्याप्त पानी पीने और सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

दैनिक सिटी दर्पण
आईना सच का
न्वोन्मेषकः स्व. कृष्णा शर्मा
स्व. गीता शर्मा
संस्थापकः स्व. सतपॉल शर्मा
स्वामी, प्रकाशक एवं संपादक भूपिंद्र शर्मा द्वारा मुद्रक प्रवीन तोमर की इंप्रेशन्ज प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, प्लॉट नं. 22 और 49, ग्राउंड फ्लोर, इंडस्ट्रियल एरिया, फेस-2, पंचकूला-134115 (हरियाणा) पर मुद्रित एवं 180 ए, सेक्टर 19 सी, ओल्ड हाउसिंग बोर्ड कालोनी, पंचकूला, हरियाणा-134113 से प्रकाशित।
सभी विवादों का केंद्र न्यायालय पंचकूला होगा।
स्थानीय कार्यालय
180 ए, सेक्टर 19 सी, ओल्ड हाउसिंग बोर्ड कालोनी, पंचकूला, हरियाणा-134113
संपर्क: 7888450261
Email: citydarpanharyana@gmail.com

नायब सैनी का ऐलान: किसानों को अब व्हाट्सएप पर मिलेगा क्यूआर कोड आधारित जे-फॉर्म

सरकार ने खरीद प्रक्रिया को किया ऑनलाइन, बढ़ी पारदर्शिता: मुख्यमंत्री

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश में अगले सप्ताह से सभी किसानों को व्हाट्सएप के माध्यम से क्यूआर कोड आधारित जे-फॉर्म भेजे जाएंगे, ताकि किसानों को ऋण सहित अन्य प्रकार की सुविधा लेने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो।

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी शनिवार को हरियाणा निवास चंडीगढ़ में पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले सीजन से किसान एप भी लॉन्च किया जाएगा, जिसमें किसानों को जे-फॉर्म, भुगतान की स्थिति, भूमि बुवाई एवं उपज सत्यापन की स्थिति, गेट पास शेड्यूलिंग (अगली सरसों फसल से प्रारंभ), भूमि सत्यापन की स्थिति तथा सभी सूचनाएं किसान ई-खरीद एप में उपलब्ध होंगी। जिससे खरीद कार्य में किसी प्रकार की देरी नहीं होगी।

उन्होंने इस दौरान प्रदेश में अब तक हुई गेहूं खरीद का ब्यौरा देते हुए कहा कि रबी सीजन 2026-27 में प्रदेश की मंडियों में गेहूं की बंपर आवक हुई है। इससे पिछले चार साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सरकार ने खरीद प्रबंधों को लेकर पुख्ता इंतजाम किए, जिसके चलते प्रदेश में गेहूं खरीद का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है और किसानों को समय पर भुगतान भी किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक प्रदेश की मंडियों में 21 हजार 44 करोड़ रुपये मूल्य की 81 लाख 48 हजार मीट्रिक टन गेहूं की आवक दर्ज की जा चुकी है, जो पिछले 4 वर्षों में सर्वाधिक है। अकेले 11 अप्रैल को एक ही दिन में 7 लाख 71 हजार मीट्रिक टन गेहूं की रिकॉर्ड आवक हुई। उन्होंने कहा कि अब तक 5 लाख 80 हजार किसान अपनी उपज लेकर मंडियों में पहुंच चुके हैं। हर किसान की पहचान डिजिटल गेट पास के माध्यम से सुनिश्चित की जा रही है। इसके साथ ही 79 लाख 14 हजार मीट्रिक टन गेहूं का बायोमेट्रिक सत्यापन हो चुका है, जो लगभग 97 प्रतिशत है। प्रदेश का किसान तकनीक को तेजी से अपना रहा है और पारदर्शी व्यवस्था पर भरोसा जता रहा है। प्रदेश की मंडियों में 70 लाख 23 हजार मीट्रिक टन गेहूं की खरीद पूरी हो चुकी है, साथ ही प्रदेश की मंडियों से 34 लाख 56 हजार मीट्रिक टन गेहूं का उठान हो चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 18 अप्रैल से उठान प्रक्रिया में और तेजी आई है। प्रतिदिन साढ़े 3 लाख मीट्रिक टन का उठान हो रहा है। पिछले वर्ष से तुलना करते हुए उन्होंने कहा कि रबी सत्र 2025-26 में जहां कुल 72 लाख 89 हजार मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई थी। वहीं, इस वर्ष अब तक 81 लाख 48 हजार मीट्रिक टन की आवक हो चुकी है।

उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकारों के समय न डिजिटल व्यवस्था थी, न पारदर्शिता थी, न समय पर भुगतान होता था। किसानों को मंडियों में लंबी कतारों में खड़ा रहना पड़ता था, कागजी टोकन बनते थे और भुगतान के लिए हफ्तों, कभी-कभी महीनों का इंतजार करना पड़ता था। वर्ष 2014 से अब तक फसल खरीद की प्रक्रिया में बड़ा सुधार हुआ है। इससे पहले, केवल गेहूं और धान की ही खरीद एम.एस.पी. पर होती थी। आज हरियाणा देश का पहला राज्य है, जहां सभी फसलों की एम.एस.पी. पर खरीद होती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर इस वर्ष 10 लाख 7 हजार 657 किसान पंजीकृत हैं। सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए ई-खरीद पोर्टल और मोबाइल एप के माध्यम से डिजिटल गेट पास और एग्जिट पास की व्यवस्था लागू की है। इस सीजन में अब तक 13 लाख 47 हजार डिजिटल गेट पास जारी किए गए हैं।

फसल खरीद सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने प्रदेश की सभी 416 मंडियों व 281 खरीद केन्द्रों की जियो फेंसिंग की है। इससे यह सुनिश्चित हुआ है कि मंडी से बाहर किसी अज्ञात स्थान पर कोई भी फर्जी खरीद संभव नहीं है। इसके साथ-साथ सीसीटीवी से खरीद प्रक्रिया की निगरानी हो रही है। प्रदेश की मंडियों में 932 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार ने आढ़ती की सेवाओं को ध्यान में रखते हुए उनका कमीशन 33 रुपये 75 पैसे प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 55 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है। इसके अलावा इस वर्ष बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की फसल को प्रभावित किया है। लेकिन सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए गुणवत्ता मानकों में राहत दी। पहले जहां चमक में कमी बिल्कुल स्वीकार नहीं थी, अब उसे 70 प्रतिशत तक स्वीकार किया गया है। टूटे और सिकुड़े दानों की सीमा 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दी गई है। यह निर्णय खरीद शुरू होने की तारीख से लागू किया गया, ताकि किसी भी किसान का नुकसान न हो।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने फसल खराबे पर गत 11 सालों में किसानों को मुआवजे और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 16 हजार 160 करोड़ रुपये की राशि दी है। इसी के साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लगभग 20 लाख 18 हजार किसानों को 22 किस्तों में 7 हजार 562 करोड़ रुपये की राशि किसानों के बैंक खातों में डाली जा चुकी है।

इस अवसर पर विधायक श्री निखिल मदान, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री अरुण गुप्ता, खाद्य आपूर्ति विभाग के आयुक्त एवं सचिव श्री जे गणेशन, सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग की अतिरिक्त निदेशक श्रीमती वर्षा खांगवाल, श्री मनीष लोहान, मुख्यमंत्री के मीडिया सचिव श्री प्रवीण आत्रेय भी मौजूद थे।

अमृतसर के व्यापारियों ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से की भेंट

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

- **मजीठ मंडी के सुखे मेवे के थोक व्यापार को सोनीपत में विस्तार की स्वीकृति**

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी से शनिवार को पंजाब के अमृतसर स्थित मजीठ मंडी के व्यापारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने शिष्टाचार भेंट की। यह मुलाकात संत कबीर कुटीर आवास पर हुई है। इस अवसर पर व्यापारियों ने अपने व्यवसाय के विस्तार तथा हरियाणा में निवेश की संभावनाओं को लेकर मुख्यमंत्री से विस्तार से चर्चा की। बैठक के दौरान मजीठ मंडी, अमृतसर के व्यापारियों द्वारा सुखे मेवे के थोक व्यापार को सोनीपत में विस्तारित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिस पर मुख्यमंत्री ने सकारात्मक रुख अपनाते हुए इसे स्वीकृति प्रदान की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार प्रदेश में व्यापार एवं उद्योग को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और निवेशकों को सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने अमृतसर से आए सभी व्यापारियों का हरियाणा में स्वागत करते हुए कहा कि राज्य सरकार इज आफ डूइंग बिजनेस के सिद्धांत पर कार्य कर रही है, जिससे व्यापारियों को पारदर्शी, सरल एवं सुगम प्रक्रियाएं सुनिश्चित हो सकें। उन्होंने कहा कि हरियाणा आज देश के प्रमुख औद्योगिक एवं लॉजिस्टिक हब के रूप में उभर रहा है, जहां निवेश के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध है। उन्होंने यह भी अवगत कराया कि अमृतसर के अतिरिक्त दिल्ली के खारी बावली तथा भगीरथ पैलेस जैसे प्रमुख व्यापारिक केंद्रों के विस्तार को भी राई (सोनीपत) क्षेत्र में पहले ही स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

हरियाणा में लक्षित सुक्ष्म योजना और जन भागीदारी से मलेरिया के खिलाफ लड़ाई की तेज

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

- **राज्य में पॉजिटिविटी रेट कम, मौत का आंकड़ा जीरो; विश्व मलेरिया दिवस पर निगरानी बढ़ाई**

विश्व मलेरिया दिवस पर हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग ने मलेरिया को खत्म करने में तेजी लाने के लिए कई नई लक्षित पहल शुरू की हैं, जिसमें गांव और मोहल्ला स्तर पर सुक्ष्म निगरानी स्त्रोत का पता लगाना और घनी जोखिम वाली आबादी की मॉनिटरिंग पर फोकस किया गया है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने बताया कि ये उपाय राज्य भर में ट्रांसमिशन को रोकने के लिए जल्दी पता लगाने और तुरंत जबरदस्त इलाज सुनिश्चित करने के लिए तैयार किए गए हैं।

इस नई पहल के तहत स्वास्थ्य कार्यकताओं द्वारा नियमित की जाने वाली गतिविधियों.के अलावा, पिछले साल मलेरिया के मामलों की रिपोर्ट करने वाले सभी गांवों और शहरी इलाकों को कवर करने के लिए एक सघन सुक्ष्म योजना तैयार की गई।ऐसे इलाकों में स्वास्थ्य टीमें हर महीने घर घर जाकर सर्वे कर रही हैं, जिसमें 950 से ज्यादा दौरे पहले ही किए जा चुके हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी संभावित मामला छूट न जाए।

विभाग का यह एक और कदम है कि हर रिपोर्ट की जांच अवश्य की जाएगी। अब हर केस की जांच एक स्पेशल टीम करती है, जिसमें एक एपिडेमियोलॉजिस्ट भी शामिल है ताकि इन्फेक्शन की सही शुरूआत में ही पता लगाया जा सके तथा उस सोर्स को फैलने से रोका जा सके। इस वैज्ञानिक, डेटा-ड्रिवन तरीके से बीमारी की निगरानी और मजबूत होने की उम्मीद है।

यह मानते हैं कि 75 प्रतिशत से ज्यादा नए केस बाहर से आए मजदूरों से जुड़े हुए हैं। विभाग द्वारा लेबर साइट्स का हर महीने हर महीने के पहले सोमवार को जांच शुरू की जाएगी। इस लक्षित बाहरी पहुंच का उद्देश्य कमजोर समूह में इन्फेक्शन का जल्दी पता लगाना और फैलने का खतरा कम करना है।

इस साल की ग्लोबल थीम ह्लमलेरिया खत्म करने के प्रयास अब हमें करने ही होंगे। हरियाणा ने मलेरिया को नियंत्रण करने में पहले ही काफी तरक्की कर ली है। वर्ष 2014 में 4,485 केसों में से तेजी से घटकर 2025 में सिर्फ.202 रह गए है, और हाल के सालों में मलेरिया से कोई मौत नहीं हुई है। वर्ष 2025 में दर्ज कुल 515 मामलों में से, सिर्फ.202 राज्य के अंदर के थे, जबकि बाकी दूसरे राज्यों से जुड़े हुए थे। खास बात यह है कि 31 मार्च, 2026 तक सिर्फ.8 मामले दर्ज हुए हैं, जो अब लगातार नियंत्रण में है।

राज्य के मजबूत निगरानी सिस्टम के तहत वर्ष 2025 में 36 लाख से ज्यादा टेस्ट किए गए। वार्षिक रक्त जांच दर 12.37 प्रतिशत तक पहुँच गई, जो राट्रीय स्तर से ज्यादा है, जबकि पॉजिटिविटी रेट 0.014 प्रतिशत बहुत कम है। जो बेहतर रोकथाम के प्रयासों को दशार्ता है। हरियाणा में डायग्नोसिस के लिए फील्ड सर्वे के दौरान आरडीटी को मुख्य टूल के तौर पर इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा है। जबकि संस्थान स्तर पर डायग्नोसिस के लिए माइक्रोस्कोपी को मुख्य आधार के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा।

स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे बुखार के मामलों की तुरंत जांच करवाएं और पूरा इलाज करवाने सहयोग करें। प्राइवेट डॉक्टरों से भी संक्रामक रोग अधिनियम 1899 के तहत मलेरिया के मामलों को नोटिफाई करें। इस पर बल दिया गया है कि बीमारी फैलने से रोकने के लिए समय पर रिपोर्टिंग बहुत जरूरी है।

लगातार निगरानी जन भागीदारी के साथ, हरियाणा मलेरिया को पूरी तरह खत्म करने के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।

कुवि एजुकेशन वर्ल्ड की रैंकिंग में हरियाणा में प्रथम और देशभर में 19वें स्थान पर

सिटी दर्पण संवाददाता
कुरुक्षेत्र

- **कुलगुरु प्रो. सोमनाथ सचदेवा ने दी बधाई**
- **गुणवत्ता आधारित शिक्षा से कुवि ने बनाई अंतरराष्ट्रीय पहचान: प्रो. सोमनाथ सचदेवा**

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए एजुकेशन वर्ल्ड द्वारा जारी रैंकिंग में पूरे भारत में 19वां और हरियाणा में पहला स्थान प्राप्त किया है। विश्वविद्यालय को यह प्रतिष्ठित सम्मान आज नई दिल्ली के होटल ग्रैंड में आयोजित एक भव्य समारोह के दौरान प्रदान किया गया। यह रैंकिंग देशभर के 2,175 शिक्षाविदों, उद्योग जगत के विशेषज्ञों और छात्रों के बीच किए गए एक व्यापक सर्वेक्षण पर आधारित है। विभिन्न शैक्षणिक मापदंडों के मूल्यांकन में केयू देश के अग्रणी शिक्षण संस्थानों में उभरकर सामने आया है।

इस अवसर पर कुलगुरु प्रो. सोमनाथ सचदेवा ने इस उपलब्धि का श्रेय विश्वविद्यालय की शैक्षणिक गुणवत्ता और उच्च स्तरीय अनुसंधान के प्रति प्रतिबद्धता को दिया। उन्होंने कहा कि यह रैंकिंग विश्वविद्यालय परिवार के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। उन्होंने बताया कि यह सम्मान संस्थान की शिक्षण और अनुसंधान में उत्कृष्टता के प्रति समर्पण का प्रमाण है। साथ ही, विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को उसकी मूल भावना के अनुरूप लागू करते हुए विद्यार्थियों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार किया है। कुलगुरु ने इस सफलता के लिए सभी शिक्षकों, गैर-शिक्षक कर्मचारियों और विद्यार्थियों को बधाई दी और विश्वास जताया कि इस प्रकार की पहचान से विश्वविद्यालय को वैश्विक शैक्षणिक मानकों को हासिल करने की नई प्रेरणा मिलेगी।

आईक्यूएसी सेल के प्रमुख प्रो. तेजेन्द्र शर्मा ने बताया कि कुवि ने राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष विश्वविद्यालयों में 19वां स्थान प्राप्त किया है तथा राज्य में सर्वोच्च स्थान हासिल कर हरियाणा में अपनी अग्रणी स्थिति बरकरार रखी है। उन्होंने यह भी कहा कि विश्वविद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रभावी रूप से लागू करने वाले अग्रणी संस्थानों में शामिल है।

लोक सम्पर्क विभाग के निदेशक प्रो. महासिंह पूनिया ने बताया कि वर्ष 1956 में स्थापित कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय देश के प्रतिष्ठित बहु-विषयक संस्थानों में से एक है। विश्वविद्यालय अपनी समृद्ध विरासत और आधुनिक शिक्षण पद्धतियों के साथ नवाचार और समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है तथा क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

राज्य सरकार ने खरीफ 2025 का 370.52 करोड रुपए का फसल मुआवजा किया मंजूर: हरपाल सिह

सिटी दर्पण संवाददाता
कुरुक्षेत्र

हरियाणा पंजाबी साहित्य एवं संस्कृति अकादमी के निदेशक एवं शुगरफेड के पूर्व चेयरमैन हरपाल सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार लगातार किसानों के हित में कार्य कर रही है। प्रदेश सरकार ने खरीफ 2025 फसल मुआवजा योजना के तहत 370.52 करोड रुपए के बजट को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के इस निर्णय से प्रदेश के 1.50 लाख से अधिक किसान लाभांवित होंगे। इन किसानों के खातों में सीधे इस राशि को ट्रांसफर किया जाएगा।

उन्होंने जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि अभी हाल में ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों की बैठक लेकर निर्देश दिए हैं कि किसानों के लिए जितनी भी कृषि योजनाएं बनाई गई हैं। उनका सरलीकरण होना चाहिए। किसानों को डिजिटल प्रक्रिया के इस्तेमाल के समय कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए।

पूर्व चेयरमैन हरपाल सिंह ने कहा कि मुआवजा ई क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से जारी किया जाएगा। मेरी फसल, मेरा ब्यौरा प्रणाली से एकीकृत एक पारदर्शी और किसानों के अनुकूल डिजिटल प्लेटफॉर्म है। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र को समृद्ध बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार कार्य कर रहे हैं। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी लगातार किसानों, दूध उत्पादकों, मधुमक्खी पालकों व स्वयं सहायता समूहों से सीधा संवाद कर रहे हैं ताकि उनकी जमीनी समस्याओं को जानकर उन्हें दूर किया जा सके। किसानों के अलावा हरियाणा सरकार ने दिव्यांगजनों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए 40 प्रतिशत से 99 प्रतिशत तक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को हरियाणा रोडवेज की साधारण बसों में मुफ्त यात्रा सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है। इस फैसले से प्रदेश के लगभग 1.22 लाख दिव्यांगजन लाभान्वित होंगे।

उन्होंने बताया कि प्रदेश के दिव्यांगजनों द्वारा लंबे समय से यह मांग की जा रही थी कि 100 प्रतिशत से कम दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को भी यह सुविधा दी जाए। इस मांग को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है।

खाद्य आपूर्ति विभाग ने 343471, हैफेड ने 151548 व वेयरहाउस ने 11772 एमटी खरीदी गेहूं

खरीद एजेंसियों ने अब तक खरीदी 506728 मीट्रिक टन गेहूं: विवेक आर्य

सिटी दर्पण संवाददाता
कुरुक्षेत्र

अतिरिक्त उपायुक्त विवेक आर्य ने कहा कि कुरुक्षेत्र के खरीद केन्द्रों व मंडियों में गेहूं की खरीद का कार्य खाद्य आपूर्ति, हैफेड तथा हरियाणा वेयर हाउस एजेंसी द्वारा शुरू कर दिया गया है। इन तीनों एजेंसियों ने 24 अप्रैल को देर सायं तक 506728 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद का कार्य पूरा कर लिया है। इस सीजन में गेहूं का 2585 रुपए प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जा रहा है। अहम पहलू यह है कि जिले में 291312 एमटी गेहूं का उठान कार्य पूरा किया गया है।

एडीसी विवेक आर्य ने कहा कि कुरुक्षेत्र में गेहूं की खरीद करने के लिए 29 खरीद केन्द्र व मंडिया स्थापित की गई है। इन मंडियों से खाद्य आपूर्ति, हैफेड, एफसीआई और हरियाणा वेयर हाउस कार्पोरेशन की तरफ गेहूं की खरीद का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि खाद्य आपूर्ति विभाग की रिपोर्ट के अनुसार इस सीजन में खाद्य आपूर्ति एजेंसी द्वारा अजराना कला में 3322, अमीन में 2710 एमटी, बाबैन मंडी में 26231 एमटी, बारना में 2757 एमटी गेहूं, भौर सैंयदा में 4321 एमटी, बोधनी में 6650 एमटी गेहूं, चढुनी जाटान में 2009 एमटी गेहूं, गुमथला गढु में 21709 एमटी, इशाक में 4615 एमटी, इस्माइलाबाद मंडी में 71293 एमटी, झांसा मंडी में 10766 एमटी, कराह साहब में 9220 एमटी, किरमच में 1944 एमटी गेहूं, थानेसर मंडी में 84978 एमटी, लाडवा मंडी से 66540 एमटी, लुखी में 3537 एमटी, मलिकपुर में 5880 एमटी, नलवी में 850 एमटी, नीमवाला में 5626 एमटी, पिहोवा मंडी में 58676 एमटी, पिहोवा एक्सटेंशन मंडी में 23504 एमटी, पिपली मंडी से 24943 एमटी, शाहबाद से 40111 एमटी गेहूं, थाना में 3270 एमटी गेहूं, ठोल मंडी से 21256 एमटी गेहूं खरीद गया है।

उन्होंने कहा कि हैफेड द्वारा अजराना कला में 3322 एमटी, बोधनी मंडी में 3888 एमटी, चढुनी जाटान मंडी में 2009 एमटी गेहूं, इस्माईलाबाद मंडी से 26251 एमटी गेहूं, झांसा मंडी में 1032 एमटी गेहूं, किरमच में 1944 एमटी, थानेसर 33533, लाडवा मंडी में 11847 एमटी, लुखी में 3537 एमटी, मलिक पुर में 5880 एमटी, पिहोवा मंडी में 21150 एमटी गेहूं, पिहोवा एक्सटेंशन में 11331 एमटी, गेहूं, पिपली मंडी में 9495 एमटी गेहूं, शाहबाद मंडी में 16239 एमटी गेहूं खरीद कार्य पूरा किया गया है। इसी तरह हरियाणा वेयरहाउस द्वारा बारना में 2757 एमटी, बोधनी में 2762 एमटी, ठोल में 6253 एमटी गेहूं खरीद कार्य को पूरा किया गया है। उन्होंने कहा कि इस सीजन में अधिकारियों को विशेष हिदायत दी गई है कि उठान कार्य पर विशेष फोकस रखा जाए ताकि व्यापारियों और किसानों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। उन्होंने कहा कि मंडी परिसर में किसानों की सुविधा के लिए पर्याप्त बिजली, पानी, सफाई व्यवस्था व अन्य मूलभूत सुविधाओं का ध्यान रखने के आदेश सम्बंधित अधिकारियों को दिए है।

उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा किसानों की फसल का एक-एक दाना खरीदने के लिए व्यवस्था और प्रबंधन सुनिश्चित किए गए हैं। ऐसे में किसान सहभागी बनते हुए खरीद कार्य में अपना योगदान दें। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि वे अपनी गेहूं की फसल को अच्छी तरह से सुखाकर एवं साफ करके मंडी में लाएं।

संक्षिप्त-समाचार

नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगी हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की उपाध्यक्षा सुमन सैनी:कंवलजीत कौर

कुरुक्षेत्र। जिला परिषद की अध्यक्ष कंवलजीत कौर ने कहा कि नारी शक्ति वंदन को लेकर एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन 27 अप्रैल को सुबह 9 बजे पंचायत भवन के सभागार में होगा। इस कार्यक्रम में हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की उपाध्यक्षा सुमन सैनी मुख्य अतिथि होंगी। जिप चेयरपर्सन शनिवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों से बातचीत कर रही थी। इससे पहले जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विरेन्द्र चौधरी ने संबंधित विभागों के स्तर पर होने वाली तैयारियों को लेकर कुछ आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही अधिकारियों, कर्मचारियों की कार्यक्रम के लिए प्रबंध करने और सफल बनाने के लिए ड्यूटियां भी लगाई है। जिप चेयरपर्सन ने कहा कि नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम को सभी के साझे प्रयासों से ऐतिहासिक और सफल बनाया जाएगा। इस कार्यक्रम में कुरुक्षेत्र से सैकड़ों की संख्या में महिलाएं भाग लेंगी। उन्होंने कहा कि सभी बीडीपीओ, सैल्फ हैल्प ग्रुप से सम्बन्धित अधिकारी महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी को सुनिश्चित करेंगे। इस कार्यक्रम में भाजपा संगठन की तरफ से भी महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। इस कार्यक्रम में महिलाओं की उपलब्धियों और सरकार द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने के लिए योजनाओं पर भी प्रकाश डाला जाएगा। इस मौके पर बीडीपीओ अमित, रुबल, विवेक, अंकित, नेहा अग्रवाल सहित अन्य अधिकारी ऑनलाइन प्रणाली से जुड़े हुए थे।

कुवि हर साल आयोजित किया करेगा रोहित सरदाना मेमोरियल व्याख्यान एवं अवार्ड समारोह

कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में पत्रकारिता के क्षेत्र को नई दिशा देने और युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने की पहल के तहत 30 अप्रैल को प्रातः सीनेट हॉल में रोहित सरदाना स्मृति व्याख्यान एवं मेमोरियल अवार्ड 2026 का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम अब हर वर्ष आयोजित किया जाएगा, जिसमें पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले एक युवा पत्रकार को 21 हजार रुपये का राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया जाएगा। जनसंचार एवं मीडिया प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का विषय ह्लपत्रकारिताः अवसर और चुनौतियांह्व रखा गया है, जिसके माध्यम से बदलते मीडिया परिदृश्य, डिजिटल दौर की चुनौतियों और जिम्मेदार पत्रकारिता पर गहन चर्चा की जाएगी। कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ पत्रकार रोहित सरदाना के योगदान को स्मरण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की जाएगी। मीडिया संस्थान के निदेशक प्रो. महासिंह पूनिया ने बताया कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अवनीश भटनागर (राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, विद्या भारती) उपस्थित रहेंगे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता कुलगुरु प्रो. सोमनाथ सचदेवा करेंगे। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में विजय नड्डा (संगठन मंत्री, विद्या भारती उत्तर क्षेत्र), डॉ. अमित आर्य तथा अंतरराष्ट्रीय सहभागिता के तहत श्रीलंका की सुमाणिमी रत्नायका भी शामिल होंगी, जिससे आयोजन को वैश्विक दृष्टिकोण मिलेगा। यह आयोजन विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संगठन और जनसंचार एवं मीडिया प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है, जबकि सहयोग विद्या भारती पूर्व छात्र परिषद का रहेगा। प्रो. पूनिया ने कहा कि यह पहल न केवल रोहित सरदाना की स्मृति को जीवित रखने का प्रयास है, बल्कि युवा पीढ़ी को जिम्मेदार, निष्पक्ष और जागरूक पत्रकारिता के लिए प्रेरित करने की दिशा में भी एक सार्थक कदम है। उन्होंने विद्यार्थियों, शिक्षकों और मीडिया से जुड़े सभी लोगों से कार्यक्रम में भाग लेने की अपील की है।

कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने गांव धांसू में गौशालाओं को 84 लाख 41 हजार रुपये से अधिक की राशि के चेक वितरित किए

चंडीगढ़। हरियाणा के लोक निर्माण एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री श्री रणबीर गंगवा ने आज हिसार के गांव धांसू में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न गौशालाओं को अनुदान राशि के चेक वितरित किए। इस मौके पर उन्होंने धांसू गोशाला में लगभग 17 लाख रुपये की लागत के शेड का लोकार्पण भी किया। कैबिनेट मंत्री श्री रणबीर गंगवा ने कहा कि हरियाणा सरकार गौवंश संरक्षण एवं संवर्धन के लिए निरंतर प्रयासरत है। सरकार की गौवंश संरक्षण एवं संवर्धन नीति के तहत गौशालाओं को आर्थिक सहायता प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसी कड़ी में आज गौशालाओं को 84 लाख 41 हजार 560 रुपये की राशि दी गई है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने गौशालाओं के बजट को बढ़ाकर 600 करोड़ रुपये वार्षिक कर दिया है। वर्ष 2014 से पूर्व यह बजट मात्र 40 करोड़ रुपये था। उन्होंने कहा कि गौधन भारतीय संस्कृति और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है। गौशालाओं के माध्यम से न केवल गौवंश की रक्षा हो रही है, बल्कि जैविक और प्राकृतिक खेती को भी बढ़ावा मिल रहा है। उन्होंने बताया कि गोबर और गौमूत्र से तैयार होने वाले जैविक खाद और कीटनाशक प्राकृतिक खेती के लिए अत्यंत उपयोगी हैं, जिससे भूमि की उर्वरता बढ़ती है और किसानों की लागत में कमी आती है। उन्होंने किसानों से आह्वान किया कि वे प्राकृतिक खेती को अपनाकर स्वास्थ्यवर्धक उत्पादन करें और पर्यावरण संरक्षण में अपनी भूमिका निभाएं। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री ने ग्राम पंचायत की ओर से रखी गई मांगो को जल्द पूरा करवाने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर जिला परिषद अध्यक्ष सोनू सिहाग डाटा, पार्षद ओपी मालिया, पूर्व चेयरमैन रणधीर धीरू व आसपास की गौशालाओं के प्रतिनिधि व गोभक्त उपस्थित रहे।

हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद् की निदेशक वर्षा खांगवाल ने राजकीय स्कूल का किया औचक निरीक्षण

चंडीगढ़। सरकारी विद्यालयों की वास्तविक स्थिति का जमीनी स्तर पर आकलन करने तथा विद्यार्थियों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद् की निदेशक, श्रीमती वर्षा खांगवाल ने पीएमश्री राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, सेक्टर-15, पंचकूला का औचक निरीक्षण किया। इस निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य शैक्षणिक गुणवत्ता के साथ-साथ विद्यार्थियों के सामाजिक-भावनात्मक विकास, जीवन कौशल तथा अनुभवात्मक अधिगम को बढ़ावा देना था। निरीक्षण के दौरान श्रीमती वर्षा खांगवाल ने विभिन्न कक्षाओं का सूक्ष्म एवं विस्तृत अवलोकन करते हुए पठन-पाठन प्रक्रिया का गहन निरीक्षण किया। उन्होंने छात्राओं से कक्षा स्तर व सामान्य ज्ञान के अनुरूप प्रश्न पूछे, जिन का छात्राओं ने उत्साह, आत्मविश्वास और सटीकता के साथ उत्तर दिया। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को पुरस्कृत कर उनका उत्साहवर्धन भी किया। छात्राओं की सक्रिय सहभागिता एवं सकारात्मक दृष्टिकोण पर उन्होंने प्रसन्नता एवं संतोष व्यक्त किया। राज्य परियोजना निदेशक द्वारा विद्यालय में लाइब्रेरी, स्वच्छता, पेयजल उपलब्धता तथा शौचालयों की स्थिति का भी निरीक्षण किया गया। श्रीमती वर्षा खांगवाल ने विद्यालय के प्रयासों की सराहना करते हुए निरंतर सुधार एवं नवाचार को अपनाने पर बल दिया, ताकि विद्यालय उत्कृष्टता के नए मानक स्थापित कर सके।

राज्य में स्व-गणना प्रक्रिया में करें भागीदारी, 30 अप्रैल तक कर सकते हैं ऑनलाइन पंजीकरण

चंडीगढ। प्रदेश में स्व-गणना प्रक्रिया कार्य जारी है जो 30 अप्रैल 2026 तक जारी रहेगा। जिसके तहत नागरिक आधिकारिक पोर्टल रीीूल्ल२४२.ॅङ्म५.ल्ल पर अपनी जनगणना संबंधी जानकारी स्वयं घर बैठे भर सकते हैं। नागरिक निरन्तर सरकार की इस डिजिटल पहल से जुड़ते हुए अपनी जनगणना संबंधी जानकारी स्वयं ऑनलाइन दर्ज कर रहे हैं। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि स्व-गणना के बाद 1 मई से 30 मई 2026 तक राज्य में घर-घर जाकर मकान सूचीकरण और सत्यापन का कार्य किया जाएगा। इस दौरान गणनाकर्मी नागरिकों द्वारा दी गई जानकारी का मिलान करेंगे। प्रवक्ता ने बताया कि स्व-गणना की सुविधा मोबाइल, टैबलेट या कंप्यूटर के जरिए कहीं से भी उपयोग की जा सकती है। नागरिकों को मोबाइल नंबर और ओटीपी के माध्यम से लॉगिन करना होगा। इसके बाद डिजिटल मानचित्र पर अपने घर का स्थान चिन्हित कर परिवार के सदस्यों, आवास की स्थिति और उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी भरनी होगी। प्रक्रिया पूरी होने पर एक यूनिक आईडी जारी की जाएगी, जिसका उपयोग सत्यापन के दौरान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि स्व-गणना प्रपत्र में लगभग 33 प्रश्न शामिल किए गए हैं, जिनमें परिवार के सदस्यों का विवरण, मकान का प्रकार, पेयजल, बिजली, स्वच्छता, शिक्षा और सामाजिक-आर्थिक स्थिति से संबंधित जानकारी ली जाएगी। इसके अलावा इस बार इंटरनेट, स्मार्टफोन, टीवी, रेडियो, कंप्यूटर/लैपटॉप और वाहन जैसी सुविधाओं से जुड़े सवाल भी शामिल किए गए हैं, ताकि जीवन स्तर और डिजिटल पहुंच का सटीक आकलन किया जा सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि नागरिकों द्वारा दी गई सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। इसका उपयोग केवल सांख्यिकीय विश्लेषण और विकास योजनाओं के निर्माण के लिए किया जाएगा। प्रवक्ता ने प्रदेश के सभी नागरिकों से अपील की है कि वे 30 अप्रैल तक स्व-गणना प्रक्रिया में भाग लेकर सही और पूर्ण जानकारी प्रदान करें, ताकि योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन और राज्य के समग्र विकास को गति मिल सके।

संपादकीय

आईसीयू मानकों पर सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक निदेर्श: स्वास्थ्य सेवा सुधार की दिशा में एक निर्णायक कदम

भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को लेकर बहस वर्षों से जारी है, किंतु इस बार सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐसा ऐतिहासिक कदम उठाया है जो देश के अस्पतालों में गहन चिकित्सा इकाइयों यानी आईसीयू की दशा को बदल सकता है। न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की खंडपीठ ने 20 अप्रैल 2026 को एक महत्वपूर्ण आदेश पारित करते हुए देश के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि वे आईसीयू के न्यूनतम मानकों को लागू करने के लिए एक यथार्थवादी और व्यावहारिक कार्य योजना तत्काल तैयार करें। न्यायालय ने इस पूरी प्रक्रिया को तीन सप्ताह के भीतर पूरा करने की समयसीमा भी निर्धारित की है। यह मामला मूलतः 2016 में निजी अस्पतालों में चिकित्सीय लापरवाही और आईसीयू तथा क्रिटिकल केयर यूनिट में एकरूप मानकों के अभाव से संबंधित शिकायत के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आया था। यद्यपि मूल अपील 2024 में बंद हो गई, परंतु न्यायालय ने देशभर में गहन चिकित्सा सेवाओं को मानकीकृत करने के व्यापक प्रश्न की निगरानी जारी रखना उचित समझा। इस निर्णय में न्यायालय की वह संवेदनशीलता झलकती है जो हर नागरिक के जीवन और स्वास्थ्य के अधिकार को संविधान के मूल अधिकारों से जोड़कर देखती है। न्यायालय ने इस प्रक्रिया की देखरेख के लिए एक मुख्य समिति का गठन पहले ही कर लिया था, जिसमें अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी, एमिकस क्यूरी करन भारिहोके और एम्स के डॉ. नितीश नाइक शामिल थे। इसके बाद परामर्श का दायरा बढ़ाते हुए देश के अग्रणी चिकित्सा विशेषज्ञों को भी इसमें शामिल किया गया, जिनमें मेदांता के अध्यक्ष डॉ. नरेश त्रेहान, नारायण हेल्थ के अध्यक्ष डॉ. देवी प्रसाद शेट्टी और इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलरी साइंसेज के निदेशक डॉ. शिव कुमार सरीन जैसे नाम शामिल हैं। इन विशेषज्ञों की सहमति से ₹गहन चिकित्सा सेवाओं के संगठन और वितरण के लिए दिशानिर्देश₹ शीर्षक से एक आधारभूत दस्तावेज तैयार किया गया है, जिसे न्यायालय ने आईसीयू के लिए न्यूनतम मानक ढाँचे के रूप में रिकॉर्ड पर लिया है। 20 अप्रैल की सुनवाई के दौरान विशेषज्ञ चिकित्सकों के दल ने न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर इन दिशानिर्देशों में शामिल किए जाने वाले सुझाव प्रस्तुत किए। न्यायालय ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को निर्देशित किया कि वह इन दिशानिर्देशों को सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को एक परामर्श के रूप में भेजे तथा अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर भी अपलोड करे। राज्यस्तरीय रिपोर्टें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को अग्रेषित की जाएंगी, जो उन्हें एमिकस क्यूरी और न्यायालय द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ दल के साथ साझा करेगा। तत्पश्चात केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें राज्यों के स्वास्थ्य सचिव, विशेषज्ञ दल, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल और एमिकस क्यूरी सम्मिलित होंगे। इस बैठक में एक अंतिम साझा मसौदा तैयार करके न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। न्यायालय के निर्देश केवल औपचारिक नहीं हैं, बल्कि उनमें एक सुस्पष्ट कार्यपद्धति भी निहित है। खंडपीठ ने कहा कि सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रधान अतिरिक्त मुख्य सचिव या सचिव एक सप्ताह के भीतर विशेषज्ञों की बैठक बुलाएं और पाँच मूलभूत आवश्यकताओं को प्राथमिकता के आधार पर चिह्नित करें। ये पाँच बिंदु जनशक्ति और उपकरण दोनों पहलुओं से संबंधित होंगे और इनमें केवल वही चीजें शामिल की जाएंगी जो आईसीयू संचालन के लिए ₹बिल्कुल आवश्यक और अनिवार्य₹ हों। इसके साथ ही न्यायालय ने यह भी कहा कि जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन के लिए एक स्पष्ट कार्यप्रणाली और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी निगरानी तंत्र भी विकसित किया जाए। सुनवाई के दौरान यह तथ्य भी उभरकर सामने आया कि आईसीयू में नर्सिंग स्टाफ की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे चौबीसों घंटे मरीजों के साथ रहते हैं। इस बात को गंभीरता से लेते हुए न्यायालय ने भारतीय नर्सिंग परिषद और पैरामेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को इस मामले में पक्षकार बनाया और उन्हें नोटिस जारी किया। उन्हें अगली सुनवाई तक यह बताना होगा कि वे आईसीयू परिस्थितियों को संभालने में सक्षम स्वास्थ्यकर्मी तैयार करने के लिए अपने पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण और शिक्षा को किस प्रकार मजबूत करेंगे। इस निर्देश का दूरगामी महत्व है क्योंकि देश में गहन देखभाल के क्षेत्र में प्रशिक्षित नर्सों की भारी कमी एक पुरानी और ज्वलंत समस्या रही है। विशेषज्ञों ने यह भी सुझाव दिया कि आईसीयू में विशेष उपकरणों को संचालित करने वाले कर्मियों को उचित प्रशिक्षण दिया जाए, चेकलिस्ट के रूप में मानक संचालन प्रक्रियाएं बनाई जाएं और मरीज की स्थिति के अनुसार निकटतम अस्पताल की पहचान करने में सहायता के लिए जीपीएस आधारित अस्पताल लोकेटर प्रणाली विकसित की जाए। ये सुझाव यह स्पष्ट करते हैं कि आधुनिक तकनीक को स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़कर ही हम एक सक्षम और संवेदनशील चिकित्सा तंत्र की स्थापना कर सकते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या इस बार न्यायालय के ये निर्देश कागजों से निकलकर धरातल पर उतर पाएंगे? भारत में न्यायिक सक्रियता का इतिहास बताता है कि ऐसे आदेश अक्सर राज्यों की प्रशासनिक सुस्ती और संसाधनों की कमी के कारण कार्यान्वयन की राह में अटक जाते हैं। परंतु इस बार न्यायालय ने तीन सप्ताह की कड़ी समयसीमा, अनिवार्य उपस्थिति और चरणबद्ध रिपोर्टिंग तंत्र के माध्यम से यह सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि यह प्रक्रिया केवल औपचारिकता न बने। 18 मई 2026 को इस मामले की अगली सुनवाई होगी, जिसमें सभी विशेषज्ञ या तो व्यक्तिगत रूप से अथवा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहेंगे। यह भी ध्यान देने योग्य है कि भारत जैसे विशाल और विविधताओं से भरे देश में हर राज्य की स्वास्थ्य संरचना, संसाधन और जनसंख्या भिन्न-भिन्न है। बड़े शहरों के बड़े अस्पतालों में आईसीयू की स्थिति भले ही कुछ बेहतर हो, किंतु दूरदराज के ग्रामीण अंचलों और छोटे जिलों में गहन चिकित्सा इकाइयों का अभाव या उनकी दयनीय दशा एक गंभीर वास्तविकता है। ऐसे में न्यायालय का यह कदम न केवल शहरी बल्कि ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों के मरीजों के लिए भी एक उम्मीद की किरण लेकर आया है। निष्कर्षतः सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्देश भारतीय स्वास्थ्य सेवाओं के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। यह केवल अस्पतालों में बेड और उपकरणों की संख्या बढ़ाने का मामला नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करने की दिशा में बढ़ाया गया कदम है जहाँ हर गंभीर रोगी को एकसमान, मानकीकृत और गुणवत्तापूर्ण गहन देखभाल मिल सके। अब यह राज्य सरकारों और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वे न्यायालय की भावना को समझते हुए इसे एक सच्चे जनस्वास्थ्य सुधार के रूप में लागू करें, न कि केवल रिपोर्ट दाखिल करने की खानापूर्ति के रूप में।

खेड़ा अकेले नहीं, जब कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व की बयानबाजी बनी विवाद का पर्याय!

डॉ. मयंक चतुर्वेदी (हि.स)

भारतीय लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका एक संतुलनकारी शक्ति के रूप में कार्य करना है। यह भूमिका तब और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है जब सत्ता पक्ष के निर्णयों पर सवाल उठाने की आवश्यकता होती है, लेकिन जब यह सवाल तथ्यों से परे जाकर आरोपों, अतिशयोक्ति और व्यक्तिगत हमलों में बदलने लगते हैं, तब लोकतांत्रिक विमर्श स्वभाविक है कि कमजोर पड़ता है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा से जुड़ा मामला भी कुछ ऐसा ही है, जोकि प्रवृत्ति की ओर इशारा करती है, जहां आखिरकार न्यायालय को हस्तक्षेप कर राजनीतिक बयानबाजी की सीमाएं तय करनी पड़ीं!

गौहाटी हाई कोर्ट द्वारा खेड़ा के बयान पर की गई टिप्पणी पूरे राजनीतिक संवाद के स्तर पर सवाल उठाने वाला संकेत माना जाए तो कुछ गलत न होगा। खेड़ा द्वारा हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी के खिलाफ लगाए गए आरोपों को न्यायालय ने गंभीरता से लिया और स्पष्ट किया कि किसी गैर-राजनीतिक व्यक्ति को राजनीतिक आरोपों में घसीटना अनुचित होने के साथ ही कानूनी दृष्टि से भी आपत्तिजनक है। वस्तुतः यह टिप्पणी इस बात का प्रमाण है कि अब न्यायपालिका राजनीतिक बयानबाजी को ह्यराजनीतिक भाषाह्न मानकर नजरअंदाज करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। पवन खेड़ा का यह तर्क कि उन्होंने सिर्फ ह्लसवालह्व उठाए थे, कोर्ट को संतुष्ट नहीं कर सका है। यह वही प्रवृत्ति है, जो पिछले कुछ वर्षों में कांग्रेस की राजनीति में बार-बार देखने को मिली है, जहां आरोपों को ह्लप्रश्नह्व का रूप देकर प्रस्तुत किया जाता है, ताकि कानूनी जवाबदेही से बचा जा सके। पर सच्चायी यही है कि कांग्रेस की इस रणनीति का प्रभाव जनता की धारणा पर पड़ता है और आम जनता भ्रमित होती है।

यदि इस घटना को व्यापक संदर्भ में देखें, तब यह भी समझ आता है कि पवन खेड़ा इस तरह के बयान देनेवालों में अकेले नहीं है। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व, विशेषकर राहुल गांधी के बयानों का इतिहास भी इसी तरह के विवादों से भरा पड़ा है। ह्लचौकीदार चोर हैह्व जैसे नारे ने राजनीतिक माहौल को गमार्या जरूर था, किंतु जब मामला अदालत तक पहुंचा, तो राहुल गांधी को स्पष्टीकरण देना पड़ा और खेद भी व्यक्त करना पड़ा। इसी प्रकार राफेल सौदे को लेकर लगाए गए आरोप भी लंबे समय तक चर्चा में रहे, किंतु उन्हें भी न्यायालय में साबित नहीं किया जा सका।

कहना होगा कि राहुल गांधी का ह्लमोदी सरनेमह्व वाला बयान भी इसी कड़ी का हिस्सा है, जिसने उन्हें मानहानि के मामले में सजा तक दिलाई। यह अलग बात है कि आगे इस मामले में उन्हें राहत मिल गई, किंतु इस पूरे प्रकरण ने यह तो स्पष्ट कर ही दिया कि राजनीतिक बयानबाजी की भी एक सीमा होती है, जिसे पार करने पर कानूनी परिणाम भुगतने पड़ते हैं।

इसी तरह से समय-समय पर देश के बाहर विदेशों में दिए गए बयानों को लेकर भी राहुल गांधी विवादों में रहे हैं। ब्रिटेन और अमेरिका में भारतीय लोकतंत्र पर उठाए गए उनके तमाम प्रश्नों ने राजनीतिक बहस को और तेज किया है। स्वभाविक है, एक नेता प्रतिपक्ष के इस तरह के बयानों ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर देश की छवि को प्रभावित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दूसरी ओर, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की बयानबाजी भी कम विवादास्पद नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना ह्लरावणह्व से करना या उन्हें ह्लजहरीलाह्व कहना, यहां तक कि आतंकवादी तक कह देना, फिर वो अलग बात है कि बाद में इसके लिए मांफी भी मांगी गई, किंतु ये सभी बयान निश्चित ही भारतीय राजनीतिक मयार्दा के स्तर पर गंभीर प्रश्न खड़े करते हैं?

यदि इन सभी घटनाओं को एक साथ रखा जाए, तो एक स्पष्ट पैटर्न उभरता है। कांग्रेस के नेता पहले तीखे और गंभीर आरोप लगाते हैं, फिर उन्हें राजनीतिक विमर्श में फैलाया जाता है और जब प्रमाण की मांग होती है, तो या तो पीछे हटना पड़ता है या मामला अदालत तक पहुंच जाता है। ऐसे में स्वभाविक है कि यहां न्यायपालिका की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। गुवाहाटी हाई कोर्ट की टिप्पणी इस बात का संकेत है कि लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता असीमित नहीं है। जब किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा दांव पर लगती है, विशेषकर वह व्यक्ति जो राजनीति में सक्रिय नहीं है, तब कानून हस्तक्षेप करता है। अदालत ने स्पष्ट किया कि आरोपों को साबित करना आवश्यक है, अन्यथा वे संभावित अपराध बन सकते हैं।

अब लगता है कि इस प्रकार के लगातार विवाद जैसे कांग्रेस की नियति बन गए हैं। । जब पार्टी के शीर्ष नेता ही बार-बार ऐसे बयान देते हैं, जिन पर न्यायालय सवाल उठाती है, तब फिर जनता के बीच भरोसा कम होना स्वाभाविक है। कहना होगा कि लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका सरकार की आलोचना करना होने के साथ ही एक मजबूत और विश्वसनीय विकल्प प्रस्तुत करना भी है। पवन खेड़ा का मामला आज याद दिला रहा है कि लोकतंत्र में शब्दों की जिम्मेदारी होती है। आरोप लगाना आसान है, लेकिन उन्हें साबित करना उतना ही कठिन और जब यह संतुलन बिगड़ता है, तो अदालत को हस्तक्षेप करना पड़ता है।

अतः कहना यही है कि आज कांग्रेस के सामने एक अवसर आत्ममंथन का है। यदि पार्टी इस संकेत को गंभीरता से लेती है और अपनी राजनीतिक शैली में सुधार करती है, तब जरूर वह अपनी खोती हुई विश्वसनीयता को वापस पा सकती है और यदि यह सिलसिला इसी तरह चलता रहा, तो न्यायालयों की सख्ती और जनता का अविश्वास दोनों ही बढ़ते जाएंगे। कहीं ऐसा न हो कि कांग्रेस एक अच्छा या बुरा विपक्ष छोड़ो, वह भविष्य में कुछ भी न रह जाए!

आज का राशिफल

मेषः आज विद्यार्थियों की पढ़ाई में खासकर नए विषयों के प्रति रुचि बढ़ेगी। परिवार के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा। आपकी वाणी और व्यक्तित्व से लोग प्रभावित होंगे। सोशल मीडिया पर आपकी सक्रियता बढ़ सकती है। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें। *(सिटी दर्पण)*

वृषभः दिनचर्या को व्यवस्थित रखना आपके लिए जरूरी रहेगा। नया वाहन खरीदने का विचार मन में आ सकता है। काम का तनाव घर तक न लाएं। करीबी लोगों से भी सावधानी बरतें, क्योंकि भरोसे में धोखा मिल सकता है। प्रेमी के साथ घूमने-फिरने की योजना बन सकती है। *(सिटी दर्पण)*

मिथुनः युवाओं को करियर में अच्छे अवसर मिल सकते हैं। राजनीति या सार्वजनिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को सम्मान मिलेगा। दांपत्य जीवन सुखद रहेगा। बुद्धिमान लोगों के बीच आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अपने फैसलों पर भरोसा रखें, ज्यादा सलाह लेने से भ्रम हो सकता है। *(सिटी दर्पण)*

कर्कः विद्यार्थी अपने भविष्य को लेकर चिंतित रह सकते हैं। घर में मेहमानों का आगमन संभव है। दिन की शुरूआत थोड़ी धीमी रह सकती है। पड़ोसियों के साथ संबंध बेहतर होंगे। संतान की प्रगति से मन प्रसन्न रहेगा। *(सिटी दर्पण)*

सिंहः व्यापार में लाभ के नए अवसर मिलेंगे। पैतृक संपत्ति मिलने के संकेत हैं। कमीशन या डील से जुड़े कामों में फायदा होगा। रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। इंटरव्यू या प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलने के योग हैं। *(सिटी दर्पण)*

कन्याः अधिक आत्मविश्वास से बचें, क्योंकि इससे नुकसान हो सकता है। खानपान में लापरवाही से स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। किसी परिजन की तबीयत को लेकर चिंता रहेगी। विदेश से जुड़े कार्यों में कुछ बाधाएं आ सकती हैं। नशे से दूर रहें और योग-प्राणायाम अपनाएं। *(सिटी दर्पण)*

तुलाः स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आप दूसरों की मदद करने में रुचि लेंगे। अधूरे कार्यों को पूरा करने का दबाव बना रह सकता है। मेडिकल या हेल्थ सेक्टर से जुड़े लोगों की आय बढ़ सकती है। रियल एस्टेट से लाभ मिलने के संकेत हैं। कार्यस्थल पर आपकी प्रतिष्ठा मजबूत होगी। *(सिटी दर्पण)*

वृश्चिकः आपको अपने पुराने परिश्रम का अच्छा फल मिलेगा। माता-पिता का सहयोग और मार्गदर्शन प्राप्त होगा। संतान को करियर में सफलता मिलने की संभावना है। लंबे समय से रुके काम अब शुरू हो सकते हैं। मनोरंजन से जुड़ी चीजों में कुछ परेशानी आ सकती है। *(सिटी दर्पण)*

धनुः आज आपका नजरिया सकारात्मक रहेगा, जिससे हर कार्य में सफलता मिलने के योग हैं। बिना मांगे सलाह देने से बचें। अधिकारी वर्ग आपके विचारों को महत्व देगा। जीवनसाथी से किया वादा पूरा कर सकते हैं। पुराने कर्ज को चुकाने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे। *(सिटी दर्पण)*

मकरः दिनचर्या में ढिलाई न बरतें। अधिक भागदौड़ के कारण थकान या पैरों में दर्द हो सकता है। घर में अकेलापन महसूस हो सकता है। गर्मी से बचाव करें और पर्याप्त पानी पिएं। दूसरों पर दबाव डालने से बचें। शाम के समय घूमने का प्लान बन सकता है। *(सिटी दर्पण)*

कुंभः व्यापार में उम्मीद से ज्यादा लाभ मिलने की संभावना है। आपके कार्य समय पर पूरे होंगे। किसी बड़े प्रोजेक्ट में निवेश कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा। अविवाहित लोगों के विवाह के योग बन सकते हैं। प्रॉपर्टी से लाभ मिलने के संकेत हैं। *(सिटी दर्पण)*

मीनः परिवार के साथ मधुर व्यवहार बनाए रखें। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को सफलता मिल सकती है। ससुराल पक्ष में आपका सम्मान बढ़ेगा। योजनाओं को सही तरीके से लागू करने में सफल रहेंगे। दोस्तों की मदद करने में आगे रहेंगे। कार्य करने के तरीके में सुधार लाने की कोशिश करेंगे। *(सिटी दर्पण)*

पोषण निगरानी ऐप: कुपोषण के समाधान के लिए डेटा का उपयोग

प्रो. लिंडसे जैक्स (हि.स)

हममें से कई लोग अपने डॉक्टरों को इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड में जानकारी दर्ज करते हुए देखते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये डेटा समय के साथ हमारे स्वास्थ्य की निगरानी करने में मदद करेंगे, जोखिमों की शुरूआत में ही पहचान कर लेंगे और समय पर कार्रवाई को निर्देशित करेंगे। डिजिटल प्रणालियाँ केवल डेटा संग्रह के कारण ही नहीं, बल्कि जानकारी को निर्णय और बेहतर देखभाल में बदलने में मदद करने की वजह से सबसे बेहतर काम करती हैं।

महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा 2021 में लॉन्च किए जाने के बाद, पोषण निगरानी ऐप ने पोषण सेवा अदायगी डेटा को अधिक कार्रवाई-योग्य बनाने का प्रयास किया है। इसका उद्देश्य केवल डिजिटलीकरण करना नहीं, बल्कि बाल विकास और पोषण सेवाओं को दर्ज करने और समीक्षा करने में अधिक गंभीरता और निरंतरता लाना है।

पोषण निगरानी में नियमित रूप से एकत्र किए गए वृद्धि डेटा को अंतिम सिरे पर खड़े व्यक्ति के लिए सार्थक निर्णयों में बदलने की क्षमता है। मासिक वृद्धि निगरानी—यदि सही ढंग से मापी जाए और लगातार रिकॉर्ड की जाए—तो जोखिम के शुरूआती संकेत प्रदान कर सकती है। एक एकल, निरंतर मौजूद इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, वृद्धि रुझानों को पूरक पोषण उपायों से जोड़ने में मदद कर सकता है, जैसे घर ले जाने वाला राशन, देखभाल करने वालों का परामर्श और गंभीर कुपोषण से पीड़ित बच्चों को स्वास्थ्य केंद्रों में रेफर करना आदि।

इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए, हमें डैशबोर्ड से निर्णय की ओर और गणना से देखभाल की ओर बदलाव करने की आवश्यकता है। अंतर्निहित संकेत, सरल चेकलिस्ट और चेतावनी; आंगनवाड़ी कार्यकताओं को कमजोर या गंभीर कुपोषण के शिकार बच्चों के लिए बाद की कार्रवाई करने में मदद कर सकती है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा आरसीएच 2.0 पोर्टल के डेटा के साथ एकीकरण, समन्वय की साथ की गयी घर की यात्रा के जरिये रेफरल फॉलो-अप को और भी मजबूत कर सकता है।

वर्तमान में, एकत्रित वृद्धि डेटा एक महत्वपूर्ण शुरूआती बिंदु प्रदान करता है। मापन प्रथाओं और प्रणाली समर्थन में सुधारों के साथ, यह समय पर निर्णय लेने में भरोसेमंद जानकारी प्रदान कर सकता है। सटीक निर्णय मूलभूत चीजों को ठीक करने पर निर्भर करते हैं—भरोसेमंद मापन, सही तकनीकें और कार्यात्मक उपकरण। यदि किसी बच्चे की ऊँचाई या वजन एक महीने में असामान्य रूप से बदलता है, तो प्रणाली को सत्यापन या पुनः मापन का संकेत देना चाहिए। ऐप में शामिल छोटे माइक्रो-वीडियो देखभाल के स्थल पर वजन पैमाने और लंबाई बोर्ड के सही उपयोग को सुदृढ़ कर सकते हैं। समान रूप से महत्वपूर्ण यह सुनिश्चित करना भी है कि प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र में माप-संकेत वाले और कार्यात्मक उपकरण मौजूद हों। ये मूलभूत बातें वृद्धि निगरानी डेटा की उपयोगिता को मजबूत करने के लिए आवश्यक हैं।

पोषण निगरानी डेटा का विश्लेषण डैशबोर्ड से निर्णय लेने की प्रक्रिया में बदलाव का भी समर्थन कर सकता है। सबसे पहले, हमें पता होना चाहिए कि कुपोषण की सबसे अधिक संभावना कब होती है—किस उम्र में और वर्ष के किन महीनों में। क्या यह जन्म के समय होता है? या क्या 0 से 3 महीने या 3 से 6 महीने महत्वपूर्ण हैं, जब माताओं को केवल स्तनपान कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है? या यह 6 महीने से 1 साल के दौरान होता है, जब पर्याप्त, उचित और सुरक्षित पूरक आहार की आवश्यकता होती है?

पोषण निगरानी डेटा के विश्लेषण से हमें उन बच्चों के बारे में और ज्यादा जानने में भी मदद मिल सकती है जो कुपोषण से ठीक हो जाते हैं। क्या कुछ खास ज़िलों के बच्चों में ठीक होने की संभावना ज्यादा होती है? क्या खरीफ फसल की कटाई वाले महीनों के दौरान बच्चों के ठीक होने की संभावना अधिक होती है? इसी तरह, ऐसे विश्लेषण हमें उन बच्चों के बारे में और भी बहुत कुछ बता सकते हैं जो अपने पूरे बचपन के दौरान बार-बार या लगातार कुपोषण का शिकार होते रहते हैं। क्या ये वे बच्चे हैं, जो जन्म के समय से ही कुपोषण के शिकार थे और बाद में भी पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाए? क्या ये वे बच्चे हैं, जिन्हें घर ले जाने वाला राशन नियमित रूप से नहीं मिल रहा है? इस तरह की जानकारी होने पर, स्थानीय स्तर पर पोषण सेवा अदायगी को बेहतर बनाया जा सकता है।

डेटा पर भरोसा बढ़ाना, अग्रिम पंक्ति के कार्यकताओं के कार्यभार में कमी लाने के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। प्रणाली में विश्वास बढ़ने के साथ, अधिक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्राथमिक रिकॉर्ड के रूप में ऐप का उपयोग करने की शुरूआत कर रहे हैं। हालांकि, कई जगहों पर, संचार-संपर्क की समस्याओं या अनुपालन आवश्यकताओं के कारण डिजिटल प्रविष्टि के साथ-साथ कागजी रजिस्टर भी रखे जाते हैं। ऑफलाइन कार्यक्षमता को मजबूत करना, डेटा की विश्वसनीयता में सुधार करना और डिजिटल-प्रथम कार्यप्रवाह पर स्पष्टता प्रदान करना, सेवा स्थल पर डेटा प्रविष्टि की ओर बदलाव को गति देने और दोहरी रिपोर्टिंग की आवश्यकता को कम करने में मदद कर सकता है। प्रणाली को परिष्कृत करने में अग्रिम पंक्ति के कार्यकताओं को शामिल करने से यह सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है कि ऐप उनके काम में सहायक हो।

पोषण निगरानी ऐप समय पर और सोच-समझकर फैसले लेने में मदद करने वाला एक भरोसेमंद उपकरण है। इसकी असली ताकत जोखिम की जल्द पहचान करने, तेजी से बाद की कार्रवाई करने और पोषण सेवाओं के बेहतर तालमेल को सक्षम बनाने में है। आखिरी छोर की जमीनी हकीकतों को ध्यान में रखकर बनाया गया और डेटा की गुणवत्ता व इसके इस्तेमाल में हुए लगातार सुधारों से और मजबूत बनाया गया पोषण निगरानी ऐप, सिर्फ. एक निगरानी उपकरण ही नहीं, बल्कि पोषण सेवा अदायगी को मजबूत बनाने का एक सार्थक उपाय भी है।

(लेखिका एडिनबर्ग विश्वविद्यालय में वैश्विक स्वास्थ्य और पोषण की प्रोफेसर हैं।)

समुद्र की गहराइयों में भारत की शक्ति

डॉ. सत्यवान सौरभ (हि.स)

आधुनिक युग में युद्ध की प्रकृति ने पारंपरिक सीमाओं को पूरी तरह पार कर लिया है। अब यह केवल टैंकों, विमानों या सैनिकों तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि एक बहुआयामी, जटिल और तकनीक-प्रधान प्रक्रिया बन चुका है, जिसमें ड्रोन, साइबर हमले, अंतरिक्ष-आधारित निगरानी प्रणालियाँ, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और हाइपरसोनिक मिसाइलें एक साथ कार्य करती हैं। इस परिवर्तित परिदृश्य में युद्ध किसी एक भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता, बल्कि समुद्र, आकाश, भूमि और साइबर स्पेस के बीच निरंतर समन्वय के रूप में संचालित होता है। ऐसे वातावरण में भारत जैसी उभरती क्षेत्रीय एवं वैश्विक शक्ति के लिए अपनी सुरक्षा रणनीति को पुनर्परिभाषित करना अनिवार्य हो गया है। विशेष रूप से समुद्री क्षेत्र में परमाणु प्रतिरोधक क्षमता का विकास अब विकल्प नहीं, बल्कि रणनीतिक आवश्यकता बन चुका है, क्योंकि यह न केवल भारत की रक्षा क्षमता को सुदृढ़ करता है, बल्कि उसकी वैश्विक सामरिक स्थिति को भी मजबूत बनाता है।

हिंद महासागर क्षेत्र की बदलती भू-राजनीतिक परिस्थितियाँ इस आवश्यकता को और स्पष्ट करती हैं। यह क्षेत्र केवल सामरिक दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि वैश्विक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति का एक प्रमुख मार्ग भी है। विश्व के अधिकांश तेल परिवहन और व्यापारिक जहाज इसी मार्ग से गुजरते हैं, और भारत की ऊर्जा सुरक्षा भी काफी हद तक इसी पर निर्भर करती है। ऐसे में इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अस्थिरता या बाहरी हस्तक्षेप भारत की आर्थिक और रणनीतिक स्थिरता को प्रभावित कर सकता है। चीन की बढ़ती समुद्री उपस्थिति, बंदरगाहों के विकास की उसकी नीति तथा क्षेत्र में उसकी सैन्य गतिविधियाँ भारत के लिए दीर्घकालिक चुनौती प्रस्तुत करती हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान की परमाणु क्षमताओं और उसकी नौसैनिक शक्ति में हो रही वृद्धि भी चिंता का विषय है। इन परिस्थितियों में भारत के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह अपनी समुद्री सुरक्षा को केवल पारंपरिक साधनों तक सीमित न रखे, बल्कि उसे परमाणु प्रतिरोधक क्षमता से भी सशक्त बनाए।

समुद्री परमाणु प्रतिरोधक क्षमता का मूल उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी संभावित विरोधी को यह स्पष्ट संदेश मिले कि यदि वह परमाणु हमला करता है, तो उसे समान या उससे अधिक प्रभावी जवाब का सामना करना पड़ेगा। यही सिद्धांत ह्यविश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोधह्न की अवधारणा को जन्म देता है, जिसके तहत कोई भी देश अपनी सुरक्षा के लिए उतनी ही परमाणु क्षमता विकसित करता है जितनी संभावित खतरे को रोकने के लिए आवश्यक हो। भारत की ह्यनो फर्स्ट यूजह्न नीति भी इसी सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि भारत पहले परमाणु हथियार का उपयोग नहीं करेगा, लेकिन यदि उस पर हमला होता है, तो वह पूरी क्षमता के साथ जवाब देगा। इस नीति की विश्वसनीयता तभी संभव है जब भारत के पास ऐसी क्षमता हो जो प्रथम हमले के बाद भी सुरक्षित रहे और प्रभावी जवाब दे सके। यही वह स्थान है जहाँ समुद्री परमाणु प्रतिरोधक क्षमता, विशेष रूप से परमाणु-संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियाँ, अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

पनडुब्बियाँ इस संदर्भ में सबसे प्रभावी माध्यम मानी जाती हैं, क्योंकि वे समुद्र की गहराइयों में लंबे समय तक गुप्त रूप से रह सकती हैं और उनका पता लगाना अत्यंत कठिन होता है। यही उनकी 'सेकंड स्ट्राइक क्षमता' को सुदृढ़ बनाता है। अर्थात यदि देश के स्थलीय या हवाई ठिकाने नष्ट भी हो जाएँ, तो समुद्र में मौजूद पनडुब्बियाँ जवाबी हमला करने में सक्षम रहती हैं। यह क्षमता किसी भी विरोधी के लिए एक मजबूत निरोधक तत्व बन जाती है, क्योंकि उसे यह ज्ञात होता है कि वह पूर्णतः सुरक्षित नहीं है। इस प्रकार, समुद्री परमाणु प्रतिरोधक क्षमता केवल युद्ध की स्थिति में ही नहीं, बल्कि शांति बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

भारत ने इस दिशा में पिछले कुछ वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति की है। स्वदेशी तकनीक पर आधारित परमाणु-संचालित पनडुब्बियों का विकास इस बात का संकेत है कि भारत अब अपनी रक्षा आवश्यकताओं के लिए बाहरी स्त्रोतों पर निर्भर रहने के बजाय आत्मनिर्भर बनने की दिशा में अग्रसर है। इन पनडुब्बियों में लंबी दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों की क्षमता होती है, जो उन्हें रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण बनाती है। इसके साथ ही, आधुनिक तकनीकों जैसे मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टार्गेटेबल री-एंट्री व्हीकल का उपयोग उन्हें और अधिक प्रभावी बनाता है, जिससे एक ही मिसाइल से अनेक लक्ष्यों को साधा जा सकता है। यह क्षमता न केवल सैन्य दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि विरोधी के लिए रणनीतिक चुनौती भी प्रस्तुत करती है।

हालाँकि, केवल पनडुब्बियों का निर्माण ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनके संचालन, रखरखाव और सुरक्षा के लिए भी एक सुदृढ़ तंत्र की आवश्यकता होती है। परमाणु पनडुब्बियाँ अत्यंत जटिल तकनीकी प्रणालियों पर आधारित होती हैं और उनका संचालन उच्च स्तर की विशेषज्ञता तथा प्रशिक्षण की माँग करता है। इसके अतिरिक्त, साइबर सुरक्षा भी एक महत्वपूर्ण पहलू बन चुकी है, क्योंकि आधुनिक युद्ध में साइबर हमले किसी भी सैन्य प्रणाली को निष्क्रिय कर सकते हैं। यदि पनडुब्बियों के संचार तंत्र या नियंत्रण प्रणाली को हैक कर लिया जाए, तो यह गंभीर खतरा बन सकता है। इसी प्रकार, अंतरिक्ष आधारित निगरानी प्रणालियाँ भी पनडुब्बियों की गोपनीयता को चुनौती दे सकती हैं, जिससे उनकी रणनीतिक उपयोगिता प्रभावित हो सकती है।

भविष्य की रणनीति में इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखना आवश्यक होगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम संचार और उन्नत सेंसर तकनीक का उपयोग पनडुब्बियों की क्षमताओं को और अधिक सुदृढ़ कर सकता है। क्वांटम संचार विशेष रूप से सुरक्षित संचार का एक नया माध्यम प्रदान कर सकता है, जिससे दुश्मन द्वारा संचार को बाधित या अवरोधित करना लगभग असंभव हो जाएगा। साथ ही, उन्नत सेंसर और निगरानी प्रणालियाँ पनडुब्बियों को अधिक सटीक, प्रभावी और सुरक्षित बना सकती हैं।

अंतरराष्ट्रीय सहयोग भी इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, किंतु अंततः किसी भी देश की सुरक्षा उसकी अपनी क्षमताओं पर ही निर्भर करती है। भारत विभिन्न वैश्विक मंचों पर सक्रिय है और समुद्री सुरक्षा के लिए सहयोग को प्रोत्साहित करता है, परंतु उसे अपनी स्वदेशी क्षमताओं को भी समान रूप से सुदृढ़ करना होगा। इसके लिए अनुसंधान एवं विकास में निवेश बढ़ाना, वैज्ञानिक संस्थानों को सशक्त बनाना तथा रक्षा क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देना आवश्यक है।

समुद्री परमाणु प्रतिरोधक क्षमता का विकास केवल सैन्य शक्ति का प्रदर्शन नहीं, बल्कि एक संतुलित और जिम्मेदार रणनीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य शांति और स्थिरता बनाए रखना है। एक मजबूत प्रतिरोधक क्षमता संभावित संघर्षों को रोकने में सहायक होती है और यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी देश आक्रामक कदम उठाने से पहले उसके परिणामों पर गंभीरता से विचार करे। इस प्रकार, यह क्षमता युद्ध को रोकने का एक प्रभावी माध्यम बन जाती है।

आधुनिक युग में भारत की समुद्री परमाणु प्रतिरोधक क्षमता उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति का एक केंद्रीय तत्व बन चुकी है। यह न केवल भारत को बाहरी खतरों से सुरक्षित रखती है, बल्कि उसे वैश्विक मंच पर एक जिम्मेदार और सक्षम शक्ति के रूप में स्थापित भी करती है। बदलती वैश्विक परिस्थितियों और उभरती चुनौतियों के बीच, भारत के लिए यह आवश्यक है कि वह अपनी रणनीति को निरंतर अद्यतन करता रहे और नई तकनीकों तथा विचारों को अपनाकर अपनी सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ बनाए। इस दिशा में उठाए गए कदम न केवल वर्तमान के लिए, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी एक सुरक्षित और स्थिर वातावरण सुनिश्चित करेंगे।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने डिप्टी कमिश्नरों को समय सीमा से पहले बाढ़ सुरक्षा कार्य पूरे करने के निर्देश दिए; कहा–सरकार जनता के साथ मजबूती से खड़ी है

बारिश से पहले ड्रेनों और संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की तुरंत सफाई सुनिश्चित की जाए: भगवंत सिंह मान

सिटी दर्पण संवाददाता

चंडीगढ़

आगामी मानसून सीजन के मद्देनजर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज डिप्टी कमिश्नरों को बाढ़ सुरक्षा से जुड़े सभी कार्य समय पर पूरा करने के निर्देश दिए और किसी भी तरह की लापरवाही पर व्यक्तिगत जवाबदेही तय करने की चेतावनी दी। एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने नालों और संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की तुरंत सफाई, गाद निकालने, प्रदूषण नियंत्रण उपायों को तेज करने और लंबित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के निर्देश दिए, ताकि बारिश से पहले सभी प्रबंध पूरे हो सकें।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान, जिनके साथ राज्यसभा सदस्य संत बलबीर सिंह सीचेवाल भी मौजूद थे, ने पूरे पंजाब में बाढ़ सुरक्षा कार्यों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए मास्टर प्लान तैयार करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ड्रेनों और नदियों की योजना सिंचाई विभाग के इंजीनियरों के साथ समन्वय करके तैयार की जानी चाहिए, ताकि नियमित रूप से डी-सिल्टिंग, सफाई और मजबूती सुनिश्चित की जा सके।

उन्होंने जोर देकर कहा कि इससे मानसून के दौरान लोगों को बाढ़ के खतरे से बचाने में मदद मिलेगी और हर अधिकारी इस कार्य के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा। उन्होंने गिद्दड़पिंडी रेलवे पुल समेत अन्य संभावित बाढ़ स्थलों की शीघ्र सफाई के निर्देश दिए, ताकि किसी भी आपात स्थिति से बचा जा सके।

बुड्ढा नाले की सफाई के बारे में मुख्यमंत्री ने बताया कि पवित्र बुड्ढा नाले के पानी को लुधियाना शहर के शुरूआती बिंदु तक साफ कर दिया गया है और आगे का कार्य जारी है। उन्होंने डेयरियों से नाले में जाने वाले गोबर की सख्ती से जांच करने और नगर निगम द्वारा उसके उचित निस्तारण को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि हैबोवाल में सीबीजी प्लांट को जल्द चालू किया जाए और ताजपुर में प्रस्तावित प्लांट के लिए 2.5 एकड़ भूमि आवंटन का प्रस्ताव एक सप्ताह के भीतर अंतिम रूप दिया जाए। औद्योगिक गंदे पानी के उचित उपचार और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए।

पानी के प्रवाह और प्रदूषण नियंत्रण के संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि चिट्टी वेईं में 200 क्योसिक पानी छोड़ने के लिए सिम्बली में रेगुलेटर चालू किया जाए। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर पुलों में तकनीकी सुधार और काला संघियां ड्रेन में प्रदूषण कम करने के लिए बिस्त दोआब नहर से 100 क्योसिक पानी छोड़े जाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने आगे कहा कि स्टोन लायनिंग का कार्य पूरा हो गया है।

मुख्यमंत्री ने डेयरी अपशिष्ट को नालों में डालने पर सख्ती से रोक लगाने की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि इस संबंध में जिम्मेदारी तय की जाएगी। सतलुज नदी पर धुसी बांध सड़क परियोजना का मामला केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री के समक्ष उठाया जाएगा, जिसे 117.75 करोड़ की लागत के साथ नाबार्ड के सहयोग से पूरा किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर जानकारी देते हुए कहा कि लुधियाना के बुड्ढा नाला, काला संघियां ड्रेन और सतलुज के धुसी बांध की सफाई को लेकर संत बलबीर सिंह सीचेवाल की हाजरी में जालंधर और लुधियाना के उपायुक्तों के साथ विशेष बैठक की गई है।

उन्होंने कहा कि अधिकारियों को सतलुज और अन्य मौसमी नदियों के कमजोर बांधों को मजबूत करने तथा बुड्ढा नाले के लिए एसटीपी परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। आने वाले दिनों में महत्वपूर्ण सुधार दिखाई देंगे और सरकार जनता के साथ मजबूती से खड़ी है।

सरकार द्वारा बीटी हाइब्रिड नरमा और देसी कपास के बीजों पर 33 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी; खरीफ के लिए 1.25 लाख हेक्टेयर का लक्ष्य तय: खुड्डियां

सिटी दर्पण संवाददाता

चंडीगढ़

राज्य में फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने और नरमा क्षेत्र का विस्तार करने की दिशा में अहम कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री स भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना द्वारा प्रमाणित बीटी कॉटन हाइब्रिड और देसी कपास के बीजों पर 33 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

इस संबंध में जानकारी देते हुए पंजाब के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री स गुरमीत सिंह खुड्डियां ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा 87 अनुमोदित बीटी कॉटन हाइब्रिड और देसी कपास की चार किस्में–एल.डी.1019, एल.डी.949, एफ.डी.के.124 और पी.बी.डी.88–में से किसी भी किस्म का चयन करने वाले किसानों को बीज लागत का लगभग

एक-तिहाई हिस्सा सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य के किसानों ने इस सब्सिडी मॉडल को सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। पिछले खरीफ सीजन में नरमा की खेती के तहत क्षेत्र में 19 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई, जिससे यह क्षेत्र खरीफ 2024 के 1 लाख हेक्टेयर से बढ़कर खरीफ 2025 में 1.19 लाख हेक्टेयर हो गया। उन्होंने आगे बताया कि खरीफ 2026 के लिए 1.25 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को नरमा खेती के अंतर्गत लाने का लक्ष्य रखा गया है।

कपास को ‘सफेद सोना’ बताते हुए कृषि मंत्री ने किसानों से अधिक पानी की खपत करने वाली धान की फसल के स्थान पर वैकल्पिक फसलें अपनाने की अपील की। उन्होंने बताया कि सब्सिडी का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन पोर्टल 20 अप्रैल से खोल दिया गया है।

उन्होंने किसानों से आग्रह किया कि वे केवल पंजीकृत डीलरों से प्रमाणित बीज खरीदें और आवेदन करते समय पक्का बिल अपलोड करें। सत्यापन के बाद 33 प्रतिशत सब्सिडी सीधे लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में भेज दी जाएगी।

यह पहल किसानों को वित्तीय राहत प्रदान करने के साथ-साथ अन्य लाभ भी देगी। इससे किसानों को वैज्ञानिक रूप से अनुशंसित, उच्च उत्पादकता वाली नरमा और कपास की किस्में अपनाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने कहा कि देसी कपास और पीएयू-प्रमाणित बीटी हाइब्रिड बीजों पर सब्सिडी से पंजाब की पारंपरिक कपास पट्टी को पुनर्जीवित करने में मदद मिलेगी।

मंत्री ने कहा कि इस सब्सिडी योजना से लागत में कमी आएगी और विशेष रूप से मालवा क्षेत्र में नरमा खेती का और विस्तार होने की उम्मीद है। उन्होंने सभी मुख्य कृषि अधिकारियों को व्यापक जागरूकता अभियान चलाने और प्रत्येक पात्र किसान के लिए ऑनलाइन पोर्टल तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि कोई भी किसान जानकारी या डिजिटल पहुंच की कमी के कारण इस योजना के लाभ से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराकर राज्य उत्पादकता और लाभ दोनों में वृद्धि सुनिश्चित करेगा तथा सभी कपास उत्पादकों से समय रहते पोर्टल पर आवेदन कर इस योजना का अधिकतम लाभ उठाने की अपील की।

श्री गुरु तेग बहादुर गुरुद्वारा साहिब, कोटकपूरा की प्रबंधक कमेटी और संगत ने स्पीकर संधवां का सम्मान किया

सिटी दर्पण संवाददाता

चंडीगढ़

पंजाब विधानसभा द्वारा पारित ‘जगत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) विधेयक 2026’ अब कानून बन चुका है, जिससे समूची सिख संगत में खुशी और संतोष की लहर है। यह कानून श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी जैसी घटनाओं को रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस ऐतिहासिक निर्णय के उपलक्ष्य में पूरे राज्य में विभिन्न स्थानों पर धन्यवाद समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में श्री गुरु तेग बहादुर गुरुद्वारा साहिब में प्रबंधक कमेटी और संगत द्वारा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का आभार व्यक्त किया गया तथा पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवां का विशेष रूप से सम्मान किया गया। इस अवसर पर संबोधित करते हुए स्पीकर संधवां ने कहा कि पंजाब सरकार धार्मिक मयार्दाओं और लोगों की भावनाओं की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और यह कानून बेअदबी जैसी घटनाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करेगा। उन्होंने कहा कि दोषियों को कानून के अनुसार कड़ी सजा दी जाएगी। स्पीकर ने गुरुद्वारा साहिब में उपस्थित संगत का धन्यवाद करते हुए कहा कि सरकार भविष्य में भी राज्य के सभी धार्मिक स्थलों की सुरक्षा, सम्मान और पवित्रता बनाए रखने के लिए हर संभव कदम उठाती रहेगी।

4.90 लाख से अधिक किसानों के खातों में 15,871.51 करोड़ रुपये की अदायगी: लाल चंद कटारूचक

सिटी दर्पण संवाददाता

चंडीगढ़

निर्बाध खरीद सीजन के अपने वादे को पूरा करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली राज्य सरकार पूरी फसल की खरीद और किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए त्वरित कार्रवाई कर रही है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री लाल चंद कटारूचक ने जानकारी देते हुए बताया कि अब तक 4,90,260 (4.90 लाख) किसानों को 15,871.51 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। आवक के संदर्भ में, राज्य भर की मंडियों में 87,89,802.82 मीट्रिक टन गेहूं पहुंच चुका है, जिसमें से कल देर शाम तक 83,94,114 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की जा चुकी है। उन्होंने यह भी बताया कि लिफटिंग की प्रकिया में भी तेजी देखने को मिल रही है। खरीद के मामले में जिला पटियाला अग्रणी है,

जहां कुल 7,83,749.85 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया है। संगरूर जिला 7,24,988.5 मीट्रिक टन के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि फिरोजपुर 5,95,924.35 मीट्रिक टन खरीद के साथ तीसरे स्थान पर है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री लाल चंद कटारूचक के मार्गदर्शन में विभाग द्वारा 122 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद के लिए समुचित प्रबंध किए गए हैं। इसके साथ ही मंडियों में साफ-सफाई और स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है।

छोटे और मध्यम वर्ग के किसानों के लिए अत्यंत लाभकारी साबित हो रही है एआईएफ योजना : मोहिंदर भगत

सिटी दर्पण संवाददाता

चंडीगढ़

पंजाब के बागवानी मंत्री मोहिंदर भगत ने बताया कि कृषि अवसंरचना फंड (एआईएफ) योजना छोटे और मध्यम वर्ग के किसानों के लिए बहुत लाभकारी साबित हो रही है। इस योजना के तहत किसान कृषि अवसंरचना को मजबूत करने के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

- योजना का लाभ लेने के लिए जरूरतमंद किसान नोडल एजेंसी बागवानी विभाग से कर सकते हैं संपर्क
- अब तक एआईएफ योजना के तहत 34,265 परियोजनाओं को मिली मंजूरी

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार किसानों की आय बढ़ाने और कृषि को लाभकारी व्यवसाय बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि एआईएफ योजना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मंत्री ने बताया कि एआईएफ योजना के तहत कोल्ड स्टोरेज, गोदाम, ग्रेडिंग और पैकिंग यूनिट, प्रोसेसिंग सेंटर और अन्य कृषि सुविधाओं की स्थापना को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इससे किसानों को अपनी उपज का बेहतर मूल्य मिल रहा है और फसलों के नुकसान में भी कमी आ रही है। उन्होंने कहा कि 31 मार्च 2026 तक के आंकड़ों के अनुसार राज्य में एआईएफ योजना के तहत 34,265 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। इन परियोजनाओं के लिए

विभिन्न वित्तीय संस्थानों द्वारा 7,991 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 7,496 करोड़ रुपये लाभार्थियों को जारी किए जा चुके हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि पंजाब का बागवानी विभाग इस योजना को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है और राज्य का कोई भी किसान अपने नजदीकी बागवानी कार्यालय में जाकर विभाग के अधिकारियों से संपर्क कर इस योजना का लाभ उठा सकता है।

पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय में श्री गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन

सिटी दर्पण संवाददाता

बठिंडा

पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय, बठिंडा के पंजाबी विभाग द्वाराइंटैक पंजाब चैप्टर और बठिंडा चैप्टर के सहयोग से श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी वर्ष को समर्पित कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत ‘श्री गुरु तेग बहादुर जी की शिक्षाएं और शहादतः सर्वकालिक सार्थकता’ विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन 24 अप्रैल 2026 को किया गया। कुलपति प्रो. राघवेन्द्र प्रसाद तिवारी के नेतृत्व में आयोजित इस संगोष्ठी में प्रसिद्ध पंजाबी चिंतक और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ऑफ एमिनेंस डॉ. मनमोहन सिंह (पूर्व आईपीएस) ने मुख्य वक्तव्य दिया, जबकि पंजाबी यूनिवर्सिटी के सिख इनसाइक्लोपीडिया विभाग के प्रो. परमवीर सिंह ने विशेष व्याख्यान प्रस्तुत किया। इंटैक पंजाब चैप्टर के संयोजक मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) बलविंदर सिंह तथा बठिंडा चैप्टर के संयोजक श्री कंवर भीम सिंह ने विशेष अतिथि के रूप में भाग लिया। इसके अतिरिक्त विभिन्न अकादमिक सत्रों की अध्यक्षता प्रो. सतनाम सिंह जस्सल, प्रो. राजिंदर सिंह तथा हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय के प्रो. नरेश कुमार ने की। उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के डीन (अकादमिक) प्रो. रामाकृष्ण वुसिरिका ने की।

अपने मुख्य वक्तव्य में डॉ. मनमोहन सिंह ने शहादत की अवधारणा का ऐतिहासिक विश्लेषण करते हुए गुरु तेग बहादुर जी की अद्वितीय शहादत पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि यह शहादत धार्मिक स्वतंत्रता और मानव अधिकारों की रक्षा के लिए दी गई थी तथा इसे केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से भी समझने की आवश्यकता है।

प्रो. परमवीर सिंह ने अपने विशेष व्याख्यान में कहा कि गुरु तेग बहादुर जी ने अपने उपदेशों को व्यवहार में उतारा और समाज को निर्भयता का संदेश दिया। उनकी शहादत ने भारत में सम्मानपूर्वक जीवन जीने की चेतना को मजबूत किया और अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष की प्रेरणा दी। इंटैक के संयोजक मेजर जनरल (से.नि.) बलविंदर सिंह ने ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण और सिख इतिहास के प्रचार-प्रसार की आवश्यकता पर बल दिया तथा नई पीढ़ी को अपने समृद्ध विरासत से जोड़ने की आवश्यकता बताई। डीन (अकादमिक) प्रो. रामाकृष्ण वुसिरिका ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में इस संगोष्ठी के आयोजन के लिए पंजाबी विभाग की सराहना की तथा विश्वविद्यालय में स्थापित किए जा रहे ‘श्री गुरु तेग बहादुर सेंटर ऑफ स्टडीज इन इंडिक सिविलाइजेशन एंड रिलीजियस स्टडीज’ के बारे में जानकारी दी।

संगोष्ठी के लिए 70 से अधिक प्रतिभागियों ने पंजीकरण कराया और तीन अकादमिक सत्रों में चयनित शोध पत्र प्रस्तुत किए गए। शोधकर्ताओं ने गुरु तेग बहादुर जी के जीवन, बाणी और शहादत के विभिन्न पहलुओं पर शोधपरक विचार प्रस्तुत किए।

कार्यक्रम की शुरूआत विभागाध्यक्ष डॉ. अमनदीप सिंह के स्वागत भाषण से हुई तथा प्रो. रमनप्रीत कौर ने संगोष्ठी का परिचय प्रस्तुत किया। मंच संचालन डॉ. सरबजीत सिंह ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन डॉ. सतप्रीत सिंह जस्सल और गुरप्रीत कौर ने प्रस्तुत किया।

इस अवसर पर विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के प्रमुख, शिक्षक, शोधार्थी और विद्यार्थी उपस्थित रहे, साथ ही आसपास के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों से आए प्रतिभागियों ने भी संगोष्ठी में सक्रिय भागीदारी निभाई।

संक्षिप्त-समाचार

विजिलेंस ब्यूरो ने वरिष्ठ कांस्टेबल को 5,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों किया काबू

चंडीगढ़। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही मुहिम के दौरान थाना जैतो, जिला फरीदकोट में तैनात वरिष्ठ कांस्टेबल विक्रम शर्मा को 5,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों काबू किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए राज्य विजिलेंस ब्यूरो के एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि उक्त आरोपी को तहसील जैतो, जिला फरीदकोट के एक निवासी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता के खिलाफ झगड़े की शिकायत मिली थी, जिसके तहत आरोपी वरिष्ठ कांस्टेबल शिकायतकर्ता को उसकी ऑल्टो कार सहित थाना जैतो, जिला फरीदकोट ले गया था। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया। इस संबंध में शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि आरोपी वरिष्ठ कांस्टेबल ने उसकी कार थाने में ही रख ली और कार छोड़ने के बदले 5,000 रुपये रिश्वत मांगी। शिकायतकर्ता ने रिश्वत मांगने संबंधी पूरी बातचीत रिकॉर्ड कर ली थी। शिकायतकर्ता रिश्वत नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने विजिलेंस ब्यूरो यूनिट, फरीदकोट से संपर्क किया। उसकी शिकायत पर प्रारंभिक जांच के बाद विजिलेंस ब्यूरो की टीम ने जाल बिछाया, जिसके दौरान आरोपी वरिष्ठ कांस्टेबल को दो सरकारी गवाहों की मौजूदगी में शिकायतकर्ता से 5,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया। इस संबंध में आरोपी के खिलाफ विजिलेंस ब्यूरो थाना फिरोजपुर में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है।

2027 में पंजाब से विदाई तयः गुरजीत औजला

अमृतसर। अमृतसर से सांसद गुरजीत सिंह औजला ने सात राज्यसभा सदस्यों के दल परिवर्तन पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि इस घटनाक्रम का पंजाब की राजनीति पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ये जनाधार वाले नेता नहीं थे, बल्कि ऐसे व्यक्तियों को आगे बढ़ाया गया जिन्हें समर्पित कार्यकताओं को दरकिनार कर नामित किया गया था। उन्होंने कहा कि जनता ने इन्हें सीधे तौर पर नहीं चुना था। गुरजीत सिंह औजला ने कहा कि यह पतन की शुरूआत है और वर्ष 2027 में जनता सत्ता से विदाई देगी। उन्होंने कहा कि यह घटनाक्रम स्पष्ट करता है कि राजनीति ठोस विचारधारा के बजाय अवसरवाद पर आधारित रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि जहां राजनीतिक आधार कमजोर होता है, वहां दबाव की राजनीति और जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का सहारा लिया जाता है। उन्होंने कहा कि इस दल परिवर्तन से न तो राजनीति प्रभावित होगी और न ही कोई विशेष लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि समर्पित कार्यकताओं को महत्व नहीं दिया गया और बाहरी चेहरों को प्राथमिकता दी गई। अब वही परिणाम सामने आ रहे हैं, जिनकी नींव स्वयं रखी गई थी। उन्होंने कहा कि जैसा बोया गया, वैसा ही परिणाम सामने आया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता में रहते हुए संवैधानिक मूल्यों को कमजोर किया गया, समाचार माध्यमों पर दबाव बनाया गया और सतर्कता तंत्र का राजनीतिक उपयोग किया गया। उन्होंने कहा कि अब उसी प्रकार की स्थिति दूसरे स्तर पर भी दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि झूठे वादों के सहारे सत्ता प्राप्त की गई, लेकिन अब सच्चाई सामने आ रही है और वास्तविक स्थिति उजागर हो रही है। एक साथ सात राज्यसभा सदस्यों का दल परिवर्तन उन्होंने राजनीति के इतिहास की गंभीर घटनाओं में से एक बताया।

जेसीबी इंडिया ने पीएमजीएसवाय-3 के विस्तार का किया स्वागत, गांवों की सड़कें होंगी और बेहतर

चंडीगढ़। जेसीबी इंडिया ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाय-3) को मार्च 2028 तक बढ़ाने के केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया है। कंपनी ने कहा कि यह कदम देश में ग्रामीण कनेक्टिविटी को मजबूत करने की प्रतिबद्धता को और सुदृढ़ करता है। कंपनी के अनुसार, गांवों को सेवाओं और विकास केंद्रों से जोड़ने वाली महत्वपूर्ण सड़कों को बेहतर बनाने से लोगों की रोजमर्रा की पहुंच आसान होगी, स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और समुदायों को प्रगति व बेहतर जीवन जीने के अवसरों के करीब लाने में मदद मिलेगी। इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए जेसीबी इंडिया के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर श्री दीपक शेट्टी ने कहा कि ‘ग्रामीण सड़कें लोगों के रोजमर्रा के जीवन को सीधे प्रभावित करती हैं। ये तय करती हैं कि आपात स्थिति में मदद कितनी जल्दी पहुंचेगी और आजीविका के अवसर कैसे विकसित होंगे। पीएमजीएसवाय जैसे कार्यक्रम ग्रामीण भारत में वास्तविक बदलाव लाते हैं। बेहतर सड़क ढांचा ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी सुविधाओं, सेवाओं और अवसरों से बेहतर तरीके से जोड़ने में मदद करता है। इससे जमीनी स्तर पर होने वाली समस्याएं, जैसे खराब होने वाले उत्पादों का नुकसान, कम होता है और वंचित क्षेत्रों में स्थिर आर्थिक अवसर बनते हैं। ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए, जेसीबी पीएमजीएसवाय-III के विस्तार का स्वागत करता है और सरकार के साथ मिलकर गांवों तक बेहतर कनेक्टिविटी मजबूत करने का समर्थन करता है, ताकि सभी को साथ लेकर टिकाऊ और समावेशी विकास हो सके।

स्पॉटलाइट में रहा ओरेन इंटरनेशनल एफडीएम

चंडीगढ़। ओरेन इंटरनेशनल आज अपने फैशन एजुकेशन प्लेटफॉर्म को नई ऊंचाइयों पर ले गया। ओरेन फैशन स्कूल ने चंडीगढ़ में एक बड़े स्टूडेंट फैशन शो और सेलिब्रिटी इंटरैक्शन सेशन का आयोजन किया। ओरेन इंटरनेशनल भारत की सबसे बड़ी ब्यूटी एंड वेलनेस एजुकेशन कंपनी है और इसके 19 राज्यों में 118 स्कूल और कनाडा के विक्टोरिया में एक सेंटर है । इस इवेंट में नए डिजाइनरों, सेलेब्रिटी फैशन और एंटरटेनमेंट हस्तियों और मीडिया ने जोश, रचनात्मकता और उत्साह के साथ हिस्सा लिया। खास बात यह रही कि इस इवेंट में फराह संजना और दृष्टि खुराना जैसे जाने-माने नामों ने भी शिरकत की। ओरेन के छात्रों ने अपने खुद के डिजाइन किए कलेक्शन पेश करके हुनर, मौलिकता और रैंप कॉन्फिडेंस का शानदार नमूना दिखाया। पूरा माहौल ऊर्जा से भरा था – यह ओरेन की हैंड्स-ऑन ट्रेनिंग का नतीजा और उनकी सीखने सिखलाने की फिलॉसफी की पहचान था। यह इवेंट तब अपने चरम पर पहुँच गया जब फैशन और मनोरंजन जगत की दो मशहूर हस्तियाँ फराह संजना और दृष्टि खुराना वहाँ पहुँचीं। दोनों सेलिब्रिटी ने छात्रों से खुलकर बातचीत की, अपने करियर के अनुभव, इंडस्ट्री की असलियतें और वो गुण शेयर किए जो एक अच्छे डिजाइनर को महान डिजाइनर से अलग बनाते हैं – यह खुली बातचीत स्टूडेंट्स ने बड़े उत्साह से सुनी। मीडिया बाइट्स और इन-हाउस वीडियो कवरेज ने भी इस मौके की रौनक बढ़ा दी। इस दिन को और भी खास बनाते हुए, ओरेन इंटरनेशनल ने पंजाब के लामरिन टेक स्किल्स यूनिवर्सिटी (एलटीएसयू) के साथ एक बड़ी इंडस्ट्री पार्टनरशिप की घोषणा की। यह समझौता एलटीएसयू के सीईओ श्री विमल मन्होत्रा के साथ हुआ। इसके तहत ओरेन एलटीएसयू के फैशन डिजाइन डिग्री प्रोग्राम्स के लिए इंडस्ट्री पार्टनर बनेगा – जिससे विद्यार्थियों को मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी डिग्री मिलेगी और साथ ही ओरेन की इंडस्ट्री एक्सपर्टीज, इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोफेशनल नेटवर्क का फायदा भी होगा। लामरिन टेक स्किल्स यूनिवर्सिटी पंजाब के सीईओ विमल मन्होत्रा ने कहा ओरेन इंटरनेशनल के साथ हमारी साझेदारी भारत में फैशन शिक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। एलटीएसयू की अकादमिक ताकत और ओरेन के इंडस्ट्री अनुभव को मिलाकर हम छात्रों के लिए ऐसा रास्ता बना रहे हैं जहाँ उन्हें दोनों दुनियाओं का सबसे अच्छा फायदा मिले – एक मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी डिग्री और वो हाथों-हाथ, इंडस्ट्री के लिए तैयार प्रशिक्षण जिसकी फैशन इंडस्ट्री को जरूरत है।

पेटीएम ऐप, यूपीआई, क्यूआर, साउंड बॉक्स और अन्य सेवाएं पूरी तरह चालू

चंडीगढ़। पेटीएम ने कहा कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटिड (पीपीबीएल) पर नियामकीय कार्रवाई का कंपनी पर कोई वित्तीय, व्यावसायिक या परिचालन प्रभाव नहीं पड़ा है और इसकी सभी सेवाएं बिना किसी रुकावट के चल रही हैं। पेटीएम ऐप और इसकी सभी सेवाएं, जिनमे पेटीएम यूपीआई, पेटीएम गोल्ड और इसकी सहायक एवं संबद्ध कंपनियों द्वारा दी जाने वाली सेवाएं जैसे पेटीएम क्यूआर, पेटीएम साउंड बॉक्स, पेटीएम कार्ड मशीनस, पेटीएम गेटवे आदि शामिल हैं, सामान्य रूप से काम कर रही हैं। कंपनी ने यह भी कहा कि उसका पेटीएम पेमेंट्स बैंक के साथ कोई महत्वपूर्ण व्यावसायिक संबंध या एक्सपोजर नहीं है और उसकी कोई भी सेवा इससे जुड़ी नहीं है। पेटीएम ने कहा कि जैसा पहले बताया गया है, पेटीएम और इसकी सेवाएं बिना किसी रुकावट के संचालित हो रही हैं और आगे भी जारी रहेंगी। इसमें पेटीएम एप, पेटीएम यूपीआई, पेटीएम गोल्ड और अन्य सेवाएं जैसे पेटीएम क्यूआर, पेटीएम साउंड बॉक्स, पेटीएम कार्ड मशीन्स, पेटीएम ट्रैवल, पेटीएम पेमेंट्स गेटवे और पेटीएम मनी शामिल हैं। एक नियामकीय फाइलिंग में पेटीएम ने कहा कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक स्वतंत्र रूप से संचालित होता है और इसमें पेटीएम के बोर्ड या प्रबंधन की कोई भूमिका नहीं है। कंपनी ने 31 मार्च 2024 को इसमें अपने निवेश को पहले ही राइट ऑफ कर दिया था और इसका कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ा।

सात राज्यसभा सदस्यों का दल परिवर्तन पतन की शुरूआत

चेन्नई का 'गढ़' बचाने उतरेगी सीएसके, गुजरात टाइटंस के लिए 'करो या मरो' की स्थिति

प्लेऑफ की रेस: आज का मुकाबला तय करेगा अंकों का समीकरण

एजेंसी (हि.स.)

चेन्नई

पिछले कुछ मैचों शानदार प्रदर्शन करने वाली चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) की टीम रविवार को गुजरात टाइटंस के खिलाफ यहां होने वाले इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के मैच में अपनी लय बरकरार रखने की कोशिश करेगी। दूसरी तरफ लगातार दो हार का सामना करने वाली गुजरात टाइटंस की टीम अच्छा प्रदर्शन कर-के अपने अभियान को पटरी पर लाने के लिए बेताब होगी। सीएसके ने इस सत्र की शुरूआत अच्छी नहीं की थी लेकिन इसके बाद उसने शानदार वापसी करके अपने पिछले चार मैचों में से तीन में जीत हासिल की है। इसमें मुंबई इंडियंस पर 103 रन की जीत भी शामिल है, जिसमें संजू सैमसन ने सत्र का अपना दूसरा शतक लगाया था।

रुतुराज गायकवाड़ की अगुवाई वाली सीएसके के अभी छह अंक हैं और वह प्लेऑफ में जगह बनाने की दौड़ में बने रहने के लिए आगे किसी भी तरह की गलतियों से बचने के लिए प्रतिबद्ध होगी। सीएसके की टीम अभी अच्छी स्थिति में नजर आ रही है। मुंबई के खिलाफ उसे सैमसन की शानदार पारी और अकील हुसैन की अगुवाई में गेंदबाजों के बेहतर प्रदर्शन के कारण बड़ी जीत मिली।

फोटो: हि.स.

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने यह जीत अपने स्टार खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी (पिंडली की चोट) और युवा बल्लेबाज आयुष म्हात्रे (हैमस्ट्रिंग की चोट) के बिना हासिल की। सीएसके के लिए हालांकि कुछ क्षेत्र चिंता का विषय बने हुए हैं। उसके शीर्ष क्रम ने अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन मध्य क्रम आक्रामक बल्लेबाजी करने और साझेदारी निभाने में नाकाम रहा है। गायकवाड़ खुद भी खराब फॉर्म से गुजर रहे हैं जबकि सरफराज खान, शिवम दुबे और डेवाल्ड ब्रेविस जैसे खिलाड़ी अच्छी शुरूआत को बड़े स्कोर में बदलने में नाकाम रहे हैं। सीएसके के लिए गेंदबाजी विभाग सकारात्मक पहलू रहा है। अंशुल कंबोज ने अपनी निरंतरता बनाए रखी है और टूर्नामेंट में अब तक सर्वाधिक 14 विकेट हासिल किए हैं। जेमी ओवरटन ने उनका अच्छा साथ दिया है। उन्होंने अभी तक नौ विकेट लिए हैं। नूर अहमद ने नियंत्रण बनाए रखा है और हुसैन ने पिछले मैच में चार विकेट लेकर अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। गुजरात टाइटंस की टीम अभी तक अवसरों का फायदा उठाने में नाकाम रही है। उसे पिछले दो मैच में हार का सामना करना पड़ा है। उसे मुंबई इंडियंस ने 99 रन और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने पांच विकेट से हराया।

उसके छह अंक है लेकिन खराब रन रेट के कारण वह सातवें स्थान पर है। आक्रामक बल्लेबाजी को बढ़ावा देने वाले प्रारूप में उनका रूढ़िवादी दृष्टिकोण हमेशा कारगर साबित नहीं हुआ है। विशेष रूप से मध्य क्रम का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है और वे अक्सर अच्छी शुरूआत का लाभ उठाने में विफल रहे हैं। आरसीबी के खिलाफ अपने पिछले मैच में भी गुजरात 230 से अधिक का स्कोर बनाने की स्थिति में दिख रही था, लेकिन उसके बल्लेबाज 16वें और 19वें ओवर के बीच वे तेजी से रन बनाने में नाकाम रहे, जो बाद में निर्णायक साबित हुआ। खराब फील्डिंग ने उसकी मुश्किलें और बढ़ा दीं हैं। विराट कोहली ने जब खाता भी नहीं खोला था तब उनका आसान कैच छोड़ दिया गया था जो काफी महंगा साबित हुआ।

टीम इस प्रकार

गुजरात टाइटंस: साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), शाहरुख खान, अनुज रावत, जोस बटलर, कुमार कुशाग्र, टॉम बैंटन, ग्लेन फिलिप्स, जेसन होल्डर, निशांत सिंधु, राहुल तेवतिया, वॉशिंगटन सुंदर, साई किशोर, जयंत यादव, अरशद खान, शाहरुख खान, मानव सुथार, राशिद खान, मोहम्मद सिराज, कागिसो रबाडा, प्रसिद्ध कृष्णा।

चेन्नई सुपर किंग्स: रुतुराज गायकवाड़ (कप्तान), एमएस धोनी (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), कार्तिक शर्मा (विकेटकीपर), डेवाल्ड ब्रेविस, सरफराज खान, उर्विल पटेल (विकेटकीपर), अमन खान, शिवम दुबे, जैक फॉल्केस, रामकृष्ण घोष, अंशुल कंबोज, जेमी ओवरटन, मैथ्यू शॉर्ट, प्रशांत वीर, राहुल चाहर, श्रेयस गोपाल, गुरजापनीत सिंह, मैट हेनरी, अकील हुसैन, स्पेंसर जॉनसन, मुकेश चौधरी, नूर अहमद।

मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा।

आईपीएल 2026: विराट कोहली के सिर फिर सजी ऑरेंज कैप

एजेंसी (हि.स.)

नई दिल्ली

फोटो: हि.स.

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की गुजरात टाइटंस पर पांच विकेट की जीत के बाद ऑरेंज कैप की दौड़ में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। इस मुकाबले में शानदार प्रदर्शन के दम पर विराट कोहली एक बार फिर शीर्ष स्थान पर पहुंच गए हैं।

206 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए कोहली ने ओपनिंग करते हुए 44 गेंदों में 81 रन की शानदार पारी खेली। उन्होंने 14वें ओवर तक बल्लेबाजी करते हुए टीम की जीत की मजबूत नींव रखी और ह्यप्लेयर ऑफ द मैचह्व भी बने। इस पारी के साथ कोहली अब 7 पारियों में 328 रन बनाकर ऑरेंज कैप की सूची में पहले स्थान पर पहुंच गए हैं। उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद के अभिषेक शर्मा (323 रन) को पीछे छोड़ा। तीसरे स्थान पर सनराइजर्स हैदराबाद के हेनरिक क्लासेन (320 रन) हैं, जबकि गुजरात टाइटंस के शुभमन गिल 297 रन के साथ चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं। गिल ने इस मैच में 24 गेंदों पर 32 रन बनाए, जिससे वह चेन्नई सुपर किंग्स के संजू सैमसन को पीछे छोड़ते हुए ऊपर आ गए। आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार भी इस मुकाबले के बाद सूची में आगे बढ़े हैं। हालांकि उन्होंने इस मैच में सिर्फ 8 रन बनाए, लेकिन कुल 238 रन के साथ वह ईशान किशन के बराबर पहुंच गए हैं। स्ट्राइक रेट के आधार पर पाटीदार आठवें और किशन नौवें स्थान पर हैं। वहीं गुजरात के बी साई सुदर्शन ने 58 गेंदों में शतक जड़कर सीजन का पांचवां शतक बनाया और शीर्ष-10 में जगह बना ली। पर्पल कैप की दौड़ में इस मैच का ज्यादा असर नहीं पड़ा, क्योंकि मुकाबले में कुल आठ विकेट ही गिरे। गुजरात के प्रसिद्ध कृष्णा 12 विकेट के साथ तीसरे स्थान पर बने हुए हैं और सनराइजर्स हैदराबाद के ईशान मलिंगा के साथ संयुक्त रूप से इस स्थान पर हैं। शीर्ष पर चेन्नई सुपर किंग्स के अंशुल कंबोज और लखनऊ सुपर जायंट्स के प्रिंस यादव काबिज हैं। इस बीच भुवनेश्वर कुमार ने जोस बटलर का विकेट लेकर अपने विकेटों की संख्या 11 तक पहुंचा दी है। वह अब राजस्थान रॉयल्स के जोफ्रा आर्चर और रवि बिश्नोई के साथ संयुक्त रूप से अगले स्थान पर हैं।

राइडर कप 2027: टाइगर वुड्स के इंकार के बाद जिम फ्यूरिक बने अमेरिका टीम के कप्तान

एजेंसी (हि.स.)

न्यूयॉर्क/लिमरिक

अमेरिका के अनुभवी गोल्फर जिम फ्यूरिक को 2027 राइडर कप के लिए यूएस टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। यह टूर्नामेंट आयरलैंड के लिमरिक स्थित अडारे मैनर में खेला जाएगा। यह फैसला उस समय आया जब दिग्गज गोल्फर टाइगर वुड्स ने इस भूमिका को स्वीकार करने से इंकार कर दिया। 55 वर्षीय फ्यूरिक, जो पीजीए टूर पर 17 खिताब जीत चुके हैं, इससे पहले 2018 में पेरिस में भी राइडर कप में अमेरिका के कप्तान रह चुके हैं, जहां टीम को हार का सामना करना पड़ा था।

वह कीगन ब्रैडली की जगह इस पद पर आए हैं। फ्यूरिक अब जैक निकलॉस, टॉम वॉटसन और डेविस लव तृतीय के बाद ऐसे चौथे अमेरिकी कप्तान बन गए हैं जिन्हें दूसरी बार यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। फ्यूरिक ने पीजीए ऑफ अमेरिका की प्रेस विज्ञप्ति में कहा, दूसरी बार यूएस राइडर कप टीम का कप्तान बनना मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है। मैं पूरी तरह प्रतिबद्ध हूं कि खिलाड़ियों को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए सही माहौल और रणनीति प्रदान करूं, ताकि हम यूरोपीय जमीन पर कप वापस जीत सकें। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि वह अपने पिछले अनुभव का उपयोग करते हुए कुछ नए विचारों को भी शामिल करेंगे। गौरतलब है कि अमेरिका ने आखिरी बार 1993 में यूरोप में राइडर कप जीता था। 2018 में मिली हार के बाद फ्यूरिक की कप्तानी पर सवाल उठे थे, खासकर टीम चयन और रणनीति को लेकर। हालांकि, उन्होंने 2024 प्रेसिडेंट्स कप में

फोटो: हि.स.

अमेरिका को लगातार 10वीं जीत दिलाकर अपनी नेतृत्व क्षमता साबित की। दूसरी ओर, टाइगर वुड्स इस पद के लिए सबसे बड़े दावेदार माने जा रहे थे, लेकिन उन्होंने हाल ही में एक सड़क दुर्घटना और नशे में ड्राइविंग के आरोप के बाद स्वास्थ्य कारणों से खुद को इस जिम्मेदारी से दूर रखा है। पीजीए ऑफ अमेरिका ने बताया कि वुड्स फिलहाल इलाज पर ध्यान देना चाहते हैं। यूरोपीय टीम की कप्तानी एक बार फिर ल्यूक डोनाल्ड को सौंपी गई है, जो लगातार तीसरी बार यह जिम्मेदारी निभाएंगे। उनका लक्ष्य अपनी टीम को लगातार तीसरी जीत दिलाना है। 2027 राइडर कप का आयोजन 17 से 19 सितंबर के बीच किया जाएगा, जहां फ्यूरिक की अगुवाई में अमेरिकी टीम यूरोप में जीत का सूखा खत्म करने की कोशिश करेगी।

ओलंपिक पदक विजेता हॉकी खिलाड़ी गुरबख्श सिंह ग्रेवाल का निधन

चंडीगढ़। ओलंपिक हॉकी पदक विजेता गुरबख्श सिंह ग्रेवाल का यहां जीरकपुर में शुक्रवार को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वह 84 वर्ष के थे। गुरबख्श 1968 के मैक्सिको सिटी ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय टीम के सदस्य थे। उन्होंने अपने भाई बलबीर सिंह ग्रेवाल के साथ एक ही ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। इस तरह से वे उन कुछ भाईयों की जोड़ी में शामिल हैं जो एक साथ ओलंपिक में खेले। गुरबख्श ने अपने खेल करियर के अलावा पश्चिमी रेलवे में खेल अधिकारी के रूप में काम किया, जहां उन्होंने राजस्थान की कई प्रतिभाओं की पहचान करने और उन्हें रेलवे हॉकी टीम में शामिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुंबई में सेवा से सेवानिवृत्त होने के बाद वह खेल प्रशासन में सक्रिय रहे। वह मुंबई हॉकी संघ के मानद सचिव भी रहे।

ला लीगा 2025-26: बेटिस ने रियल मैड्रिड को 1-1 से रोका

बार्सिलोना खिताब के करीब

एजेंसी (हि.स.)

सेविल

ला लीगा 2025-26 में रियल मैड्रिड को रियल बेटिस के खिलाफ शुक्रवार रात 1-1 से ड्रॉ खेलना पड़ा, जिससे उसकी खिताबी उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। मुकाबले के अंतिम क्षणों में हेक्टर बेल्लेरिन के गोल ने रियल मैड्रिड से जीत छीन ली। मैच के 17वें मिनट में रियल मैड्रिड ने बढ़त बनाई। फेडेरिको वाल्वरडे के दूर से लगाए गए शॉट को बेटिस के गोलकीपर अल्वारो वायेस ठीक से नहीं रोक पाए और गेंद विनीसियस जूनियर के पास पहुंची, जिन्होंने शानदार फिनिश करते हुए टीम को 1-0 की बढ़त दिलाई।

इसके बाद जूड बेलिंगहैम के पास बढ़त दोगुनी करने का मौका था, लेकिन वह चूक गए। पहले हाफ के अंत तक बेटिस ने वापसी की कोशिश की, लेकिन रियल के गोलकीपर आंद्रे लुनिन ने कई बेहतरीन बचाव कर टीम को बढ़त दिलाए रखी। दूसरे हाफ में रियल मैड्रिड ने खेल पर नियंत्रण बनाए रखा, लेकिन कई मौके गंवा दिए। किलियन एम्बाप्पे का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। उन्होंने ट्रेंट अलेक्जेंडर-अर्नोल्ड के पास पर आसान मौका गंवाया, वहीं उनका एक गोल ऑफसाइड करार दिया गया। लुनिन ने 65वें मिनट में कुचो हर्नांडेज के खिलाफ शानदार एक हाथ से बचाव किया और फिर नातान के शॉट को भी रोका। विनीसियस जूनियर भी एक आसान मौका गंवा बैठे, जिससे रियल बढ़त को सुरक्षित नहीं कर सका। इसका खामियाजा टीम को 93वें मिनट में भुगतना पड़ा। फेरलैंड मेंडी से गेंद छिनने के बाद एंटनी ने हमला बनाया और गेंद बेल्लेरिन के पास पहुंची,

फोटो: हि.स.

जिन्होंने भीड़ के बीच से लो शॉट लगाकर गोल कर दिया। मैच के बाद बेल्लेरिन ने कहा, ऐसी स्थिति में ज्यादा सोचने का समय नहीं होता। मैं आमतौर पर दूर से शॉट नहीं लगाता, लेकिन इस बार मौका मिला और गेंद गोल में चली गई। उन्होंने आगे कहा, मुझे लगता है कि हमने मैच में अच्छा नियंत्रण रखा और हमें एक अंक से ज्यादा मिलना चाहिए था।

जीत नहीं मिलना थोड़ा निराशाजनक है, लेकिन यह अच्छा परिणाम है। इस ड्रॉ के बाद बार्सिलोना 82 अंकों के साथ शीर्ष पर है और दूसरे स्थान पर काबिज रियल मैड्रिड से आठ अंक आगे है। बार्सिलोना के पास एक मैच अतिरिक्त है और वह गेटाफे के खिलाफ जीत दर्ज कर अपनी बढ़त को 11 अंक तक बढ़ा सकता है। अब रियल मैड्रिड को खिताब की दौड़ में बने रहने के लिए बाकी मैचों में लगभग परफेक्ट प्रदर्शन करना होगा, जबकि 10 मई को कैंप नोउ में होने वाला एल क्लासिको इस सीजन का निर्णायक मुकाबला साबित हो सकता है।

दर्पण विशेष

विश्व बौद्धिक संपदा दिवस: केवल कानूनों का दस्तावेज नहीं, नवाचार की संजीवनी

दुनिया भर में 26 अप्रैल का दिन 'विश्व बौद्धिक संपदा दिवस' के रूप में मनाया जाता है। देखने में यह केवल एक कैलेंडर की तारीख लग सकती है, जिसे संयुक्त राष्ट्र और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने एक औपचारिक आयोजन बना दिया है। लेकिन अगर आप इसकी गहराई में उतरें, तो पाएंगे कि यह दिन उस 'अदृश्य अर्थव्यवस्था' की रीढ़ है, जो हमारे दैनिक जीवन, मनोरंजन, खेल और यहां तक कि हमारी सुबह की चाय के कप तक को प्रभावित करती है।

खेल के मैदान से पेटेंट की प्रयोगशाला तक

इस वर्ष 2026 में, WIPO ने एक बेहद रोमांचक विषय चुना है: 'आईपी और स्पोर्ट्स: रेडी, सेट, इनोवेट, । खेलों की दुनिया, जिसे हम अक्सर केवल पसीने और मैदान की जंग समझते हैं, असल में बौद्धिक संपदा के सिद्धांतों पर टिकी हुई है।

जब कोई एथलीट दौड़ते हुए अपनी तकनीक को थोड़ा सुधारता है, या जब कोई कंपनी ऐसे जूते बनाती है जो हवा के घर्षण को कम कर सकें, तो वह केवल इंजीनियरिंग नहीं है-वह बौद्धिक संपदा है। 2026 के इस थीम ने इस बात को केंद्र में ला खड़ा किया है कि कैसे पेटेंट, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट मिलकर आधुनिक खेल जगत को चला रहे हैं। सोचिए, क्या बिना ट्रेडमार्क और ब्रांडिंग के ओलंपिक या आईपीएल जैसे टूर्नामेंट का अस्तित्व संभव होता? नहीं। वह 'लोगो', वह जर्सी का रंग, वह ब्रॉडकास्टिंग राइट्स-ये सब IP हैं। ये खेल को केवल एक मनोरंजन नहीं, बल्कि एक अरबों डॉलर का उद्योग बनाते हैं, जो दुनिया भर के लाखों लोगों को रोजगार देता है। लेकिन बौद्धिक संपदा का दायरा खेलों से कहीं अधिक विस्तृत है। यह उस लेखक की कलम से लेकर, जिसने एक उपन्यास लिखा है, उस वैज्ञानिक की लैब तक फैला है, जिसने कैंसर की दवा खोजी है।

भारत: एक उभरती हुई 'नवाचार शक्ति'

भारत के परिप्रेक्ष्य में, बौद्धिक संपदा का महत्व और भी बढ़ जाता है। पिछले कुछ वर्षों में भारत जिस तरह से दुनिया के 'स्टार्टअप हब' के रूप में उभरा है, उसने IP की महत्ता को एक नई ऊंचाई दी है। अक्सर हमारे स्थानीय कारीगर, कलाकार या युवा उद्यमी यह सोचते हैं कि 'पेटेंट' या 'कॉपीराइट' तो बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए है। यह धारणा ही भारतीय नवाचार की सबसे बड़ी दुश्मन है। एक स्टार्टअप के लिए, उसका आइडिया ही उसकी सबसे बड़ी संपत्ति है। यदि उसे सुरक्षित नहीं किया गया, तो वह संपत्ति नहीं, बल्कि एक 'लीक' बन जाती है, जिसे कोई भी बड़ा खिलाड़ी चुरा सकता है। सरकार के 'Startup India' मिशन के तहत पेटेंट और ट्रेडमार्क फाइलिंग में जो उछाल आया है, वह बताता है कि अब हम जागरूक हो रहे हैं। फिर भी, अभी लंबा सफर तय करना बाकी है। हमें यह समझना होगा कि जीआई टैग का संरक्षण-चाहे वह दार्जिलिंग चाय हो या बनारसी साड़ी-हमारे सांस्कृतिक धरोहर को वैश्विक बाजार में खड़ा करने का एकमात्र तरीका है।

एआई का युग: बौद्धिक संपदा के लिए नई चुनौती

2026 में जब हम इस दिवस को मना रहे हैं, तो हमें एक बहुत बड़े 'हाथी' को कमरे में नजरअंदाज नहीं करना चाहिए-और वह है 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस'। एआई ने रचनात्मकता की परिभाषा बदल दी है। आज एआई एल्गोरिदम पेंटिंग बना रहे हैं, संगीत रच रहे हैं, और कोडिंग लिख रहे हैं। सवाल यह है: यदि एआई ने कोई पेंटिंग बनाई, तो उसका मालिक कौन है? क्या वह सॉफ्टवेयर का मालिक है? या वह व्यक्ति जिसने एआई को प्रॉम्प्ट दिया? या खुद मशीन? कानूनी जगत में यह बहस 2026 में अपने चरम पर है। पारंपरिक कानून 'मानवीय प्रयास' पर आधारित थे। एआई के दौर में, जब मशीनें इंसानी बुद्धिमत्ता की नकल कर रही हैं, हमें अपनी परिभाषाओं को दोबारा लिखना होगा। यदि हमने इन कानूनों को अपडेट नहीं किया, तो हम एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाएंगे जहां असली कलाकारों की मेहनत को एआई द्वारा 'मशीनीकृत' कर दिया जाएगा, और उसका आर्थिक लाभ उन तक नहीं पहुंचेगा।

बौद्धिक संपदा: क्या यह केवल 'कानूनी जंग' है?

अक्सर लोग पूछते हैं-क्या IP के कारण ज्ञान महंगा नहीं हो जाता? क्या पेटेंट दवाइयों को आम आदमी की पहुंच से दूर नहीं करते? यह एक वाजिब सवाल है। बौद्धिक संपदा का उद्देश्य ज्ञान को 'कैद' करना नहीं है, बल्कि उसे 'पुरस्कृत' करना है। यदि हम वैज्ञानिकों और लेखकों को उनकी मेहनत का फल नहीं देंगे, तो वे अगली बार नवाचार के लिए प्रोत्साहित नहीं होंगे। संतुलन महत्वपूर्ण है। एक ओर नवाचार के लिए प्रोत्साहन है, और दूसरी ओर जनहितहै। एक स्वस्थ समाज वही है जो इन दोनों के बीच संतुलन बना सके-जहाँ कॉपीराइट का सम्मान भी हो और 'पब्लिक डोमेन' (जो ज्ञान सबके लिए है) की गरिमा भी बनी रहे।

हर नागरिक की जिम्मेदारी

'विश्व बौद्धिक संपदा दिवस' पर हमें यह संकल्प लेना होगा कि हम 'कॉपी-पेस्ट' की संस्कृति से ऊपर उठेंगे। जब आप किसी लेखक की किताब की पायरेटेड कॉपी खरीदते हैं, या किसी कलाकार की कला का अनाधिकृत उपयोग करते हैं, तो आप केवल एक कानून नहीं तोड़ रहे होते, आप उस व्यक्ति के सपनों को मारने का काम कर रहे होते हैं। 'सिटी दर्पन' के पाठकों से मेरी अपील है-चाहे आप एक छात्र हों, उद्यमी हों या एक कलाकार-अपने विचारों को सुरक्षित करना सीखें। नवाचार को बढ़ावा दें और बौद्धिक संपदा का सम्मान करें। क्योंकि किसी ने सच ही कहा है, आइडिया से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती, बशर्ते उसे सही सुरक्षा कवच मिले। इस दिवस का उद्देश्य केवल गोष्ठियां करना या सेमिनार आयोजित करना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि दुनिया जिस गति से आगे बढ़ रही है, उसमें हमारी 'बौद्धिक पूंजी' ही हमारी असली ताकत है। आज के दिन, आइए हम उस अदृश्य संपदा को सलाम करें जिसने इस दुनिया को बेहतर, अधिक सुविधाजनक और अधिक रंगीन बनाया है।

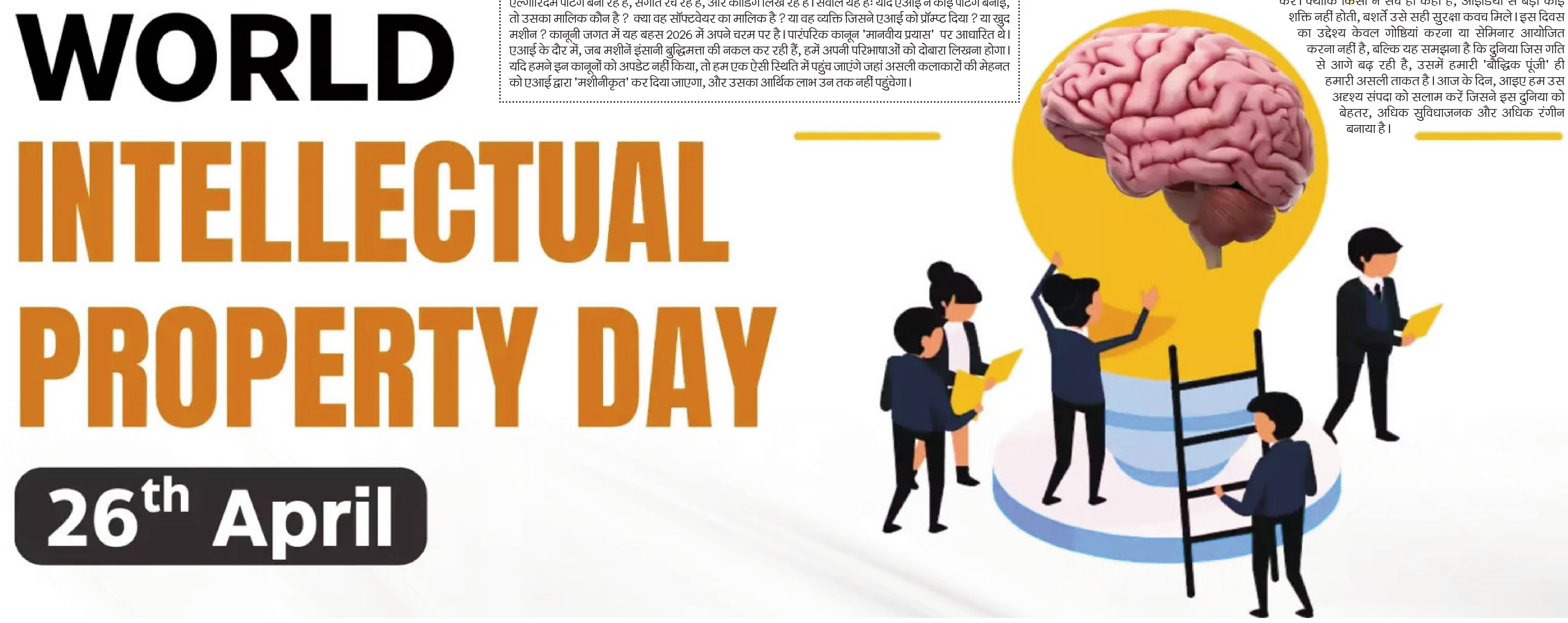

निर्वाचन आयोग की बड़ी कार्रवाई, डायमंड हार्बर के पांच पुलिस अधिकारी निलंबित

अधिकारियों पर चुनाव के दौरान निष्पक्षता बनाए रखने में विफल रहने और गंभीर कदाचार के आरोप

एजेंसी (हि.स.)
कोलकाता

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के बीच भारत निर्वाचन आयोग ने बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए डायमंड हार्बर पुलिस जिले के पांच पुलिस अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने इन अधिकारियों पर चुनाव के दौरान निष्पक्षता बनाए रखने में विफल रहने और गंभीर कदाचार के आरोप लगाए हैं। यहां से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी सांसद हैं।

निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल सरकार के मुख्य सचिव को भेजे पत्र में यह आदेश जारी किया। आयोग ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की 22 अप्रैल की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद यह निर्णय लिया। आयोग ने जिन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, उनमें डायमंड हार्बर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप गराई, एसडीपीओ सजल मंडल, डायमंड हार्बर थाना प्रभारी मौसम चक्रवर्ती, फलता थाना प्रभारी अजय बाग और उस्थी थाना प्रभारी सुभेच्छा बाग शामिल हैं। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि इन अधिकारियों को तत्काल निलंबित किया जाए तथा उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की जाए। संदीप गराई भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं, इसलिए उनके कैडर नियंत्रण प्राधिकरण को भी रिपोर्ट भेजने की बात कही गई है। इसके अलावा आयोग ने डायमंड हार्बर की पुलिस अधीक्षक डॉ. इशानी पाल को चेतावनी जारी करने के निर्देश दिए हैं। आयोग का कहना है कि वह अपने अधीनस्थ अधिकारियों में अनुशासन और चुनाव जैसे

फोटोः हि.स.

संवेदनशील मामलों में निष्पक्षता सुनिश्चित करने में विफल रहीं। निर्वाचन आयोग ने राज्य सरकार को आदेशों का तत्काल पालन करने को कहा है और तत्काल अनुपालन रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में प्रशासनिक फेरबदल की यह कड़ी कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले अप्रैल की शुरूआत में भी आयोग ने सुवेंदु अधिकारी के रोडशो के दौरान कानून-व्यवस्था संभालने में विफल रहने पर भवानीपुर क्षेत्र के चार वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निलंबित किया था। राज्य में इस बार मतदान प्रतिशत के रिकॉर्ड आंकड़ों ने भी आयोग को सतर्क कर दिया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने हाल ही में जानकारी दी थी कि पश्चिम बंगाल ने आजादी के बाद से अब तक का अपना सबसे उच्च मतदान प्रतिशत दर्ज किया है, जो कई जिलों में 90% के आंकड़े को पार कर गया है। उच्च मतदान के इस माहौल में, आयोग किसी भी तरह की हिंसा या प्रशासनिक पक्षपात की गुंजाइश नहीं रखना चाहता। आयोग का मानना है कि मतदान के दौरान प्रशासनिक तंत्र का निष्पक्ष रहना अनिवार्य है ताकि आम जनता का लोकतंत्र में विश्वास बना रहे। विशेषज्ञों का मानना है कि निर्वाचन आयोग द्वारा पुलिस तंत्र में किया जा रहा यह बड़ा फेरबदल राज्य की चुनावी राजनीति में एक बड़ा संदेश दे रहा है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि राज्य सरकार इन आदेशों को कितनी तत्परता से लागू करती है और आगे के चुनावी चरणों में प्रशासनिक तंत्र किस प्रकार अपनी भूमिका निभाता है। फिलहाल, चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि वे निगरानी जारी रखेंगे और किसी भी नियम उल्लंघन पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेंगे।

अराघची के इस्लामाबाद पहुंचते ही ईरान ने कहा-अमेरिका से बातचीत की योजना नहीं

एजेंसी (हि.स.)
तेहरान

फोटोः हि.स.

ईरान ने साफ किया है कि विदेश मंत्री अब्बास अराघची की इस्लामाबाद यात्रा के दौरान अमेरिका के साथ बातचीत की योजना फिलहाल नहीं है। अराघची के नेतृत्व में ईरान का प्रतिनिधिमंडल इस्लामाबाद पहुंचा है। ईरान ने कहा है कि इस यात्रा के दौरान ईरान-अमेरिका के बीच कोई सीधी बैठक तय नहीं है। खास बात यह है कि अमेरिका ने कहा है कि अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और व्हाइट हाउस सलाहकार जेरेड कुशनर शनिवार को ईरान के साथ बातचीत के लिए इस्लामाबाद जाएंगे।

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची के नेतृत्व में शुक्रवार रात ईरान का प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तानी नेताओं के बातचीत इस्लामाबाद पहुंचा है। ईरान इंटरनेशनल ने संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा एवं विदेश नीति समिति के प्रमुख इब्राहिम अजीजी के हवाले से बताया है कि विदेश मंत्री अब्बास अराघची की पाकिस्तान यात्रा केवल द्विपक्षीय मुद्दों तक सीमित है और इसका परमाणु वार्ता से कोई संबंध नहीं है।

अजीजी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, तेहरान में विदेशी पत्रकारों से मुलाकात की और उन्हें हमारे देश की सही तस्वीर पेश करने के लिए आने के लिए धन्यवाद दिया। बैठक में मैंने स्पष्ट कर दिया कि विदेश मंत्री अराघची की पाकिस्तान यात्रा केवल द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा के लिए है और उन्हें परमाणु वार्ता से संबंधित कोई कार्य नहीं सौंपा गया है, जो ईरान की प्रमुख सीमाओं में से एक है।

पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, ईरानी विदेश मंत्री शुक्रवार देर रात इस्लामाबाद पहुंचे। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने एक्स पर उनके पहुंचने की जानकारी दी। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई भी डेलीगेशन के साथ हैं। हालांकि अमेरिका का कहना है कि तेहरान द्वारा ट्रंप प्रशासन से संपर्क करने के बाद अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और व्हाइट हाउस सलाहकार जेरेड कुशनर शनिवार को ईरान के साथ बातचीत के लिए इस्लामाबाद जाएंगे। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लीविट ने अपने बयान में कहा कि ईरान ने आमने-सामने की बातचीत का अनुरोध किया है।

सूरत में नाबालिग से छेड़छाड़ पर देर रात बवाल, गुस्साई भीड़ ने पुलिस स्टेशन घेरा

एजेंसी (हि.स.)
सूरत

सूरत शहर के अलथाण इलाके में नाबालिग से छेड़छाड़ की घटना के बाद देर रात भारी हंगामा हो गया। घटना से नाराज परिजन और स्थानीय लोग बड़ी संख्या में अलथाण पुलिस स्टेशन पहुंच गए और विरोध प्रदर्शन किया। स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि पुलिस को हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को नियंत्रित करना पड़ा। जानकारी के अनुसार सूरत के अलथाण इलाके में मंगलवार रात 12 वर्षीय पाटीदार समाज की बच्ची से छेड़छाड़ की घटना के बाद भारी हंगामा खड़ा हो गया। बच्ची जब एटलांटा मॉल स्थित ट्यूशन से घर लौट रही थी, इसी दौरान एक युवक ने उसके साथ छेड़छाड़ की। बच्ची के चिल्लाने पर आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और आरोपित को पकड़ लिया। गुस्साए लोगों ने पुलिस के आने से पहले आरोपित की जमकर पिटाई कर दी। 112 कंट्रोल रूम की टीम पहुंचने के बाद भी भीड़ का गुस्सा शांत नहीं हुआ और लोगों ने आरोपित को

फोटोः हि.स.

पुलिस वैन से बाहर निकालकर फिर से मारपीट की। सुरक्षा कारणों से आरोपित शेख अजीज को बाद में पांडेसरा पुलिस स्टेशन शिफ्ट किया गया। उसे मेडिकल जांच के लिए नई सिविल अस्पताल ले जाया गया। पुलिस जांच में सामने आया है कि वह मूल रूप से बारडोली का रहने वाला है और पेशे से डिजाइनर है। घटना की जानकारी फैलते ही पाटीदार समाज के लोग बड़ी संख्या में एकत्र हो गए। वराछा, कतारगाम, कापोद्रा और सरथाणा जैसे इलाकों से समाज के लोग और सरदार पटेल ग्रुप के सदस्य मौके पर पहुंचे। करीब 3 किलोमीटर के दायरे में 4 हजार से अधिक लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिससे ट्रैफिक जाम की स्थिति पैदा हो गई।

380 करोड़ की हेरोइन तस्करी मामले में 6 पाकिस्तानी तस्करों को 20 साल की कठोर कैद और जुमार्ना

एजेंसी (हि.स.)
कच्छ

कच्छ के जखौ समुद्री तट पर वर्ष 2021 में पकड़े गए अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स तस्करी के चर्चित मामले में भुज की स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने कड़ा फैसला सुनाया है। भारतीय समुद्री सीमा के जरिए करीब 380 करोड़ रुपये की हेरोइन देश में घुसाने की साजिश रचने वाले 6 पाकिस्तानी नागरिकों को कोर्ट ने 20 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक दोषी पर 2 लाख रुपये का जुमार्ना भी लगाया गया है।

यह मामला दिसंबर 2021 में सामने आया था, जब गुजरात एटीएस को विश्वसनीय सूत्रों से सूचना मिली थी कि पाकिस्तान के कराची बंदरगाह से 'अल हुसैनी' नाम की एक नाव भारी मात्रा में हेरोइन लेकर भारतीय जलसीमा की ओर बढ़ रही है। सूचना मिलते ही एटीएस ने भारतीय तटरक्षक बल के साथ मिलकर संयुक्त ऑपरेशन चलाया। 20 दिसंबर 2021 की सुबह जखौ के पास समुद्र में संदिग्ध बोट को घेरकर पकड़ा गया। तलाशी के दौरान बोट में सवार सभी 6 लोग पाकिस्तानी नागरिक पाए गए और उनके पास से करीब 380 करोड़ रुपये कीमत की हेरोइन बरामद हुई। इस मामले में 21 दिसंबर 2021 को एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। जांच के दौरान बोट का रूट, थ्रूढर डेटा, अंतरराष्ट्रीय संपर्क, मोबाइल रिकॉर्ड, फॉरेंसिक रिपोर्ट और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की गहन जांच की गई। एटीएस ने मजबूत चार्जशीट दाखिल करते हुए कोर्ट में कुल 203 दस्तावेजी सबूत और 13 गवाह पेश किए। इसमें एटीएस अधिकारी, कोस्ट गार्ड के जवान और फॉरेंसिक विशेषज्ञ शामिल थे। भुज की स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने सभी सबूतों और गवाहों के आधार पर सभी को दोषी करार दिया। कोर्ट ने कहा कि नशीले पदार्थों की तस्करी केवल कानून का उल्लंघन नहीं, बल्कि देश की युवा पीढ़ी और आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। कोर्ट ने सभी को एनडीपीएस एक्ट की धाराओं 8(उ), 22(उ), 25 और 29 के तहत दोषी ठहराते हुए 20 साल की सख्त कैद और जुमार्ने की सजा सुनाई। चार साल बाद आए इस फैसले ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत की समुद्री सीमाओं के जरिए नशे की तस्करी करने वालों के खिलाफ कानून और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सख्त हैं।

संक्षिप्त-समाचार

अवैध रेत निकालने इंद्रावती नदी के भीतर 200 मीटर लंबी सड़क बनाई

बीजापुर। जिले के भोपालपटनम ब्लॉक के अटटूकपल्ली पंचायत अंतर्गत कोंडामौसम गांव में इंद्रावती नदी के भीतर ही करीब 200 मीटर लंबी सड़क बनाकर अवैध रेत निकालने का रास्ता तैयार कर दिया गया है। हैरानी की बात यह है कि यह पूरा निर्माण बिना किसी प्रशासनिक अनुमति के किया गया है। ग्रामीणों के अनुसार नदी के बीच मुरूम और रेत डालकर सड़क बनाई गई है, साथ ही पाइप पुलिया डालकर नदी का पानी दूसरी ओर मोड़ दिया गया है, जिससे तस्करों को रेत निकालने और वाहनों की आवाजाही में आसानी हो सके। इस पूरे मामले में तेलंगाना के ठेकेदारों की सक्रिय भूमिका सामने आ रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच और सचिव की मिलीभगत से यह पूरा खेल चल रहा है। बिना ग्रामसभा की अनुमति और बिना ग्रामीणों को जानकारी दिए सड़क निर्माण कर दिया गया। ग्रामीण मोडेम गणपत पंच ने बताया कि सिर्फ नारियल फोड़कर काम शुरू कर दिया गया, हमें कोई जानकारी नहीं दी गई। वहीं ग्रामीण तलाड़ी इरैया ने कहा कि गांव में इस विषय पर कोई बैठक नहीं हुई, किसकी अनुमति से सड़क बनी यह हमें नहीं पता। यालम शिवेया, दूबा तुलसीराम और दूबा नागेय की जमीन से होकर सड़क बनाई गई है। जमीन मालिकों को इस कार्य की सूचना तक नहीं दी गई। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व यशवंत नाग का कहना है कि आपके माध्यम से मामले की जानकारी मिली है ।

टाटानगर स्टेशन पर 15 किलो गांजा के साथ दो तस्कर गिरफ्तार

पूर्वी सिंहभूम। नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत टाटानगर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ और जीआरपी की संयुक्त टीम ने एक बार फिर बड़ी सफलता हासिल की है। शुक्रवार देर रात चलाए गए विशेष छापेमारी अभियान में दो तस्करों को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से करीब 15 किलो गांजा बरामद किया गया। बरामद गांजा की कीमत लाखों रुपये बताई जा रही है। यह कार्रवाई टाटानगर स्थित आरपीएफ पोस्ट के प्रभारी अधिकारी एस.के. साव और रेल एसपी अजीत कुमार के नेतृत्व में की गई। अधिकारियों को गुप्त सूचना मिली थी कि ट्रेन के माध्यम से गांजा की खेप टाटानगर स्टेशन पहुंचने वाली है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए आरपीएफ और जीआरपी की संयुक्त टीम ने स्टेशन परिसर और प्लेटफॉर्म क्षेत्र में सघन जांच अभियान चलाया। इसी दौरान संदिग्ध गतिविधियों में शामिल दो व्यक्तियों को रोका गया, जिनकी तलाशी लेने पर उनके पास से गांजा बरामद हुआ। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान बिहार के नवादा जिले के रजौली निवासी उपेंद्र कुमार (38) और विनोद साव (55) के रूप में हुई है। प्रारंभिक पूछताछ में दोनों ने गांजा की खेप को दूसरे राज्य तक पहुंचाने की बात स्वीकार की है। गिरफ्तारी के बाद दोनों आरोपितों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

सड़क हादसे में दो चचेरे भाइयों की मौत, दो गंभीर घायल

उमरिया। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 43 पर ग्राम अमहा खेरदाई मंदिर के पास शुक्रवार-शनिवार की दरम्यानी देर रात एक सड़क हादसे में घायल दो चचेरे भाइयों की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि दो को गंभीर हलत में शहडोल मेडिकल कॉलेज रिफर किया गया है। घटना के बारे में 108 एम्बुलेंस के ईएमटी आबिद शेख ने बताया कि देर रात सूचना मिली कि अमहा खेरदाई के पास सड़क हादसा हो गया है। सूचना मिलते ही तत्काल मौके पर पहुंचे तो वहां चार युवक गम्भीर हालत में पड़े हुए थे। सभी को जिला अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान दो युवकों की मौत हो गई। मृतकों में थाना नोरोजाबाद अंतर्गत ग्राम बरही निवासी सनन (18) पुत्र सुखराम बैगा एवं अभिषेक (20) पुत्र बाबूलाल बैगा शामिल हैं। दोनों मृतक चचेरे भाई थे। वहीं शिवम (10) पुत्र दादू राम बैगा एवं छोटू (26) पुत्र आशा राम बैगा निवासी ग्राम कंचनपुर थाना नौरोजाबाद गम्भीर रूप से घायल है, जिन्हें जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार कर शहडोल रेफेर किया गया है।

उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा 2026 का परिणाम घोषित

हाईस्कूल में 92.10 और इंटर में 85.11 फीसदी छात्र सफल

एजेंसी (हि.स.)
रामनगर (नैनीताल)

उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद् (यूबीएसई) ने वर्ष 2026 के हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षाओं के परिणाम घोषित कर दिए हैं। हाईस्कूल में 92.10% और इंटर में 85.11% छात्र सफल रहे। मेधावी सूची में अक्षत गोपाल ने 98.20% अंक इंटर की गीतिका पंत और सुशीला मेंहदीरत्ता ने 98.00% अंक के साथ संयुक्त रूप से पहला स्थान प्राप्त किया है। परिषद् के सभापति डॉ. मुकुल कुमार सती ने शनिवार को कैबिनेट मंत्री की उपस्थिति में परिणाम जारी किए। इस वर्ष दोनों स्तरों पर परीक्षाफल में वृद्धि दर्ज की गई है और छात्राओं ने बेहतर प्रदर्शन किया है। हाईस्कूल परीक्षा में 1,12,266 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिनमें से

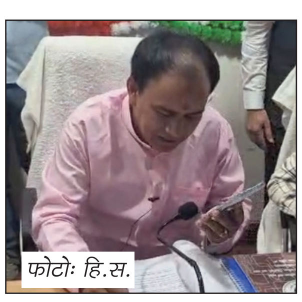
फोटोः हि.स.

1,08,983 ने परीक्षा दी और 1,00,373 सफल घोषित हुए। कुल परीक्षाफल 92.10% रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 1.33% अधिक है। बालकों का उत्तीर्ण प्रतिशत 88.03% जबकि बालिकाओं का 96.07% रहा। संस्थागत परीक्षार्थियों का परिणाम 92.47% और व्यक्तिगत परीक्षार्थियों का 65.05% दर्ज किया गया। हाईस्कूल मेधावी सूची में एम.पी. हिन्दू इण्टर कॉलेज, रामनगर (नैनीताल) के अक्षत गोपाल ने 98.20 प्रतिशत (491/500) अंक प्राप्त कर प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल किया। द्वितीय स्थान पर एस.वी.एम. इण्टर कॉलेज, चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी) के इशांत कोठारी और जी.बी. पंत राजकीय इण्टर कॉलेज, खैरना (नैनीताल) की भूमिका ने 98.00 प्रतिशत (490/500) अंक के साथ संयुक्त रूप से स्थान प्राप्त किया। भूमिका ने बालिकाओं की श्रेष्ठता सूची में भी सर्वोच्च स्थान हासिल किया। तृतीय स्थान विवेकानंद वी.एम. इण्टर कॉलेज, मण्डलसेरा (बागेश्वर) के योगेश जोशी ने 97.80 प्रतिशत (489/500) अंक प्राप्त कर हासिल किया। बागेश्वर जनपद 96.98% परिणाम के साथ प्रदेश में शीर्ष पर रहा। इण्टरमीडिएट परीक्षा में 1,02,986 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिनमें से 1,00,452 परीक्षा में शामिल हुए और 85,499 सफल हुए। कुल परीक्षाफल 85.11% रहा, जो पिछले वर्ष से 1.88% अधिक है। बालकों का उत्तीर्ण प्रतिशत 81.93% और बालिकाओं का 88.09% दर्ज किया गया। संस्थागत परीक्षार्थियों का परिणाम 85.93% और व्यक्तिगत परीक्षार्थियों का 61.48% रहा।

दूसरे चरण के मतदान से पहले हावड़ा में ईडी की छापेमारी कई चावल कारोबारियों के ठिकानों पर तलाशी

एजेंसी (हि.स.)
कोलकाता

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान से पहले प्रवर्तन निदेशालय ने एक बार फिर सक्रियता बढ़ा दी है। उत्तर 24 परगना जिले के हाबड़ा इलाके में शनिवार सुबह से कई स्थानों पर छापेमारी और तलाशी अभियान चलाया गया। स्थानीय सूत्रों के अनुसार, कई चावल कारोबारियों के घरों और परिसरों पर ईडी की टीम पहुंची। केंद्रीय बल के जवान भी अभियान में साथ रहे।

ईडी सूत्रों के मुताबिक, यह कार्रवाई राशन घोटाला मामले से जुड़े वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों के आधार पर की जा रही है। बताया गया है कि शनिवार तड़के कोलकाता स्थित सीजीओ कॉम्प्लेक्स से ईडी की कई टीमें रवाना हुई थीं। सूत्रों का कहना है कि अधिकारियों को कारोबारियों के घरों के बाहर कुछ समय तक इंतजार करना पड़ा। काफी देर तक दरवाजा नहीं खुलने के बाद लंबी प्रतीक्षा के पश्चात प्रवेश मिला और उसके बाद तलाशी अभियान शुरू किया गया। स्थानीय स्तर पर दावा किया गया है कि हावड़ा के कारोबारी समीर चंद और सागर साहा के आवासों पर भी ईडी की टीम पहुंची है, जहां तलाशी जारी है। राज्य में विधानसभा चुनाव के माहौल के बीच पिछले कुछ सप्ताह से ईडी विभिन्न मामलों में लगातार सक्रिय नजर आ रही है। कभी घरों और दफ्तरों में तलाशी ली जा रही है, तो कभी संदिग्धों को पूछताछ के लिए सीजीओ

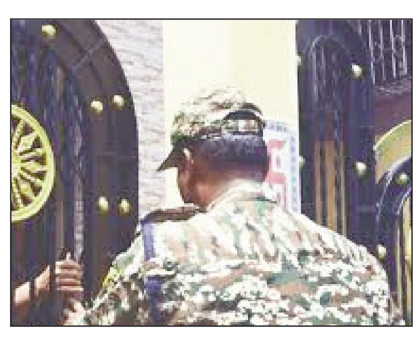

कॉम्प्लेक्स बुलाया जा रहा है। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने ईडी की इस सक्रियता पर सवाल उठाए हैं। पार्टी का आरोप है कि चुनाव के समय केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर उसे राजनीतिक रूप से परेशान करने की कोशिश की जा रही है। तृणमूल के कई नेता और मंत्रियों को भी तलब किया गया है। कुछ नेता पूछताछ में शामिल हुए हैं, जबकि कुछ ने चुनाव प्रचार में व्यस्तता का हवाला देकर समय मांगा है। उल्लेखनीय है कि राज्य में 23 अप्रैल को पहले चरण में 152 विधानसभा सीटों पर मतदान हो चुका है। दूसरे चरण में शेष 142 सीटों पर 29 अप्रैल, बुधवार को मतदान होगा। हाबड़ा विधानसभा क्षेत्र में भी इसी चरण में वोट डाले जाएंगे। चुनाव परिणाम चार मई को घोषित किए जाएंगे।

मणिपुर में हथियारों का जखीरा बरामद, पांच किलो से अधिक हेरोइन के साथ तीन गिरफ्तार

एजेंसी (हि.स.)
इंफाल

फोटोः हि.स.

मणिपुर में सुरक्षा बलों ने उग्रवाद-रोधी और नशीले पदार्थों के खिलाफ अभियानों को तेज कर दिया है, जिसके चलते चंदेल ज़िले में हथियारों और विस्फोटकों का एक बड़ी जखीरा बरामद हुआ है। चुराचांदपुर ज़िले में हेरोइन की बड़ी मात्रा के साथ तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मणिपुर पुलिस मुख्यालय द्वारा आज जारी आधिकारिक जानकारी के अनुसार शुक्रवार को सुरक्षा बलों ने चंदेल ज़िले के मोलचाम पुलिस स्टेशन के अंतर्गत खुमकोट गांव के सामान्य इलाके में एक अभियान चलाया। तलाशी के दौरान, सुरक्षा बलों ने चार सिंगल बोर राइफलें, चार देसी ग्पोम्पीर हथियार, सात पोम्पी शेल, एक डेटोनेटर के साथ तीन ग्रेनेड और संबंधित चार्जर के साथ पांच बाओफेंग रेडियो सेट बरामद किए। बरामद की गई चीजों के बारे में आगे की जांच चल रही है। वहीं, बीते 23 अप्रैल को एक अलग अभियान में सुरक्षा बलों ने चुराचांदपुर ज़िले के सिंगंगाट पुलिस स्टेशन के अंतर्गत बोलकोट से तीन लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार लोगों की पहचान नेंगमुआनलाल और गिनलामथांग गुइटे के रूप में हुई है, जो दोनों सिंगंगाट के एम बुआंगमुन गांव के निवासी हैं और हांगखानलियान के रूप में हुई है, जो हरियाणा के गुड़गांव में चकरपुर का निवासी है। अभियान के दौरान, कर्मियों ने 474 साबुनदानी जब्त कीं जिनमें संदिग्ध हेरोइन भरी थी, जिसका वजन लगभग 5.43 किलोग्राम था; इसके साथ ही एक चार-पहिया वाहन भी जब्त किया गया, जिसके बारे में माना जाता है कि इसका उपयोग मादक पदार्थों के परिवहन के लिए किया गया था। जब्त किए गए नशीले पदार्थों की कीमत करोड़ों रुपये आंकी गयी है।

मौसम | राजस्थान, मप्र और छत्तीसगढ़ में पारा 45 डिग्री के करीब, लू का रेड अलर्ट

देशभर में गर्मी का 'तीखा वार': लू के थपेड़ों से बेहाल जनता, अगले 48 घंटे भारी

बंगाल में राहत की दस्तकः 'कालबैशाखी' और बारिश का पूवार्नुमान, मछुआरों को समुद्र से दूर रहने की हिदायत

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

अप्रैल 2026 के अंतिम सप्ताह में देश का मौसम दो विपरीत छोरों पर खड़ा है। उत्तर, मध्य और पश्चिमी भारत जहां भीषण गर्मी और लू (हीटवेव) की चपेट में है, वहीं पूर्वी भारत में राहत की बारिश और 'कालबैशाखी' के संकेत मिल रहे हैं। मौसम विभाग की ताजा रिपोर्टों के अनुसार, अगले 48 घंटे देश के बड़े हिस्से के लिए चुनौतीपूर्ण रहने वाले हैं, जिसके बाद पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मौसम में व्यापक बदलाव की उम्मीद है। राजस्थान में भीषण गर्मी ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। बाड़मेर में पारा 44.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जो इस सीजन का उच्चतम स्तर है। प्रदेश के 24 शहरों में तापमान 40 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया है। राजधानी जयपुर में भी पारा 41.8 डिग्री पर पहुंच गया, जिससे दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। हालांकि, राज्य के उत्तर-पश्चिमी जिलों जैसे चूरू, हनुमानगढ़ और बीकानेर में शाम के समय धूलभरी हवाएं चलने और कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी से लोगों को मामूली राहत मिली है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, अगले दो दिन यानी 25 और 26 अप्रैल तक लू का असर बरकरार रहेगा। इसके बाद एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के आने से प्रदेश के 16 जिलों में आंधी और बारिश की संभावना है, जिससे तापमान में गिरावट आएगी। मध्य भारत में गर्मी का सितम जारी है। मध्य प्रदेश में ग्वालियर, दतिया, खजुराहो और नौगांव जैसे जिले 'हीटवेव' की चपेट में हैं।

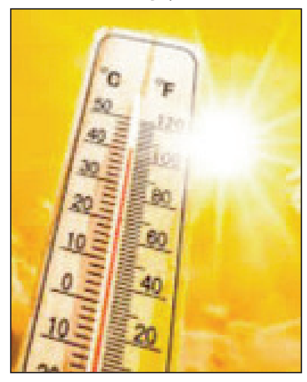

खजुराहो में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। ग्वालियर में पारा 42 डिग्री के पार है। मौसम विभाग ने ग्वालियर और उज्जैन संभाग के 20 से अधिक जिलों में लू का अलर्ट जारी किया है।

दूसरी ओर, छत्तीसगढ़ में भी गर्मी का पारा आसमान छू रहा है। राजनांदगांव में तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो प्रदेश में सर्वाधिक है। रायपुर में पारा 43.4 डिग्री और बिलासपुर में 43.6 डिग्री तक पहुंच गया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, पूर्वी उत्तर प्रदेश से दक्षिण बांग्लादेश तक बनी द्रोणिका और महाराष्ट्र क्षेत्र में सक्रिय चक्रवाती परिसंचरण के कारण शुष्क और गर्म हवाएं आ रही हैं, जिससे तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि, 26 अप्रैल से बादल छाने और कहीं-कहीं हल्की बारिश से लोगों को लू से कुछ राहत मिल सकती है।

भीषण गर्मी से जूझ रहे पश्चिम बंगाल के लिए राहत की खबरें हैं। अलीपुर मौसम विभाग ने रविवार से कोलकाता समेत पूरे दक्षिण बंगाल में मौसम बदलने का पूवार्नुमान जारी किया है। दक्षिण बंगाल के विभिन्न जिलों में 'कालबैशाखी' का असर देखने को मिलेगा। उत्तर 24 परगना, मुर्शिदाबाद, नदिया, बीरभूम, बांकुड़ा और पुरुलिया जैसे जिलों में सतर्कता जारी की गई है। अगले कुछ दिनों तक 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और गरज-चमक के साथ बारिश होने की पूरी संभावना है। समुद्री तटों पर भी हवा की गति तेज रहने के कारण मछुआरों को मंगलवार तक गहरे समुद्र में न जाने की सख्त सलाह दी गई है। इसके अलावा, उत्तर बंगाल के दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और अलीपुरद्वार में भारी बारिश के लिए 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया गया है।

गर्मी से बचाव

मौसम विभाग की चेतावनी के बीच स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने आम लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है। हाइड्रेशनः पर्याप्त मात्रा में पानी, नींबू पानी, नारियल पानी और ओआरएस का घोल लें। प्यास न लगने पर भी पानी पीते रहें। समय का ध्यानः दोपहर 12 बजे से 4 बजे के बीच घर से बाहर निकलने से बचें। यदि बाहर जाना जरूरी हो, तो सिर ढंककर रखें और सूती कपड़े पहनें। खान-पानः हल्का और सुपाच्य भोजन करें। अधिक तला-भुना और मसालेदार भोजन शरीर के तापमान को बढ़ाता है। सतर्कताः यदि आपको चक्कर आना, बहुत ज्यादा पसीना आना, सिरदर्द या बेहोशी महसूस हो, तो तुरंत ठंडी जगह पर जाएं और चिकित्सक से संपर्क करें। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि इस बार अप्रैल के अंत में तापमान में वृद्धि का मुख्य कारण वायुमंडल में नमी की कमी और शुष्क हवाओं का तेजी से प्रवेश है। उत्तर-पश्चिम भारत में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता में देरी और पूर्वी भारत में द्रोणिका रेखा का प्रभाव इस बार अलग-अलग राज्यों में मौसम को अलग-अलग दिशा दे रहा है। आने वाले दिनों में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से जहां राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ में गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है, वहीं बंगाल की खाड़ी से नमी मिलने के कारण पूर्वी भारत में बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। अगले 48 घंटों में पूरे देश की निगाहें मौसम विभाग के नए बुलेटिन पर टिकी हैं, क्योंकि यह बदलते मिजाज ही तय करेंगे कि मई की शुरूआत राहत भरी होगी या और भी अधिक गर्मी वाली।

पीएनपी अपनाने और पानी की दरों की समीक्षा की

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

यू.टी. चंडीगढ़ के खाद्य एवं आपूर्ति, उपभोक्ता मामले एवं विधिक माप विज्ञान विभाग के सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न वाणिज्यिक, औद्योगिक एवं रेस्टोरेंट एसोसिएशनों के प्रतिनिधियों तथा इंडियन ऑयल अडानी गैस प्रा. लि. ने भाग लिया। बैठक के दौरान प्रतिभागियों ने पाइप्ड नेचुरल गैस की संभावित उच्च कीमतों तथा दरों में पारदर्शिता की कमी को लेकर अपनी चिंताएं व्यक्त कीं। यह भी अवगत कराया गया कि उपभोक्ता PNG को अपनाने के इच्छुक हैं, किन्तु अनावश्यक मूल्य वृद्धि, दरों में स्पष्टता की कमी तथा सिक्योरिटी डिपॉजिट से संबंधित अस्पष्टता के कारण इस दिशा में संक्रमण प्रभावित हो रहा है। इस पर IOAGPL को निर्देशित किया गया कि वह एसोसिएशनों के समक्ष विस्तृत प्रस्तुति देकर वाणिज्यिक दरों एवं अन्य शुल्कों के संबंध में स्पष्टता प्रदान करे। इंडियन ऑयल अडानी गैस प्रा. लि. द्वारा वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को पाइप्ड नेचुरल गैस कनेक्शन प्रदान करने हेतु एक पारदर्शी एवं सुव्यवस्थित प्रक्रिया स्थापित की गई है, जो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के मानकों के अनुरूप है। प्रक्रिया की शुरूआत इच्छुक उपभोक्ता द्वारा एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर्म जमा करने से होती है, जिसमें प्रतिष्ठान का नाम, पता, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, व्यवसाय का प्रकार तथा वर्तमान ईंधन उपयोग से संबंधित जानकारी शामिल होती है। प्राप्त जानकारी के आधार पर IOAGPL द्वारा तकनीकी लोड आकलन किया जाता है तथा उपयुक्त मीटर या मीटरिंग एवं रेगुलेटिंग स्किड का निर्धारण किया जाता है। साथ ही, निकटतम गैस पाइपलाइन से दूरी का भी आकलन किया जाता है। इसके पश्चात कंपनी द्वारा एक वाणिज्यिक प्रस्ताव प्रदान किया जाता है, जिसमें तकनीकी एवं वित्तीय विवरण शामिल होते हैं। चंडीगढ़ (यू.टी.) के लिए वाणिज्यिक गैस की कीमत 2058.14 प्रति MMBTU निर्धारित है, जिस पर 12.5% वैट लागू है। कनेक्शन सिक्योरिटी डिपॉजिट एक ब्याज-मुक्त एवं वापसी योग्य राशि है (डिस्कनेक्शन के समय लागू कटौतियों के अधीन)। इसके भुगतान हेतु निम्न विकल्प उपलब्ध हैः अग्रिम भुगतान योजना , रेंटल योजना, समतुल्य पखवाड़ा किश्त योजना

मीटरिंग विकल्प उपभोक्ता की आवश्यकताओं के अनुसार निर्धारित किए जाते हैं। रेंटल शुल्क पर 18% जीएसटी लागू होता है। उपभोक्ताओं को गैस खपत के आधार पर पेमेंट सिक्योरिटी डिपॉजिट भी जमा करना होता है, जो अनुमानित खपत (30 दिन नकद जमा या 45 दिन बैंक गारंटी) के आधार पर निर्धारित किया जाता है। बर्नर कन्वर्जन एवं आंतरिक पाइपलाइन की स्थापना की जिम्मेदारी उपभोक्ता की होती है। IOAGPL का कार्यक्षेत्र मीटर तक पाइपलाइन बिछाने तक सीमित है। आंतरिक पाइपलाइन का निर्माण PNGRB मानकों के अनुरूप होना चाहिए तथा थर्ड पार्टी निरीक्षण एजेंसी से फिट फॉर यूज प्रमाणपत्र प्राप्त करना अनिवार्य है। प्रत्येक तीन वर्ष में पाइपलाइन का पुनः परीक्षण भी आवश्यक है।प्रस्ताव स्वीकृत होने के पश्चात उपभोक्ता अनुबंध पर हस्ताक्षर, केवाईसी दस्तावेज जमा करने एवं उरऊ भुगतान के साथ पंजीकरण पूर्ण करता है। इसके बाद IOAGPL द्वारा पाइपलाइन एवं मीटर की स्थापना की जाती है। आवश्यक दस्तावेज एवं ढरऊ जमा होने के बाद गैस आपूर्ति प्रारंभ की जाती है। बिलिंग पखवाड़ा आधार पर की जाती है तथा भुगतान 7 दिनों के भीतर करना होता है। रेंटल एवं EFI योजनाओं के अंतर्गत शून्य खपत की स्थिति में भी शुल्क देय रहते हैं। यद्यपि न्यूनतम खपत शुल्क लागू नहीं है, तथापि सभी दरें एवं शर्तें कंपनी की नीति के अनुसार समय-समय पर परिवर्तित हो सकती हैं। समग्र रूप से यह प्रक्रिया PNG के उपयोग हेतु एक सुव्यवस्थित, सुरक्षित एवं पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करती है।

चंडीगढ़ में विश्व मलेरिया दिवस का आयोजन

सिटी दर्पण संवादादता
चंडीगढ़

विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों के अनुरूप, स्वास्थ्य विभाग, यूटी चंडीगढ़ के मलेरिया विंग द्वारा आज विश्व मलेरिया दिवस 2026 मनाया गया। इस वर्ष का विषय मलेरिया उन्मूलन के लिए प्रतिबद्धः अब हम कर सकते हैं, अब हमें करना ही होगा है। यह सभी गतिविधियां स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशक, डॉ. सुमन के मार्गदर्शन एवं नेतृत्व में आयोजित की गईं। मलेरिया की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु सभी एएएम में स्थित मलेरिया यूनिट्स पर स्वास्थ्य कर्मचारियों, जिनमें एसएमओ/एमओ, पैरामेडिकल स्टाफ एवं मरीज शामिल थे, को शपथ दिलाई गई। इस शपथ में समुदाय स्तर पर मच्छरों के प्रजनन स्त्रोतों को समाप्त करने के महत्व पर बल दिया गया। इसके अतिरिक्त, विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में प्रार्थना सभाओं के दौरान विद्यार्थियों एवं शिक्षकों द्वारा भी शपथ ली गई। 39 मलेरिया फील्ड यूनिट्स द्वारा जागरूकता रैलियां निकाली गईं। इन रैलियों के दौरान घर-घर जाकर लोगों को जागरूक किया गया तथा सूचना, शिक्षा एवं संचार सामग्री वितरित की गई। साथ ही, मच्छरों के प्रजनन स्थलों की गहन जांच भी की गई।

विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में अधिकारियों एवं स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा व्याख्यान आयोजित किए गए, जिनमें मलेरिया के लक्षण, बचाव के उपाय तथा उन्मूलन रणनीतियों के बारे में जानकारी दी गई। सहायक निदेशक मलेरिया, डॉ. उपेंद्रजीत सिंह गिल ने सेक्टर-25 स्थित चितकारा इंटरनेशनल स्कूल में 484 विद्यार्थियों एवं 57 शिक्षकों को वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम के बारे में जागरूक किया। इसी प्रकार सेक्टर-28 के सेंट सोल्जर इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल तथा सेक्टर-40 के श्री गुरु हरि किशन पब्लिक स्कूल में भी 150 विद्यार्थियों एवं 97 शिक्षकों को जागरूक किया गया।

एसडी कॉलेज में दो दिवसीय एसईएम कार्यशाला संपन्न, प्रतिभागियों को सिखाए डेटा विश्लेषण के गुर

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

सेक्टर-32 स्थित गोस्वामी गणेश दत्त सनातन धर्म कॉलेज के पोस्ट ग्रेजुएट कामर्स एंड मैनेजमेंट विभाग द्वारा पीएम-उषा योजना के अंतर्गत आयोजित दो दिवसीय स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग (एसईएम) वर्कशॉप रविवार को संपन्न हो गई। वर्कशॉप के दूसरे दिन का मुख्य फोकस एसईएम के एडवांस्ड एप्लीकेशंस पर रहा। इस दौरान प्रतिभागियों को एम्पिरिकल रिसर्च तकनीकों की गहन जानकारी दी गई, जिससे उनकी शोध संबंधी समझ और कौशल को मजबूत करने में मदद मिली।

कार्यशाला के सत्र पंजाब यूनिवर्सिटी के अर्थशास्त्र विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. नितिन अरोड़ा द्वारा संचालित किए गए। उन्होंने व्यावहारिक प्रदर्शन और हैंड्स-ऑन लर्निंग के माध्यम से प्रतिभागियों को लगातार सक्रिय रूप से जोड़े रखा। दूसरे सत्र और समापन में स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग (एसईएम) और पैनल डेटा एनालिसिस पर फोकस किया गया। इसमें प्रतिभागियों को प्रैक्टिकल अभ्यास कराकर बताया गया कि जटिल और लंबे समय के डेटा को कैसे संभालते हैं और उससे सही निष्कर्ष कैसे निकाले जाते हैं। प्रतिभागियों को लॉन्गिट्यूडिनल और जटिल डेटा सेट्स के प्रबंधन, समय-आधारित संबंधों को समझने तथा शोध मॉडलों की विश्वसनीयता बढ़ाने के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली।

इंटरएक्टिव सत्र के दौरान रियल-टाइम डेटा विश्लेषण और मॉडल की व्याख्या कराई गई, जिससे प्रतिभागियों की विश्लेषणात्मक क्षमता और एसईएम टूल्स के प्रभावी उपयोग में आत्मविश्वास बढ़ा। यह कार्यशाला एनईपी 2020 के तहत बहु-विषयक शिक्षा और कौशल विकास की भावना को आगे बढ़ाने वाला एक अच्छा प्रयास रही, जिसमें प्रतिभागियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया और चर्चा की। समापन सत्र के दौरान कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. अजय शर्मा ने रिसोर्स पर्सन के योगदान की सराहना की और प्रतिभागियों के उत्साह की प्रशंसा की। उन्होंने प्रतिभागियों को उन्नत शोध पद्धतियों के साथ लगातार जुड़े रहने के लिए प्रेरित किया।

एमओएसजेई का राष्ट्रीय चिंतन शिविरः दूसरे दिन विजन से एक्शन की ओर बढ़ते कदम, राज्यों-केंद्र के बीच गहन विचार-विमर्श

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

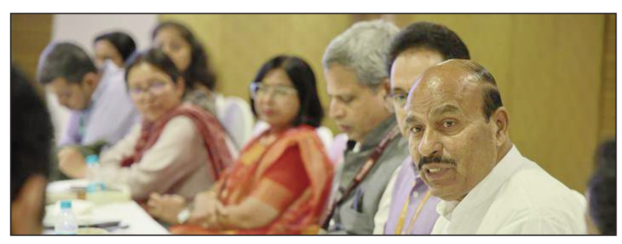

चंडीगढ़ में आयोजित तीन दिवसीय राष्ट्रीय चिंतन शिविर अंत्योदय का संकल्प, अमृत काल का प्रतिबिंब - विकसित भारत@2047 के दूसरे दिन राज्यों एवं केंद्र के बीच गहन विषयगत विचार-विमर्श के साथ विजन को क्रियान्वयन में बदलने की दिशा में ठोस प्रगति हुई। शिविर में देशभर से आए मंत्रियों एवं वरिष्ठ अधिकारियों ने सामाजिक न्याय योजनाओं की अंतिम छोर तक प्रभावी पहुंच, सामुदायिक सहभागिता तथा पब्लिक-प्राइवेट-पीपुल पार्टनरशिप मॉडल को मजबूत बनाने पर केंद्रित चर्चा की। दिवस की शुरूआत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री श्री बी. एल. वर्मा के नेतृत्व में आयोजित सामूहिक योग सत्र से हुई, जिसमें मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि तथा अन्य प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस सत्र ने दिनभर की कार्यवाही के लिए सकारात्मक और सहभागी वातावरण तैयार किया। सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देने एवं सामाजिक न्याय सेवाओं की डिलीवरी को सशक्त बनाने हेतु PPPP मॉडल विषय पर आयोजित थीमैटिक ब्रेकफास्ट सत्र में प्रतिभागियों ने चर्चा की कि किस प्रकार स्थानीय समुदाय, नागरिक समाज संगठन तथा निजी क्षेत्र मिलकर सबसे वंचित वर्गों तक सेवाएं पहुंचा सकते हैं। दूसरे दिन के सत्रों में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेन्द्र कुमार भी शामिल हुए और राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के साथ विषयगत चचाओं का अवलोकन किया। उन्होंने विकसित भारत 2047 के विजन को सामाजिक क्षेत्र में गरिमा, सुलभता और निरंतरता के तीन स्तंभों पर आधारित बताते हुए कहा कि योजनाओं का लाभ कागजों तक सीमित न रहकर जमीनी स्तर पर निर्बाध और उपयोगकर्ता-अनुकूल सेवाओं के रूप में सुनिश्चित होना चाहिए। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सचिव श्री सुधांश पंत ने बताया कि शिविर के लिए दस प्रमुख विषयों की पहचान की गई है, जिनमें सात विषय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा तीन विषय दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग से संबंधित हैं। प्रतिभागियों को पांच समूहों में विभाजित किया गया है, जो स्पष्ट कार्ययोजना, समयबद्ध क्रियान्वयन और ठोस सुझावों पर केंद्रित हैं।

युवा क्रिकेटर अदिति श्योराण का नेशनल स्कूल गेम्स टीम में चयन

सिटी दर्पण संवाददाता
सोनीपत-रोहतक-चंडीगढ़

सोनीपत के दुभेटा गांव की युवा प्रतिभाशाली क्रिकेटर अदिति श्योराण का 69वें नेशनल स्कूल गेम्स के तहत होने वाली महिला क्रिकेट चैंपियनशिप के लिए चयन हो गया है। अदिति श्योराण इस चैंपियनशिप में चंडीगढ़ की अंडर-17 महिला क्रिकेट टीम में शामिल की गई हैं। चंडीगढ़ शिक्षा विभाग की ओर से टीम की घोषणा कर दी गई है। स्टेट,नेशनल और बीसीसीआइ लेवल पर केवल 15 वर्ष की उम्र में अपने शानदार प्रदर्शन से प्रभावित करने वाली वाली अदिति श्योराण के चयन पर उनके गांव और परिवार में खुशी का माहौल है। क्रिकेटर शेफाली वर्मा की तरह धाकड़ बल्लेबाज और स्पिन गेंदबाजी करने वाली अदिति अब चंडीगढ़ क्रिकेट टीम की तरफ से 29 अप्रैल से रोहतक में होने वाली 69वींनेशनल स्कूल चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगी। अदिति के चयन पर परिवार में दादा चौधरी रघबीर सिंह श्योराण,दादी मूर्ति देवी मां अनु श्योराण,बुआ कुसुम,मोनिका और सचिन काफी खुश हैं। इस बार सीबीएसई 10वीं बोर्ड रिजल्ट में भी अदिति ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 83 प्रतिशत अंक हासिल किए हैं। दुभेटा गांव के सरंपच विकास आर्या ने भी अदिति के चयन पर बधाई देते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि गांव कि यह बेटी एक दिन देश के लिए खेलेगी। अदिति की प्रारंभिक शिक्षा गोहाना के पास खानपुर कलां स्थित ग्लोबल पब्लिक स्कूल से हुई है।

❍ रोहतक में 29 अप्रैल से शुरू होने वाली 69वें नेशनल स्कूल गेम्स अंडर 17 गर्ल्स क्रिकेट टीम में हुआ सिलेक्शन

अदिति की इस साल खेलों में रही खास उपलब्धियां

युवा क्रिकेटर अदिति श्योराण क्रिकेट में विभिन्न स्तर पर चंडीगढ़ महिला क्रिकेट टीम की अहम खिलाड़ी हैं। 2022 में चंडीगढ़ प्रशासन की क्रिकेट एकेडमी में चुने जाने के बाद इन्होंने लगातार चार साल से स्टेट,नेशनल और बीसीसीआइ प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया है। चंडीगढ़ के कार्मल कान्वेंट स्कूल-9 में 11वीं की छात्रा अदिति स्टेट और नेशनल स्तर पर क्रिकेट टीम की कप्तानी भी कर चुकी हैं। 2025-26 में अदिति ने क्रिकेट सहित दो अन्य खेलों में नेशनल लेवल पर विभिन्न प्रतियोगिताओं में चंडीगढ़ की टीमों का प्रतिनिधित्व किया है। हाल ही में दिल्ली में आयोजित नेशनल स्कूल गेम्स बेसबाल टीम में चुनी गई और फरवरी में आयोजित नेशनल स्कूल गेम्स साफ्टबाल में भी टीम की तरफ से खेलकर शानदार प्रदर्शन किया है। बीसीसीआइ की ओर से अंडर-19 महिला चैंपियनशिप में भी यूटीसीए चंडीगढ़ की टीम की तरफ से लखनऊ में आयोजित क्रिकेट टूनार्मेंट में हिस्सा लिया। खेल उपलब्धियों के लिए अदिति को हरियाणा सरकार से खेल प्रतिभा सम्मान और चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से स्टेट अवार्ड हासिल कर चुकी है। एमडीयू रोहतक और पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के प्रतिष्ठित खेल पुरस्कार भी इस खिलाड़ी को मिल चुके हैं।

विश्व पशु चिकित्सा दिवस पर निःशुल्क एंटी-रेबीज टीकाकरण एवं स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन

सिटी दर्पण संवादादता
पंचकूला

विश्व पशु चिकित्सा दिवस के अवसर पर आज पैट एनिमल मैडिकल सैंटर द्वारा एक निःशुल्क एंटी-रेबीज टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच एवं जागरूकता शिविर का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्देश्य पालतू पशुओं को घातक बीमारियों से सुरक्षित रखना तथा आमजन में पशु स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। शिविर के दौरान 100 से अधिक पालतू पशुओं का रेबीज जैसी जानलेवा बीमारी से बचाव हेतु निःशुल्क टीकाकरण किया गया। इसके अतिरिक्त, 150 से अधिक कुत्तों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया, जिसमें उनकी सामान्य स्वास्थ्य स्थिति का मूल्यांकन किया गया। इस अवसर पर पेट एनिमल मेडिकल सेंटर के इंचार्ज डॉक्टर रणजीत सिंह जादौन तथा संस्थान के पशु चिकित्सकों एवं विशेषज्ञों द्वारा लोगों को पालतू पशुओं में होने वाली प्रमुख बीमारियों जैसे रेबीज, पार्वो वायरल संक्रमण तथा उनके प्रबंधन के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही, पशुओं की नियमित देखभाल, टीकाकरण और स्वच्छता के महत्व पर भी जोर दिया गया, जिससे उन्हें विभिन्न बीमारियों से सुरक्षित रखा जा सके।

रूमेटोलॉजिकल रोग जागरूकता माहः चिकित्सा विशेषज्ञों ने शीघ्र निदान पर दिया जोर, भ्रांतियों को दूर करने और देश में बढ़ते बोझ को रेखांकित किया

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

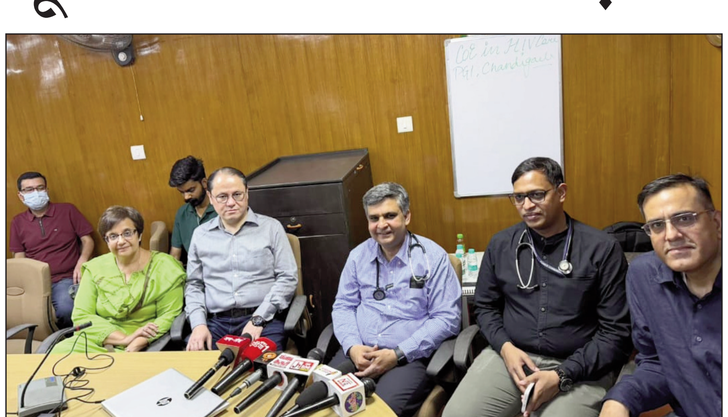

मेटोलॉजिकल रोग जागरूकता माह के अवसर पर, पीजीआईएमईआर के आंतरिक चिकित्सा विभाग के क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी एवं रूमेटोलॉजी प्रभाग के विशेषज्ञों ने मीडिया को संबोधित करते हुए रूमेटोलॉजिकल रोगों को भारत में एक प्रमुख किंतु उपेक्षित जनस्वास्थ्य चुनौती के रूप में पहचानने की आवश्यकता पर बल दिया। इस अवसर पर पीजीआईएमईआर की रूमेटोलॉजी देखभाल और शिक्षा में अग्रणी भूमिका को रेखांकित करते हुए बताया गया कि वर्ष 1971 में भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के अस्पताल में देश का पहला समर्पित रूमेटोलॉजी केंद्र स्थापित किया गया, जो विशेष रोगी देखभाल और अनुसंधान में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ।

इस अवसर पर बोलते हुए, प्रो. अमन शर्मा, अध्यक्ष, इंडियन रूमेटोलॉजी एसोसिएशन ने बताया कि रूमेटिक एवं मस्कुलोस्केलेटल रोग भारत की लगभग 25-30% आबादी को प्रभावित करते हैं, और ये देश में विकलांगता के शीर्ष 25 कारणों में शामिल हैं। आंकड़ों के अनुसार, लगभग पाँच में से एक मरीज को गंभीर विकलांगता का सामना करना पड़ता है, जिससे उनकी कार्यक्षमता और आत्मनिर्भरता प्रभावित होती है। चिंताजनक रूप से, 25-49 वर्ष आयु वर्ग—जो आर्थिक रूप से सबसे अधिक उत्पादक है—में विकलांगता का सबसे अधिक बोझ देखा जाता है, जिससे सामाजिक-आर्थिक प्रभाव भी व्यापक रूप से पड़ता है। सामान्य भ्रांतियों का खंडन करते हुए, विशेषज्ञों ने बताया कि आर्थराइटिस कोई एक रोग नहीं बल्कि 100 से अधिक विभिन्न स्थितियों का समूह है, जिसमें रूमेटाइड आर्थराइटिस, ल्यूपस, वैस्कुलाइटिस, स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस और कनेक्टिव टिश्यू रोग शामिल हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये रोग केवल बुजुर्गों तक सीमित नहीं हैं, न ही हर जोड़ दर्द यूरिक एसिड के कारण होता है, और सभी मामलों में आजीवन उपचार आवश्यक नहीं होता।

कमर दर्द, सॉफ्ट टिश्यू रूमेटिज्म और फाइब्रोमायल्जिया जैसी स्थितियाँ ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में व्यापक रूप से पाई जाती हैं। अध्ययनों के अनुसार, लगभग 37% रूमेटाइड आर्थराइटिस मरीजों में गंभीर कार्यात्मक अक्षमता देखी जाती है, जबकि लगभग 22% मरीजों की कार्य क्षमता प्रभावित होती है। विशेषज्ञों ने भारत में प्रशिक्षित रूमेटोलॉजिस्ट की भारी कमी को एक बड़ी चुनौती बताया। उन्होंने कहा कि चिकित्सा शिक्षा के स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर रूमेटोलॉजी का पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं दिया जाता। यह कमी विशेष रूप से प्रशिक्षित नर्सों, फिजियोथेरेपिस्ट और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जैसे सहयोगी स्वास्थ्य कर्मियों में भी देखी जाती है।

चिकित्सा विशेषज्ञों ने निम्नलिखित सुझाव दिएः सामुदायिक आधारित स्वास्थ्य कार्यक्रमों का विकास, रूमेटोलॉजी प्रशिक्षण में निवेश बढ़ाना और बहु-विषयक (मल्टीडिसिप्लिनरी) देखभाल मॉडल को सुदृढ़ करना।

उन्होंने कहा, शीघ्र निदान और समय पर उपचार से विकलांगता को काफी हद तक कम किया जा सकता है और जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सकता है। जन-जागरूकता, क्षमता निर्माण और नीतिगत प्राथमिकता इस बढ़ते बोझ से निपटने के लिए अत्यंत आवश्यक हैं।

प्रेस कॉन्फ्रेंस का समापन 26 अप्रैल को पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ से सुखना झील तक आयोजित जागरूकता वॉक में भाग लेने के आमंत्रण के साथ हुआ, तथा आम जनता और स्वास्थ्य हितधारकों से अपील की गई कि वे शुरूआती लक्षणों को पहचानें, स्वयं दवा लेने से बचें और विशेषज्ञ चिकित्सक से परामर्श लें। सही दृष्टिकोण अपनाने पर कई रूमेटोलॉजिकल रोगों का प्रभावी प्रबंधन संभव है, जिससे मरीज सक्रिय और उत्पादक जीवन जी सकते हैं।

संक्षिप्त-समाचार

चंडीगढ़ में आयोजित चिंतन शिविर में स्माइल-बेगरी सर्वे मोबाइल एप्लिकेशन का शुभारंभ

चंडीगढ़। भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 24 से 26 अप्रैल 2026 तक चंडीगढ़ में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ आयोजित चिंतन शिविर के दौरान स्माइल-बेगरी सर्वे मोबाइल एप्लिकेशन का शुभारंभ किया। यह मोबाइल एप्लिकेशन स्माइल-भिक्षावृत्ति उप-योजना (भिक्षावृत्ति में संलग्न व्यक्तियों का व्यापक पुनर्वास) के अंतर्गत विकसित की गई है। इसका उद्देश्य वास्तविक समय डेटा संग्रह और बेहतर निगरानी के माध्यम से जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन को मजबूत करना है। यह एप्लिकेशन कार्यान्वयन एजेंसियों और जिला अधिकारियों को सर्वेक्षण डेटा को डिजिटल रूप से एकत्रित करने में सक्षम बनाएगा, जिससे सटीकता, पारदर्शिता और समय पर रिपोर्टिंग सुनिश्चित होगी। मोबाइल एप्लिकेशन का शुभारंभ देर से और अनियमित डेटा रिपोर्टिंग जैसी चुनौतियों से निपटने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है, साथ ही यह शहरों में वास्तविक समय की निगरानी, डेटा विश्लेषण और प्रदर्शन ट्रैकिंग के लिए मंत्रालय की क्षमता को भी बढ़ाती है। इस अवसर पर बोलते हुए, यह बताया गया कि यह पहल सरकार के ₹भिक्षावृत्ति मुक्त भारत₹ के लक्ष्य के अनुरूप है। यह मोबाइल एप्लिकेशन योजना के समग्र निगरानी ढांचे को और मजबूत करेगी। मंत्रालय ने चिन्हित व्यक्तियों को समाज की मुख्यधारा में पुनः शामिल करने और उन्हें गरिमा और आत्मविश्वास के साथ जीवन जीने में सक्षम बनाने के लिए प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों का लाभ उठाने और संस्थागत तंत्रों को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

चिंतन शिविर में भिखारियों/आश्रय गृहों की देखभाल, पुनर्वास और प्रबंधन संबंधी दिशा-निर्देशों का अनावरण किया गया

चंडीगढ़। भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 24 से 26 अप्रैल, 2026 तक चंडीगढ़ में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ आयोजित चिंतन शिविर के दौरान भिखारियों/आश्रय गृहों की देखभाल, पुनर्वास और प्रबंधन पर आदर्श दिशानिर्देशों का अनावरण किया। इन दिशानिर्देशों में निवारक स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता, अवसंरचना और क्षमता, पोषण और खाद्य सुरक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और पुनर्वास, कानूनी सहायता और जागरूकता, बाल और लैंगिक संवेदनशीलता, और जवाबदेही एवं निगरानी जैसे प्रमुख क्षेत्रों को शामिल करते हुए एक व्यापक ढांचा प्रदान किया गया है। ये दिशानिर्देश विभिन्न केंद्रीय और राज्य सरकारी योजनाओं के साथ समन्वय पर भी जोर देते हैं ताकि उपरोक्त निदेशों का सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में समान रूप से कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके। मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आग्रह किया कि वे देश भर में भिखारियों/आश्रय गृहों में मानवीय और गरिमापूर्ण जीवन को सुनिश्चित करने के लिए इन दिशानिर्देशों को अक्षरशः लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं।

पेक में विद्यार्थियों के लिए परीक्षा तनाव प्रबंधन विषय पर वर्कशॉप का हुआ आयोजन

चंडीगढ़। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज (डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी), चंडीगढ़ के स्टूडेंट काउंसलिंग सेल ने परिसर में कॉलेज विद्यार्थियों के लिए परीक्षा तनाव प्रबंधन विषय पर एक वर्कशॉप का सफलतापूर्वक आयोजन किया। इस सत्र का उद्देश्य विद्यार्थियों को शैक्षणिक दबाव से निपटने और परीक्षा के दौरान मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने के व्यावहारिक उपायों से सुसज्जित करना था। यह कार्यक्रम डॉ. डी.आर. प्रजापति (डीन छात्र कल्याण) के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। वर्कशॉप का संचालन सुश्री दीप्ति कपिला द्वारा किया गया, जिन्होंने तनाव और चिंता को कम करने के प्रभावी उपाय साझा किए। इंटरैक्टिव गतिविधियों और विचारोत्तेजक चचार्ओं के माध्यम से उन्होंने विद्यार्थियों को रिलैक्सेशन तकनीक, समय प्रबंधन और सकारात्मक सोच जैसे उपायों के बारे में मार्गदर्शन दिया। वर्कशॉप का समन्वय डॉ. सुलता भंडारी (प्रोफेसर इंचार्ज, स्टूडेंट काउंसलिंग सेल), श्री नवीन कुमार (स्टूडेंट काउंसलर) और सुश्री तन्वी शर्मा (स्टूडेंट काउंसलर) द्वारा किया गया। उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य के महत्व पर जोर देते हुए विद्यार्थियों को आवश्यकता पड़ने पर सहायता लेने के लिए प्रेरित किया। इस वर्कशॉप में विद्यार्थियों की उत्साहपूर्ण भागीदारी देखने को मिली, जिन्होंने सत्र को अत्यंत लाभकारी और रोचक पाया। यह पहल पेक द्वारा अपने विद्यार्थियों के लिए सहयोगात्मक और स्वस्थ शैक्षणिक वातावरण विकसित करने की निरंतर प्रतिबद्धता को दशार्ती है।

पंचकूला की मंडियों में अब तक 33557 मीट्रिक टन गेंहू की खरीद तथा 18610 मीट्रिक टन गेंहू का हुआ उठान

पंचकूला। जिला में रबी सीजन 2026-27 के दौरान गेंहू की खरीद एवं उठान का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। सरकारी खरीद एजेंसियों द्वारा जिला की मंडियों में से अब तक 33557 मीट्रिक टन गेंहू की खरीद की गई और 18610 मीट्रिक टन गेंहू का उठान किया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक कार्यालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि सरकारी खरीद एजेंसियों हैफेड और हरियाणा वेयर हाउसिंग कारपोरेशन द्वारा रायपुररानी, बरवाला और पंचकूला स्थित अनाज मंडियों में गेहूं की खरीद की जा रही है। उन्होंने बताया कि रायपुररानी अनाज मंडी से हैफेड द्वारा 4368 मीट्रिक टन गेंहू और हरियाणा वेयर हाउसिंग कोरपोरेशन द्वारा 11661 मीट्रिक टन गेंहू की खरीद की गई। इसी प्रकार बरवाला अनाज मंडी से हैफेड द्वारा 7743 मीट्रिक टन गेंहू और हरियाणा वेयर हाउसिंग कारपोशन द्वारा 8385 मीट्रिक टन गेंहू की खरीद की गई। इसके अलावा पंचकूला अनाज मंडी से हैफेड द्वारा 1400 मीट्रिक टन गेंहू की खरीद की गई। उन्होने बताया कि मंडियों में खरीद के साथ साथ उठान का कार्य भी सुचारू रूप से चल रहा है। रायपुररानी अनाज मंडी से हैफेड द्वारा 2047 मीट्रिक टन गेंहू और हरियाणा वेयर हाउसिंग कोरपोरेशन द्वारा 5263 मीट्रिक टन गेंहू का उठान किया गया। इसी प्रकार बरवाला अनाज मंडी से हैफेड द्वारा 5669 मीट्रिक टन गेंहू और हरियाणा वेयर हाउसिंग कारपोशन द्वारा 5206 मीट्रिक टन गेंहू का उठान किया गया। पंचकूला अनाज मंडी से हैफेड द्वारा 425 मीट्रिक टन गेंहू का उठान किया गया।

पंचकूला नगर निगम आम चुनाव के लिए जनसभा/रैली और होर्डिंग/विज्ञापन बोर्ड लगाने के लिए स्थान निर्धारित

पंचकूला। पंचकूला नगर निगम आम चुनाव 2026 के अंतर्गत उम्मीदवारों द्वारा जनसभा/रैली/ नुक्कड़ सभा का स्थान और होर्डिंग/बैनर और विज्ञापन बोर्ड लगाने के स्थान निर्धारित किए गए है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त श्री सतपाल शर्मा ने बताया कि जनसभा/रैली/नुक्कड़ सभा के लिए निर्धारित स्थानों में एमडीसी सेक्टर-2, ओपन प्लॉट, सूरज थियेटर सेक्टर-1, मार्केट सेक्टर-7, आउटर मार्केट सेक्टर-10, आयरन मार्केट सेक्टर-15, मार्केट सेक्टर-17, लेबर चैक सेक्टर-17 (नोर्थ साइड), लेबर चैक सेक्टर-17 (साउथ साइड), औद्योगिक क्षेत्र फेस-2 मार्केट, अभयपुर पार्क सेक्टर-14 साप्ताहिक सब्जी मंडी, मार्केट सेक्टर-12, 12ए, सेक्टर-5 शालीमार ग्राउंड, सेक्टर-3 ताउ देवीलाल के बैक साइड, सेक्टर-20 अनाजमंडी मार्केट, आशियाना फ्लैट, सेक्टर-20 पार्ट-2, बीड घग्गर, खडग मंगोली अपर मार्केट, सेक्टर-24-25 मार्केट और सेक्टर-31-32 के साथ लगते नाडा गांव के बैक साइड, सेक्टर-26, 27 और 28, शीतला माता मंदिर के पास गांव रामगढ़ (पौंड), बीला नजदीक राजकीय स्कूल, गांव कोट, मटटावाला, खगेसरा, टोका, सुखदर्शनपुर, खटौली, नग्गल, जलौली और अलीपुर शामिल है। उन्होंनें बताया कि इसी प्रकार चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के लिए विज्ञापन बोर्ड/पोस्टर लगाने के जो स्थान निर्धारित किए गए है उनमें एमडीसी सेक्टर-2, ओपन प्लॉट, मार्केट सूरज थियेटर सेक्टर-1, सेक्टर-2, 6, एमडीसी-5 मार्केट, मार्केट सेक्टर-7, आउटर मार्केट सेक्टर-9, 10, सेक्टर-15 आयरन मार्केट, मार्केट सेक्टर-16, 17, लेबर चैक सेक्टर-17 (नोर्थ साइड), लेबर चैक सेक्टर-17 (साउथ साइड), मार्केट औद्योगिक क्षेत्र फेस-2, अभयपुर पार्क साप्ताहिक सब्जी मंडी सेक्टर-14, मार्केट सेक्टर-12, 12ए, सेक्टर-4, 5, 11 मार्केट और गांव हरिपुर, मार्केट सेक्टर-4, देवी नगर, सेक्टर-3 और सेक्टर-21, मार्केट गांव महेशपुर, सेक्टर-20, मार्केट सेक्टर-20 पार्ट-2 और गांव कुडी, मार्केट बीड घग्गर, चंडी मंदिर/चंडी कोटला मार्केट, खडग मंगौली अप्पर, मार्केट खडग मंगौली लोअर, नाडा साहिब, सेक्टर-23, 24, 25, 30, 31, मोंगीनंद, मार्केट सेक्टर-26, 27, 28, किशनपुरा और ट्रिब्यून मित्र विहार, मार्केट रामगढ़, बिल्ला, भानू, मान्क्या, जसवंतगढ़, डबकोरी, विलेज मार्केट कोट, मटटावाला, खंगेसरा, टोका, सुखदर्शनपुर, खटौली, नग्गल, जलौली और अलीपुर शामिल है।

पंचकूला नगर निगम आम चुनाव 2026 के अंतर्गत सामान्य पर्यवेक्षक व पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त

पंचकूला। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त श्री सतपाल शर्मा ने बताया कि हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचकूला नगर निगम आम चुनाव-2026 के अंतर्गत सामान्य पर्यवेक्षक व पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए है। उन्होंने बताया कि आईएएस अधिकारी श्री डी सुरेश (7696288340) को सामान्य पर्यवेक्षक और आईपीएस अधिकारी श्री सुरेंद्र पाल सिंह (7696843374) को पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। सामान्य ऑब्जर्वर का कैंप कार्यालय पीडब्लूडी रेस्ट हाउस सेक्टर-1 में कमरा नंबर 9 ग्राउंड फ्लोर में बनाया गया है और पुलिस पर्यवेक्षक का कैंप कार्यालय कमरा नंबर 8 ग्राउंड फ्लोर में स्थापित किया गया है।